रांची एवं डालटनगंज (मेदिनीनगर) से एक साथ प्रकाशित
₹3.00 रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155 www.rastriyanaveenmail.com
ईश्वर में हमारा विश्वास
राष्ट्रीय नवीन मेल
सत्यमेव जयते
बजट 2024
श्रावण कृष्ण पक्ष 03, संवत 2081 | रांची, बुधवार, 24 जुलाई 2024, वर्ष-25, अंक- 172, पृष्ठ-12

15 हजार रुपये तक ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को सीधा हस्तांतरण

2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय व्यय से 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज **-निर्मला सीतारमण**, वित्त मंत्री

बजट 2024

48,20,512 करोड़ रुपये केंद्रीय बजट में कुल व्यय अनुमानित है

1.36 लाख डाकघर देश के दूरदराज के इलाकों तक बैंकिंग को सुलभ बना रहे

14.01 लाख करोड़ रुपये का सकल बाजार उधारी चालू वित्तीय वर्ष में अनुमानित

11,11,111 करोड़ रु. कुल पूंजीगत व्यय का प्रस्ताव किया गया है

32.07 लाख करोड़ कुल प्राप्ति व शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ अनुमानित

01 करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और भत्ता

25 हजार गांवों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी

सकल घरेलू उत्पाद के **4.9 फीसदी** तक रह सकता है राजकोषीय घाटा

डिजिटल इंडिया पर जोर, किसान से श्रमिक तक होंगे ऑनलाइन, रोजगार सृजन पर फोकस

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला केंद्रीय बजट 2024-25 लोकसभा में पेश किया। सफेद साड़ी पहने खास लुक में निर्मला सीतारमण ने लगातार 7 वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी बनाया। राजग के चुनाव प्रचार के दौरान किए गए वादों के अनुसार बजट में ढेरों सुधार व बदलाव देखने को मिले। सरकार ने डिजिटल इंडिया को और मजबूत करते हुए इसके तहत कई काम करने का फैसला किया है। कहा गया कि किसान से लेकर श्रमिकों तक को ऑनलाइन पोर्टल्स से कनेक्ट किया जाएगा। एक करोड़ युवाओं को टॉप-500 कंपनियों में 12 महीने इंटर्नशिप और हर महीने भत्ता देने की भी बात कही गई है। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में कुल व्यय 48,20,512 करोड़ रुपये अनुमानित है। इसमें से कुल पूंजीगत व्यय 11,11,111 करोड़ है। वर्ष 2023-24 की तुलना में इस वर्ष का पूंजीगत व्यय में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दिखाई गई है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल प्राप्तियां 32.07 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। शुद्ध कर प्राप्तियां 25.83 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं।

सकल बाजार उधारी 14.01 लाख करोड़ रुपये अनुमानित हैं। वित्त मंत्री ने एक घंटा 23 मिनट के बजट भाषण में वेतनभोगी वर्ग को थोड़ा राहत देने का ऐलान किया। नई कर व्यवस्था चुनने वाले करदाताओं के लिए अब 7.75 लाख रुपये तक की इनकम कर मुक्त हो गई है। वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट में बिहार के लिए 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा है। वहीं, आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान किया है।

केंद्रीय बजट 2024-25 में बिहार के लिए 60 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं, आंध्र प्रदेश को 15 हजार करोड़ रुपये की मदद का ऐलान

1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा

- रक्षा मंत्रालय — ₹6.2 लाख करोड़
- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय — ₹2.78 लाख करोड़
- रेल मंत्रालय — ₹2.55 लाख करोड़
- उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय — ₹2.13 लाख करोड़
- गृह मंत्रालय — ₹2.03 लाख करोड़
- ग्रामीण विकास मंत्रालय — ₹1.77 लाख करोड़
- रसायन और उर्वरक मंत्रालय — ₹1.68 लाख करोड़
- संचार मंत्रालय — ₹1.37 लाख करोड़
- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय — ₹1.27 लाख करोड़

वित्त मंत्री ने कहा, निकट भविष्य में मिडिल क्लास के लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं बनाएगी

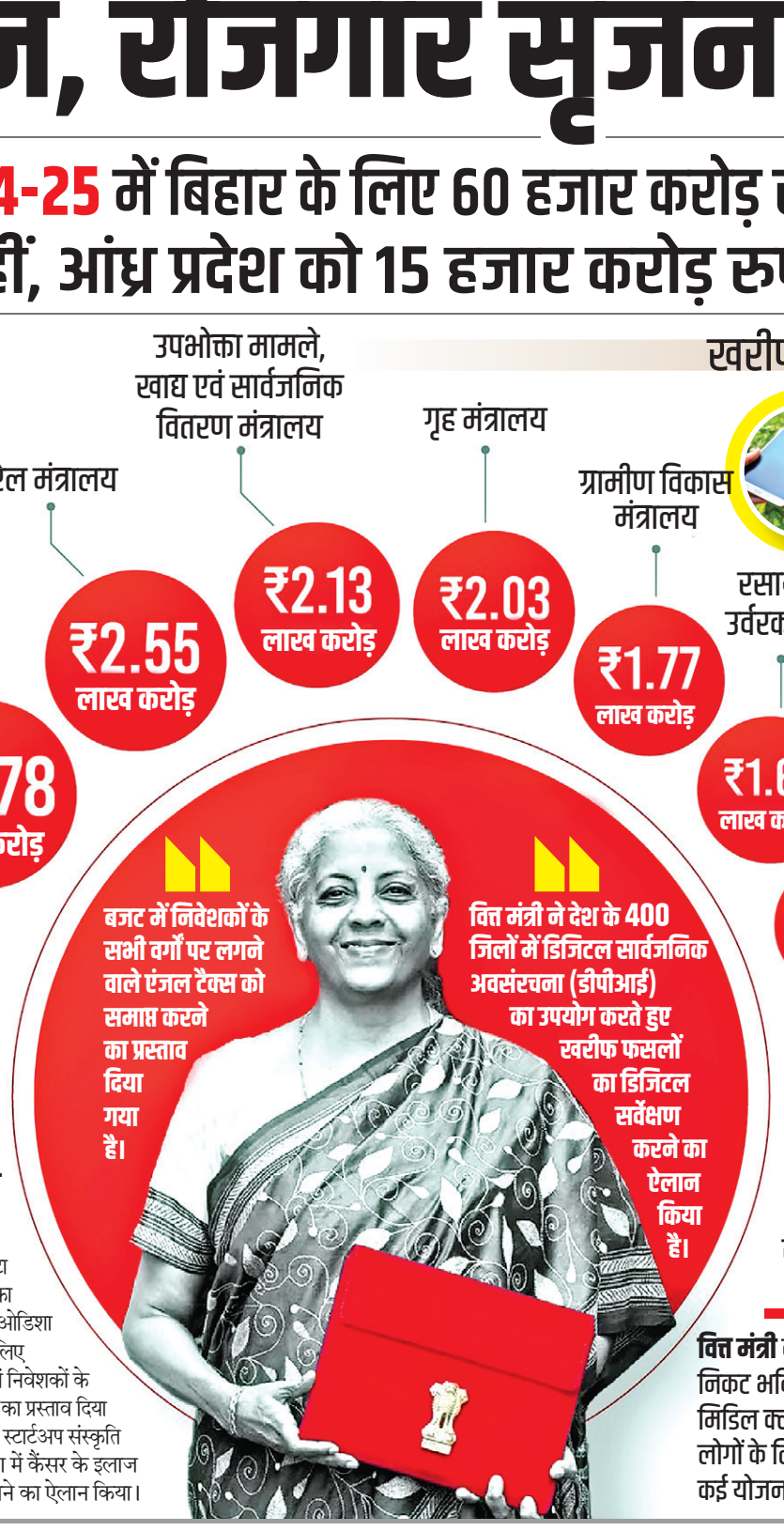

स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 4.9 फीसदी रहने का अनुमान है। बजट में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पेशल योजना लाने का वादा भी किया गया है। बजट में निवेशकों के सभी वर्गों पर लगने वाले एंजल टैक्स को समाप्त करने का प्रस्ताव दिया गया है। इससे देश के स्टार्टअप को फायदा मिलेगा और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कैंसर के इलाज की तीन दवाओं को मूल सीमा शुल्क से छूट दिए जाने का ऐलान किया।

खरीफ फसलों का होगा डिजिटल सर्वेक्षण

वित्त मंत्री ने देश के 400 जिलों में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का उपयोग करते हुए खरीफ फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पांच राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही झींगा, मछली, ब्रूडस्टॉक के लिए केंद्रीयकृत प्रजनन केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करने हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध करने का भी ऐलान किया है। वहीं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार सृजन में तेजी लाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सहयोग नीति तैयार करने की घोषणा की। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में नौ प्राथमिकताएं निर्धारित की हैं। इसमें खेती में उत्पादकता, रोजगार और क्षमता विकास, समग्र मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अधोसंरचना, नवाचार, शोध और विकास, अगली पीढ़ी के सुधार सहित अन्य कारकों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है।

मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए खोला खजाने का पिटारा

नई दिल्ली। बजट में मिडिल क्लास लोगों को आर्थिक मोर्चे पर समृद्ध करने की दिशा में कई कदम उठाए गए हैं। इससे पहले फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट में मिडिल क्लास लोगों के लिए आवास योजना भी शुरू करने की बात कही गई थी। इसके अलावा, मिडिल क्लास के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए रूफ टॉप सोलर एनर्जी का भी ऐलान किया था। वित्त मंत्री ने कहा, निकट भविष्य में मिडिल क्लास के लोगों के लिए सरकार कई योजनाएं बनाएगी। किराए के मकान में रहने वाले लोगों को अपना घर उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर आर्थिक सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। वित्त मंत्री ने अपनी पहली घोषणा के बारे में बताते हुए कहा, सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए कर्मचारियों को एकमुश्त वेतन - ईपीएफओ में पंजीकृत लोगों को 15 हजार रुपये तक का सीधा हस्तांतरण।

युवा रोजगार पर विशेष योजना

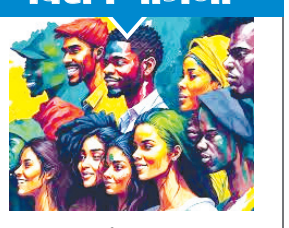

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शहरों में औद्योगिक पार्क भी बनाने का ऐलान किया है। उनहोंने एक करोड़ से भी अधिक युवाओं को प्रशिक्षण देने की घोषणा की है। युवाओं के लिए रोजगार के नए-नए अवसर सृजित करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। मध्यमवर्गीय परिवारों को एजुकेशन प्राप्त करने में हो रही दिक्कतों को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन लोन की सुविधा विकसित की है। वित्त मंत्री ने कहा कि उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले मध्यमवर्गीय परिवार से जुड़े युवाओं को 10 लाख रुपए लोन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। जिन लोगों ने पहले ऋण लिया है और उसका भुगतान कर दिया है, उनके लिए मुद्रा ऋण की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए की जाएगी।

आज | कल

देश के हर वर्ग को समृद्ध करने वाला बजट : प्रधानमंत्री मोदी

एजेंसी

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए

बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा है कि यह हर वर्ग के लोगों को समृद्धि की राह पर ले जाने वाला बजट है। उन्होंने कहा, यह हमारे देश को प्रगति की अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाएगा। पीएम ने सीतारमण और उनकी टीम की प्रशंसा करते हुए कहा, यह दूरदर्शी बजट हमारे समाज के हर वर्ग का उत्थान और सशक्तिकरण करेगा, जिससे सभी के लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। पीएम मोदी ने कहा, इस बजट में एमएसएमई सेक्टर के लिए क्रेडिट देने की सुविधा बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणाएं की गई हैं। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। प्रधानमंत्री ने कहा, चाहे स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1,000 करोड़ रुपये का फंड हो, या फिर एंजेल टैक्स हटाने का फैसला हो,

शेष पेज 11 पर

न्यू टैक्स रिजीम में 7.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री

नई दिल्ली। सरकार ने नई टैक्स रिजीम में पर्सनल इनकम टैक्स की दरों में कटौती की है। अब, नई टैक्स रिजीम के तहत 7.75 लाख रुपये आमदनी वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। सरकार ने नया टैक्स स्लैब पेश किया है।

न्यू टैक्स रिजीम : न्यू टैक्स रिजीम में नौकरीपेशा लोगों की 7.75 लाख तक की आय टैक्स-फ्री हो सकती है। अगर आपकी सैलरी से आय 7.75 लाख रुपये है तो 75 हजार रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन का घटा दें तो सात लाख बनता है। इनमें से तीन लाख रुपये पर कोई टैक्स नहीं देना है। बाकी के चार लाख पर पांच फीसदी, यानि 20 हजार रुपये टैक्स बनेगा। न्यू टैक्स रिजीम में इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87(ए) के तहत 20 हजार रुपये की माफी मिल जाती है। इस तरह 7.75 लाख की आय पर जीरो टैक्स बन जाएगा।

नई कर प्रणाली में बदलाव ₹17,500 तक की होगी बचत

नई कर प्रणाली

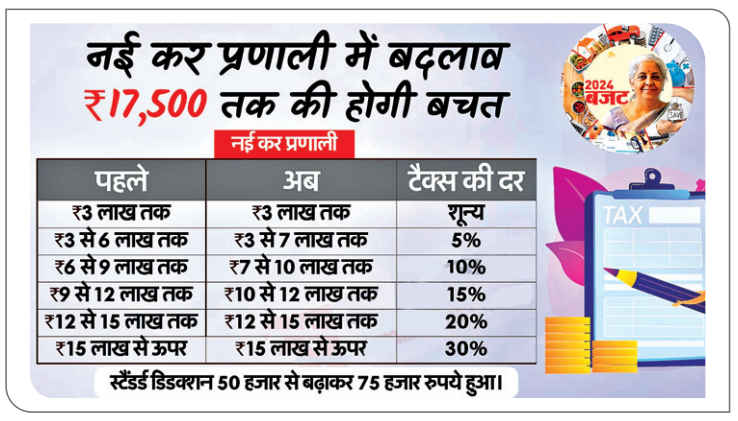

पहले	अब	टैक्स की दर
₹3 लाख तक	₹3 लाख तक	शून्य
₹3 से 6 लाख तक	₹3 से 7 लाख तक	5%
₹6 से 9 लाख तक	₹7 से 10 लाख तक	10%
₹9 से 12 लाख तक	₹10 से 12 लाख तक	15%
₹12 से 15 लाख तक	₹12 से 15 लाख तक	20%
₹15 लाख से ऊपर	₹15 लाख से ऊपर	30%

स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार रुपये हुआ।

ओल्ड टैक्स रिजीम : ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट के विकल्प ज्यादा हैं, पर स्लैब चार ही हैं। इसमें ढाई लाख तक की इनकम ही टैक्स फ्री है। इनकम टैक्स एक्ट की धारा 87ए का फायदा लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम में 5.50 लाख रुपये तक की इनकम ही टैक्स फ्री हो सकती है, क्योंकि इसमें इस सेक्शन के तहत 12500 रुपये ही माफ होते हैं।

इंडिया

कोऊ नृप होई हम हीं का हानि, चेरी छांड़ि के होइब न रानी

सुनील बादल

हर साल की तरह इस बार का भी बजट संसद के विचारार्थ प्रस्तुत किया गया जिसका शोर देश के साथ विदेशों में भी है पर रोज कमाने खाने वाले बहुत से आम लोग इससे या तो अनजान हैं या उदासीन हैं । उन्हें लगता है कि इस पूरी प्रक्रिया में उनकी भूमिका एक दर्शक जैसी है बजट में किसी वस्तु में टैक्स घटाने पर क्या उसकी बढ़ी हुई कीमत क्या सचमुच घटेगी ? इसी प्रकार बहुत से लोगों का यह मानना है कि बजट के प्रावधान राजनीतिक कारणों से या बड़े व्यावसायिक घरानों के प्रभाव से किए जाते हैं । इस धारणा को दूर करने के लिए केंद्र और झारखंड की पूर्ववर्ती और वर्तमान सरकारों ने आम लोगों की राय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैंप लगाकर लोगों से विमर्श भी किया था पर लोगों के मन में बैठा हुआ है -"कोऊ नृप होई हम हीं का हानि, चेरी छांड़ि कि होइब न रानी।" इस उदासीनता के पीछे आजादी के इतने वर्षों बाद भी सरकारों और समाज के अंतिम व्यक्ति के बीच संवाद या विश्वास की कमी है । लोग अभी भी भ्रष्ट सरकारी तंत्र से त्रस्त हैं जबकि केंद्र और राज्य सरकारों के स्तर से ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर रोक के अनेक प्रयास किए गए हैं । झारखंड में लगातार भ्रष्ट अधिकारी तक पकड़े जा रहे हैं पर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी जमीं हैं कि उसने इसे सिस्टम का हिस्सा बना लिया है । इसीलिए इस बार के बजट में भी लाखों करोड़ों के प्रावधान से उनके लाभुकों से ज्यादा वे बिचौलिए और

भ्रष्ट अधिकारी खुश हो रहे होंगे जो ऐसी अनेक योजनाओं का लाभ लेने में आम आदमी देर कर परेशान करते हैं ताकि उन्हें रिश्वत दी जा सके । इस पर रोक के लिए आवेदनों के समयबद्ध निष्पादन को अनिवार्य किया जाना चाहिए और मॉनिटरिंग प्रणाली को मजबूत करना चाहिए अन्यथा वह गरीब असहाय आदमी लाल कार्ड बनवाने से लेकर हर छोटे बड़े लाभ के लिए इन बिचौलियों और प्रखंड स्तर के भ्रष्ट अधिकारियों के पीछे दौड़ता रहेगा । अभी स्थिति यह है कि किसी भी प्रखंड या जिले में कौन अधिकारी या कर्मचारी कब आएंगे या नहीं इसकी कोई पूर्व सूचना नहीं होती मंगल और शुक्रवार को भी प्रखंड दिवस पर यदि अधिकारी उपस्थित रहते भी हैं तो मीटिंग में बैठ जाते हैं जबकि दूसरी ओर बिचौलिया हिस्से की बता तय होते ही धड़ल्ले से सभी कर्मचारियों से काम करा देता है । इस भाग दौड़ में कोई गांव या शहर का दैनिक मजदूर या किसान कितने दिन टिक पाएगा तब उसे मजबूरी में बिचौलियों के पास जाना पड़ता है। सरकार को चाहिए इस भ्रष्ट तंत्र को विफल करने के लिए सभी सरकारी कर्मचारियों को पहचान पत्र अपने ड्रेस के सामने लगाना अनिवार्य किया जाए और शिकायत करने के लिए उच्चाधिकारियों के कार्यालय में रिकॉर्ड सहित शिकायत निवारण सेल बनाया जाए । अभी कहीं भी बायोमेट्रिक हजरिम व्यवस्था नहीं है जिस कारण कर्मचारियों और अधिकारियों की मनमानी बढ़ गई है । उच्च प्रशासनिक पदों से सेवानिवृत और वरिष्ठ नेता तक इसे राजनीतिक मजबूरी मानते हैं क्योंकि राजनीति में जड़ें जमाने के लिए ब्रांड की तरह अपने को स्थापित करने के लिए भारी भरकम राशि की जरूरत पड़ रही है और ईमानदार और सक्षम यदि राजनीति में आना भी चाहे तो अपने को प्रचारित करने से लेकर बूथ प्रबंधन तक में असफल हो जाता है क्योंकि जनता उसे प्रभावशाली नहीं मानती क्योंकि काम करने के लिए बौद्धिक और ईमानदार प्रयास से ज्यादा दबंगता चलती है । शातिर राजनेता जनता को भी जाति,धर्म जैसे भेदभाव और वर्गों में बांट कर रखते हैं ताकि उनके मुकाबले कोई खड़ा न हो सके ।

मुख्यमंत्री ने कहा

राज्य के विकास में नवनियुक्त अभ्यर्थियों की भूमिका अहम

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज फिर सकारात्मक

ऊर्जा एवं उत्साह के साथ राज्य के विकास को गति देने के उद्देश्य से विभिन्न विभागों में चयनित 183 नवनियुक्त अभ्यर्थियों को राज्य सरकार नियुक्ति पत्र दे रही है। उन्होंने कहा कि कुछ नियुक्तियां झारखंड लोक सेवा आयोग एवं कुछ नियुक्तियां झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की गई हैं।सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार ने विभिन्न पदों पर पहले भी नियुक्ति पत्र प्रदान किया है और जो छूटे हुए अभ्यर्थी थे उन्हें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सर्वांगीण विकास में एक महत्वपूर्ण कड़ी बनेंगे। साथ ही राज्य को देश के अग्रणी राज्यों के समकक्ष पहुंचाने का प्रयास आप सभी प्रतिबद्ध होकर करेंगे। मुख्यमंत्री मंगलवार को झारखंड मंत्रालय स्थित सभागार में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में चयनित असिस्टेंट टाउन प्लानर,

शेष पेज 11 पर

खेती में उत्पादकता, रोजगार, क्षमता विकास और विनिर्माण पर जोर

केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताई विकसित भारत की नौ प्राथमिकताएं

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी 3.0 सरकार का पहला बजट पेश किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत के लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में अपना विश्वास जताया है और उनके नेतृत्व में ऐतिहासिक तीसरे कार्यकाल के लिए इसे फिर से चुना है। हम अपनी नीतियों में उनके समर्थन, विश्वास और भरोसे के लिए आभारी हैं। बजट भाषण के दौरान लोकसभा में वित्त मंत्री सीतारमण ने विकसित भारत के लिए मोदी सरकार की 9 प्राथमिकताएं भी बताईं। जिनमें कृषि क्षेत्र में उत्पादकता और लचीलापन, रोजगार एवं कौशल, समावेशी मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक न्याय, विनिर्माण एवं सेवाएं, शहरी विकास , ऊर्जा संरक्षण, अवसंरचना, नवाचार अनुसंधान एवं विकास, नई पीढ़ी के सुधार शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जैसा कि अंतरिम बजट में उल्लेख किया गया है, हमें 4 अलग-अलग जातियों, गरीब, महिला, युवा और किसान पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। किसानों के लिए, हमने सभी प्रमुख फसलों के लिए उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है, जो लागत से कम से कम 50% मार्जिन के वादे को पूरा करता है।

इससे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। राष्ट्रपति कार्यालय ने एक्स पर इस मुलाकात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी और वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्रीय बजट पेश करने से पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने वित्त मंत्री को शुभकामनाएं दी। ज्ञात हो कि संसद का बजट सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस दूसरे संसद सत्र के 12 अगस्त तक चलने की संभावना है।

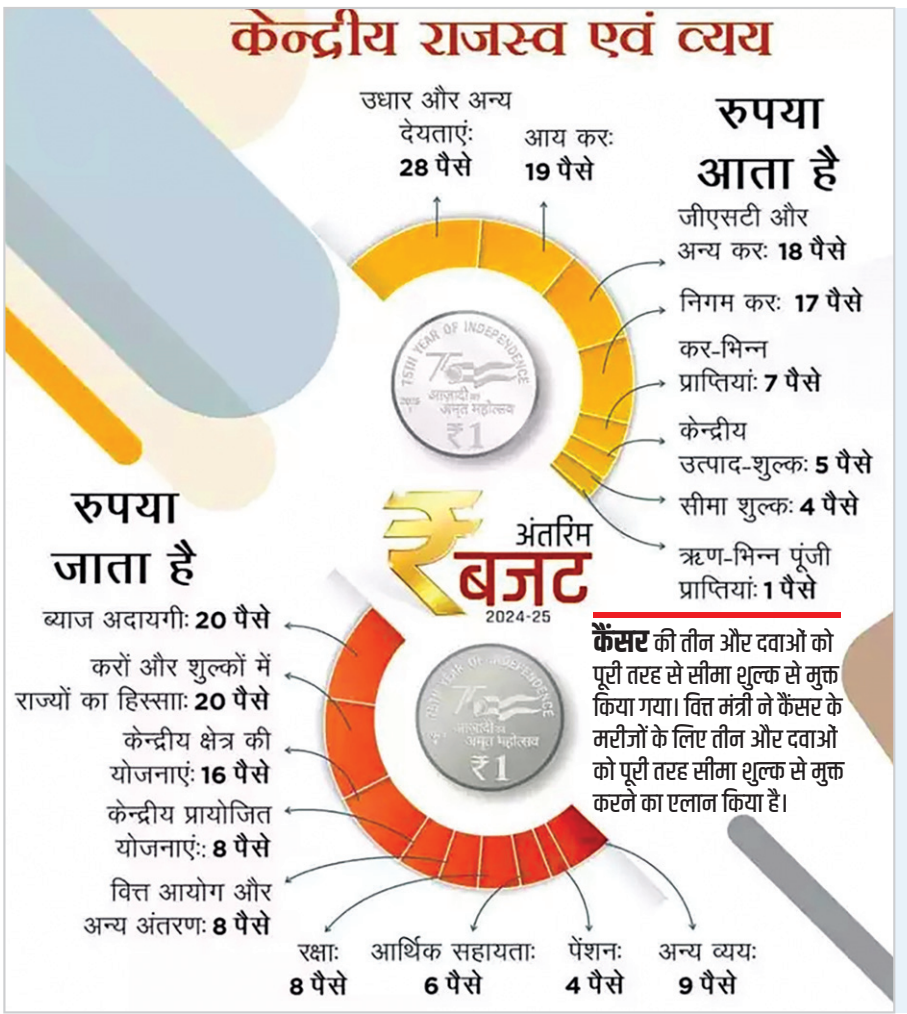

वित्त मंत्री के बजट पर गदगद प्रधानमंत्री मोदी ने खूब थपथपाई मेज

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट संसद में पेश कर दिया। वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के पीएम मोदी के लक्ष्य को सामने रखते हुए सीतारमण ने लोकसभा में 84 मिनट तक अपना बजट भाषण पढ़ा। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले सदन में पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत भाजपा सांसदों ने 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के नारे के साथ किया तो वहीं जवाब में विपक्षी सांसदों ने 'जय संविधान' का नारा लगाया। निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान सत्ता पक्ष में आगे की पंक्ति में बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी और जेपी नड्डा लगातार मेज थपथपाकर वित्त मंत्री के बजट भाषण की प्रशंसा करते दिखाई दिए। उनके साथ एनडीए सरकार के मंत्री और सांसद भी हर महत्वपूर्ण घोषणा पर मेज थपथपाते नजर आए। प्रधानमंत्री मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के 84 मिनट के बजट भाषण के दौरान लगभग 78 बार मेज थपथपाकर बजट घोषणाओं का स्वागत किया। संसदीय परंपरा के अनुसार सदन के अंदर किसी बात का समर्थन करने के लिए तालियां नहीं बजाई जाती बल्कि मेज थपथपाकर ही समर्थन या तारीफ की जाती है। पिछले कुछ वर्षों की तुलना में देखा जाए तो इस बार के बजट भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों की तरफ से कोई बहुत ज्यादा हंगामा नहीं किया गया।

जानिए किसे-कितनी राशि आवंटित की गई?

वित्त मंत्रालय	1858158.52
रक्षा मंत्रालय	621940.85
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	278000.00
रेल मंत्रालय	255393.00
उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय	223323.36
गृह मंत्रालय	219643.31
ग्रामीण विकास मंत्रालय	180233.43
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय	168499.87
संचार मंत्रालय	137293.90
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय	132469.86
शिक्षा मंत्रालय	120627.87
जल शक्ति मंत्रालय	98713.78
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	90958.63
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय	82576.57
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	26092.19
परमाणु ऊर्जा विभाग	24968.98
श्रम और रोजगार मंत्रालय	22531.47
विदेश मंत्रालय	22154.67
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय	22137.95
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	21936.90
ऊर्जा मंत्रालय	20502.00
नवीन और नवीकरणीय मंत्रालय ऊर्जा	19100.00
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय	16628.12
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	15930.26
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	14225.47
अंतरिक्ष विभाग	13042.75
आदिवासी मामलों का मंत्रालय	13000.00
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय	11469.14
भारी उद्योग मंत्रालय	7242.00
मत्स्य पालन, पशुपालन डेयरी मंत्रालय	7137.68
कानून और न्याय मंत्रालय	6788.33
पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय	5900.00
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय	5453.83
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	4520.00
वस्त्र मंत्रालय	4417.03
सूचना और प्रसारण मंत्रालय	4342.55
आयुष मंत्रालय	3712.49
युवा मामले एवं खेल मंत्रालय	3442.32
पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जलवायु परिवर्तन	3330.37
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय	3290.00
संस्कृति मंत्रालय	3260.93
अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय	3183.24
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय	3064.80
कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय	2667.06
पर्यटन मंत्रालय	2479.62
कार्मिक, लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय	2379.87
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय	2377.49
नागरिक उड्डयन मंत्रालय	2357.14
खान मंत्रालय	1941.06
राष्ट्रपति, संसद, संघ लोक सेवा आयोग और उपराष्ट्रपति का सचिवालय	1884.92
पंचायती राज मंत्रालय	1183.64
सहकारिता मंत्रालय	1183.39
योजना मंत्रालय	837.26
इस्पात मंत्रालय	325.66
कोयला मंत्रालय	192.55
संसदीय मामलों का मंत्रालय	64.00
कुल योग	48,20512.08
मंत्रालय/विभाग	आवंटित राशि (करोड़ में)

अहम योजनाएं के लिए बजट

योजनाएं	बजट (करोड़ में)
मनरेगा योजना	86,000
आयुष्मान भारत	7,300
पीएलआई योजना	6,200
सौर ऊर्जा (ग्रिड)	10,000
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली	6,250
पीएम आवास (शहरी)	30,171
पीएम आवास (ग्रामीण)	54,500
पीएम विश्वकर्मा	4824
पीएम ग्राम सड़क	19000
मिशन वात्सल्य	1472

वित्त मंत्री के पिटारे से युवाओं के लिए निकला ये खास तोहफा

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सातवीं बार सदन में आम बजट पेश कर रही हैं। इसके साथ ही उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया है। इस केंद्रीय बजट में निर्मला सीतारमण ने 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव किया है। इसके तहत घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, मुझे 2 लाख करोड़ रुपये के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 वर्षों में 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाओं और पहलों के प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है। इस वर्ष हमने शिक्षा, रोजगार और कौशल के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इसके साथ ही देश के युवाओं के लिए इस बजट में वित्त मंत्री ने जो ऐलान किया है।

सस्ता हुआ सोना और चांदी, ज्वेलरी शेयर चमके

एजेंसी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट में सोने-चांदी पर आम लोगों को खुशखबरी दी। वित्त मंत्री ने सोने और चांदी पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटाकर 6 प्रतिशत कर दिया, जो कि पहले 15 प्रतिशत थी। सीतारमण ने संसद में अपने बजट भाषण में कहा कि सोने और कीमती धातु के आभूषणों में घरेलू वैल्यू एडिशन को बढ़ाने के लिए, मैं सोने और चांदी के सीमा शुल्क को घटाकर 6 प्रतिशत करने का प्रस्ताव करती हूं। सरकार की इस घोषणा के साथ एमसीएक्स पर 24 कैरेट सोने के 5 अगस्त, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 5.33 प्रतिशत गिरकर 68,840 रुपये हो गया। वहीं, चांदी के 5 सितंबर, 2024 के कॉन्ट्रैक्ट का भाव 4.62 प्रतिशत गिरकर 85,079 रुपये प्रति किलो हो गया। वहीं, दूसरी तरफ ज्वेलरी शेयरों में तेजी देखी गई। दोपहर 2:30 बजे तक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) पर टाइटन का शेयर 6.65 प्रतिशत, सेंको गोल्ड का शेयर 5.53 प्रतिशत, टीबीजेड का शेयर 11.71 प्रतिशत, पीसी ज्वेलर्स 5 प्रतिशत और राजेश एक्सपोर्ट्स का शेयर 6.79 प्रतिशत की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था। बजट में टैक्स के मोर्चे पर भी आम आदमी को राहत दी गई है। नई टैक्स रिजीम में 3 से 7 लाख तक की आय पर 5 प्रतिशत टैक्स कर दिया गया है।

सीतारमण ने उत्तर पूर्व में 100 से अधिक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक शाखाएं स्थापित करने की घोषणा की

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में अपना सातवां बजट पेश करते हुए घोषणा की कि उत्तर पूर्व में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) की 100 से अधिक शाखाएं स्थापित की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के पूर्वोत्तर के विकास के दृष्टिकोण को यह कदम दशार्ता है। आईपीपीबी देश के अंतिम छोर पर रहने वाले लोगों को विभिन्न उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने में सबसे आगे है। यह डोर स्टेप बैंकिंग (डीएसबी) सेवाओं के साथ ग्राहकों को घर पर बैंकिंग सुविधाओं का अवसर भी देता है। इसके कारण, लाखों ग्राहकों को सहायक बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए 1.36 लाख से अधिक डाकघर देश के सबसे दूरदराज के इलाकों तक बैंकिंग को सुलभ बना रहा है।

रक्षा मंत्रालय के लिए बजट में 6,21,940 करोड़ रुपये का प्रावधान, राजनाथ सिंह ने जताया आभार

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस आम बजट में कई बड़े ऐलान के साथ तमाम मंत्रालयों के लिए धन का आवंटन किया गया है। इसी कड़ी में राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय को आवंटित बजट के लिए मोदी सरकार का आभार जताया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जहां तक रक्षा मंत्रालय के आवंटन का सवाल है, मैं 6,21,940.85 करोड़ रुपये का उच्चतम आवंटन देने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद देता हूं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत सरकार के कुल बजट का 12.9 प्रतिशत है। 1,72,000 करोड़ रुपये का पूंजीगत परिव्यय सशस्त्र बलों की क्षमताओं को और मजबूत करेगा।

केंद्रीय बजट में एमएसएमई, कृषि और इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर, कई एक्सपर्ट्स ने घोषणा का किया स्वागत

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को अपना सातवां और मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और एमएसएमई सेक्टर पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट को एक्सपर्ट्स ने सराहनीय बताया है। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को लेकर जम्मू के व्यापारी शिवांग महाजन ने बताया, प्रधानमंत्री ने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। उसी को ध्यान में रखते हुए बजट लाया गया है। बजट में एमएसएमई सेक्टर में 100 करोड़ रुपए का जो लोन दिया गया है, वो बहुत ही सराहनीय कदम है। स्टार्टअप को बढ़ाने, ई कॉमर्स हब बनाने, उसमें टैक्स को लेकर जो घोषणा की गई है और जो इंटर्नशिप का प्रावधान है।

सभी वर्ग-समुदायों को उनका हक-अधिकार दे रही राज्य सरकार : हेमंत सोरेन

नवीन मेल संवाददाता

रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने मंगलवार को पी पीएमएवाई (शहरी) योजना अंतर्गत राज्य संपोषित रांची के साईं सिटी के नजदीक स्थित नवनिर्मित मुड़मा कुष्ठाश्रम परियोजना का विधिवत उद्घाटन किया। मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शुभारंभ हो रहे इस परियोजना का लाभ विशेष परिवारों को मिल रहा है। ये आशियाना एक विशेष समूह के लिए बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं चाहूंगा कि इस परिसर को "निर्मल आवास" के नाम से जाना जाए। आज यहां उपस्थित सभी लोग इस परियोजना के विषय में पहले से अवगत हैं। हमारी सरकार का सदैव प्रयास रहा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति चाहे वे किसी भी वर्ग-समुदाय के हों, जिस स्थिति या परिस्थिति में रह रहे हों उन तक सरकार की आवाज पहुंचे। सरकार द्वारा संचालित जनकल्याण की योजनाएं पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार लगातार आमजनों की बात सुनती है, समझती है और उनके विकास के लिए कार्य भी करती है। राज्य सरकार आगे भी जनहित के कार्य प्रतिबद्धता के साथ करती रहेगी।

आज ऐतिहासिक दिन, सैकड़ों परिवारों को मिला आशियाना

मुख्यमंत्री ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है। राज्य सरकार ने एक बेहतर प्रयास किया है। सैकड़ों लोग आज अपने घर के मालिक बन रहे हैं। वे आज से इस नवनिर्मित आवासों के अंदर पूरे परिवार के साथ रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप जैसे विशेष समूह के परिवारों के लिए अलग-अलग जिलों में भी इस तरह की कल्याणकारी योजनाएं प्रारंभ की जा रहीं हैं। इस आशा के साथ कि आने वाले समय में आप जैसे लोग जो अपने जीवनयापन के लिए संघर्ष कर रहें हैं उनके दुःखों को हमारी सरकार कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गरीब, जरूरतमंदों के प्रति जवाबदेह और संवेदनशील है। विपरीत चुनौतियों के बावजूद जनकल्याण के कार्य निरंतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में भी होते रहेंगे। सभी वर्ग-समुदायों को उनका हक अधिकार राज्य सरकार देने का कार्य कर रही है।

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने बजट को सराहा

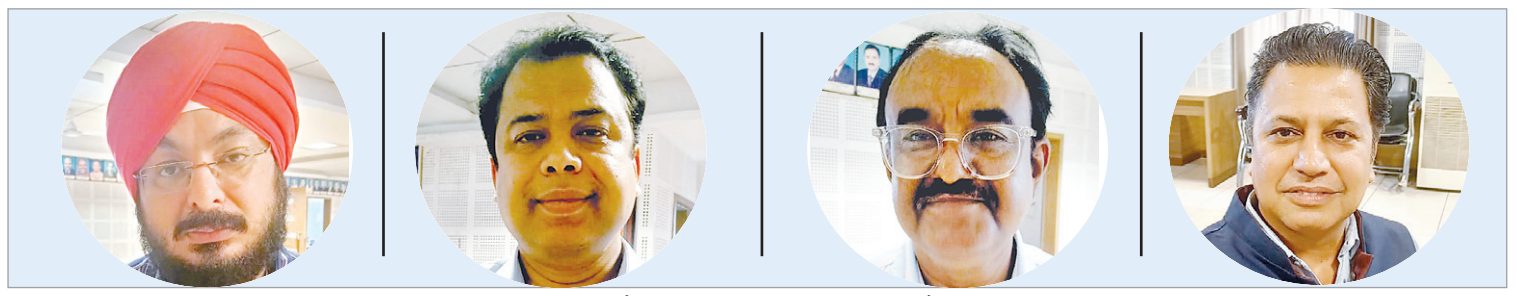

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष किशोर मंत्री ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोगों को इनकम टैक्स में राहत मिली है। यह अच्छा फैसला है। इसके अलावा रोजमर्रा की चीजों की कीमतों में कमी आयी है। बाकी झारखंड में स्वास्थ्य और शिक्षा मुख्य मुद्दा है जो सरकार को प्लान करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में अगर कोई बीमार होता है या उच्च तकनीकी शिक्षा लेना चाहता है तो उसे साउथ जाना पड़ता है। केंद्र सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। झारखंड में चुनाव है लेकिन चुनाव को देखते हुए भी कोई विशेष कुछ नहीं दिया गया। झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी सदस्य नवजोत अलंक ने केंद्रीय बजट का सराहा है। उन्होंने कहा कि बजट अच्छी है। वहीं इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि कैंसर की तीन दवाइयां पर कस्टम छूट दी गई है। मोबाइल और चार्जर भी सस्ते हुए हैं। झारखंड के लिए बहुत विशेष नहीं है लेकिन कई योजनाओं से झारखंड भी जुड़ा हुआ है। वहीं, पूर्व जनरल सेक्रेटरी डॉ अभिषेक रामधीन ने कहा कि बजट काफी अच्छा है। इस बजट में किसान, व्यापारी और स्टूडेंट सभी का ध्यान रखा गया है। जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर दिया गया है यह 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगा। बजट काफी अच्छा है। केंद्र का बजट पूरे देश को ध्यान में रखकर किया जाता है। इस बजट में हर वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। टैक्स स्लैब को भी काफी अच्छे तरह से प्रस्तुत किया गया है। संजय अखोरी ने कहा कि यह बजट मेरी नजर से केंद्र को ध्यान में रखकर बनाया गया है। कुछ राज्यों को विशेष मिला है। वहीं झारखंड को कुछ विशेष नहीं मिला। ई-कॉमर्स कंपनियों को टीडीएस में छूट देने से छोटे व्यापारियों को दिक्कत होगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष सह रांची मोटर्स डीलर एसोसिएशन के महासचिव आदित्य मल्होत्रा ने कहा कि बजट बहुत उत्साह वर्धक है। युवाओं को इंटर्नशिप कराया जा रहा है। इससे रोजगार बढ़ेगा, फ्रेशर की समस्या खत्म होगी, क्योंकि प्रेशर को नौकरी मिलने में दिक्कत होती थी। भारत के टॉप 500 कंपनियों में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप कराया जाएगा, यह बहुत बड़ी बात है। सिडबी बैंक के ब्रांचों को बढ़ाया जायेगा जो इंडस्ट्री खोलने में सुविधा होगी। मुद्रा लोन बढ़ाया गया है। अब यह 20 लाख रुपये तक कर दिया गया है। 20 लाख में एक व्यवसाय खड़ा किया जा सकता है। भारत में बहुत सारा फूड बेस्ट हो जाता था। फूड होल्डिंग से कम कीमतों में सामान को नहीं भेजा जाएगा। हमारी मांग थी कि रांची से रायपुर तक के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाया जाए लेकिन यह नहीं मिला। वहीं मेरी मांग थी की वंदे भारत ट्रेन रांची से रायपुर और रांची चलाया जाये।

केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अनुदान में वृद्धि अच्छी पहल : डॉ विनय

रांची। केंद्रीय बजट को डीएसपीएमयू के अंग्रेजी स्नातकोत्तर विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ विनय भरत ने सराहना की है। उन्होंने कहा कि एक तरफ यह अच्छी बात है कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए अनुदान 4,000 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हुई और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 15,928 करोड़ रुपये आवंटित किए गए। लेकिन यह उतना ही आश्चर्यजनक है कि यूजीसी के लिए फंडिंग को 60.99 प्रतिशत तक घटा दिया गया। पिछले साल के संशोधित अनुमान के 6,409 करोड़ रुपये से इसे घटाकर 2,500 करोड़ रुपये कर दिया गया। गौरतलब हो कि उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में बढ़ोतरी के लिए यूजीसी रिसर्च की पैरोकार है और दूसरी तरफ उसके ही बजट को 60% तक काट दिया जाता है।

बजट राजकोषीय अनुशासन और विकास का मिश्रण है : सीए शुभम

रांची। सीए शुभम मोदी ने कहा कि 23 जुलाई को प्रस्तुत भारतीय बजट 2024, राजकोषीय अनुशासन और विकास पहल का एक रणनीतिक मिश्रण है। राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% पर बनाए रखना और पूंजीगत व्यय को 11.1% तक बढ़ाकर, यह बुनियादी ढांचे के विकास और आर्थिक स्थिरता पर जोर देता है। बजट महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण उपायों पर भी प्रकाश डालता है, जिसमें आयुष्मान भारत के तहत विस्तारित कवरेज और किसानों और महिला उद्यमियों के लिए बढ़ा हुआ समर्थन शामिल है। हालांकि, कर दरों में बदलाव की कमी को व्यापक कर राहत के लिए एक चूक गए अवसर के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि मानक कटौती में वृद्धि और स्लैब दरों में बदलाव के कारण वेतनभोगी वर्ग को इससे थोड़ी राहत मिल सकती है, उन्हें आयकर में 17500 रुपये तक का अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। । फ्यूचर एंड ऑप्शन बाजार में खुदरा निवेशकों के जोखिम पर अंकुश लगाने के लिए एसटीटी बढ़ाया गया है और लॉन्ग टर्म और शार्ट टर्म कैपिटल गेन करों में भी वृद्धि हुई है। इंदिरेक्ट टैक्सेज में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिला. रूफटॉप सोलराइजेशन जैसी पहल के माध्यम से हरित ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करना, सतत विकास के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

छात्रों ने कहा- बजट से युवाओं को मिलेगा रोजगार

रांची। छात्र अविनाश कुमार ने कहा कि मुद्रा लोन में बढ़ोतरी एवं छात्रों के लिए कम ब्याज दरों पर लोन की उपलब्धता जैसे स्कीमों का जो सरकार ने आज निर्णय लिया है यह बेहद ही प्रासंगिक है। इसकी सराहना की जानी चाहिए। युवाओं को इससे रोजगार मिलेगा और वह अपना व्यवसाय शुरू कर पाएंगे। छात्रा कोमल कुमारी ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया यह बजट बेहद सराहनीय है। इसमें महिलाओं, बच्चों व बुजुर्गों सभी का ध्यान रखा गया है। देश के विकास के लिए यह बेहद सहायक सिद्ध होगा एवं देश की प्रगति इसे सुचारु रूप से विकसित होगी।

सर्वस्पर्शी है यह बजट : डॉ अटल

रांची । वोकेशनल शिक्षक एशोसिएसन के अध्यक्ष डॉ अटल पांडेय ने कहा कि पहली नौकरी पर युवाओं के इपीएफओ खाते में 15000 रुपए आएंगे। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख तक के ऋण के लिए इस वाउचर की सुविधा। हर वर्ष 1 लाख छात्रों को ऋण राशि पर 3% ब्याज पर छूट मिलेगी। महिलाओं और लड़कियों के लिए 3 लाख करोड़ रुपए पास किये गये हैं जो उनके विकास और सशक्तिकरण पर खर्च होगा। कैंसर जैसे असाध्य रोगियों के लिए फायदेमंद रहा यह बजट। मध्यमवर्गीय परिवारों को हर टैक्स स्लेव बढ़ाकर राहत दी जा रही है। कुल मिलाकर सर्वांगीण और सर्वस्पर्शी है यह बजट।

बजट से देश की अर्थव्यवस्था होगी मजबूत : संदीप

रांची। रांची नागरिक समिति के सचिव संदीप नागपाल ने कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पेश किया इस बजट में भी पिछले 10 वर्षों की भांति देश की अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने पर बल दिया गया है। नागपाल ने कहा यह बजट विशेष कर गरीब किसान महिलाओं का बजट है इस बजट से एक विकसित भारत का निर्माण होगा नागपाल ने कहा कुल मिलाकर बजट विकसित भारत वाला बजट है। बजट विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

झारखंड हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान मौखिक कहा

रिम्स की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार हो, अन्यथा इसे बंद करना बेहतर

प्राइवेट अस्पतालों में हेल्थ केयर की जगह रखा जाता है वेल्थ केयर पर ध्यान

कहा, रिम्स में मेडिकल सुविधाओं का अभाव, मरीज के देखभाल में भी लापरवाही

लोग प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं, जिनमें कई बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सरकारी एवं प्राइवेट अस्पतालों में चिकित्सा में लापरवाही से संबंधित एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान रांची स्थित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) की कुव्यवस्था पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से मौखिक कहा कि या तो रिम्स में चिकित्सा उपकरण, मेडिकल फैसिलिटी सहित आधारभूत संरचना उपलब्ध कराई जाए, अन्यथा इसे बंद करना ज्यादा बेहतर होगा।

कोर्ट ने कहा कि रिम्स में मेडिकल सुविधाओं का अभाव, मरीज के देखभाल में लापरवाही अक्सर देखने को मिलता है। रिम्स की व्यवस्था सही नहीं रहने पर लोग प्राइवेट अस्पतालों के शरण में जा रहे हैं। रांची शहर में ही कई प्राइवेट अस्पताल बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे हैं। बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहे इन प्राइवेट अस्पतालों की संख्या झारखंड में दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। प्राइवेट अस्पतालों और नर्सिंग होम में हेल्थ केयर की जगह वेल्थ केयर पर ध्यान रखा जाता है।कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने का आग्रह किए जाने पर मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि शपथ पत्र में राज्य सरकार की ओर से ऐसी बातें कही जाती हैं, जिससे लगता है कि स्विट्जरलैंड में हैं। कोर्ट ने पिछले पांच सालों में झारखंड में क्लीनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं लेने वाले नर्सिंग होम एवं अस्पतालों पर कार्रवाई और इस एक्ट का अनुपालन नहीं करने वालों पर लगे जुर्माना के संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा है कि क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट का अनुपालन नहीं करने वाले अस्पताल एवं नर्सिंग होम पर कितना जुर्माना लगाया गया है। मामले के अगली सुनवाई आठ अगस्त को होगी।

याचिकाकर्ता के पिता की मौत मेदांता, रांची में अक्टूबर 2017 को इलाज में लापरवाही की वजह से हुई थी। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर झारखंड में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने एवं इस एक्ट का अनुपालन करने का निर्देश अस्पतालों को देने का आग्रह किया गया था। बाद में कोर्ट ने इस विषय में वृहत संभावनाओं को देखते हुए इसे जनहित याचिका में तब्दील कर दिया था।

सीईओ की मतदाताओं से अपील, ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में नाम जरूर जांच लें

नवीन मेल संवाददाता। रांची

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने कहा कि राज्य में 25 जुलाई को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के अवसर पर सभी मतदान केंद्रों पर बीएलओ द्वारा इस मतदाता सूची के प्रारूप को प्रदर्शित किया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील की कि वे 25 जुलाई को सुबह अपने मतदान केंद्र जाकर अपना नाम इस ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें। यदि कोई विसंगति हो तो तत्काल अपने बीएलओ को बताएं।

के. रवि कुमार राज्य में चल रहे मतदाता सूची के द्वितीय विशिष्ट संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत 25 जुलाई को होने वाले मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के संदर्भ में निर्वाचन सदन में मंगलवार को आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि लोग चाहें तो घर बैठे ही निर्वाचन आयोग के ऑनलाइन माध्यमों जैसे वोटर हेल्पलाइन ऐप या वोटर सर्विस पोर्टल के माध्यम से भी अपना नाम जांच सकते हैं। मतदाता मोबाइल से एसएमएस के माध्यम से भी मतदाता सूची में अपना नाम जांच सकते हैं। इसके लिए अपने नंबर से आईसीआई लिखकर फिर एक स्पेस देकर अपना मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नंबर लिखकर 1950 पर मैसेज करने से मतदाता पंजीकरण से जुड़ी जानकारी मेसेज से ही उपलब्ध हो जाएगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि यदि हम अभी से मतदाता सूची में अपने नाम की जांच कर लेंगे, तो फिर चुनाव के समय कोई असहज स्थिति नहीं आती है। अन्यथा, चुनाव के समय कहीं-कहीं ऐसी शिकायतें भी मिलती हैं कि उनका मतदाता पहचान पत्र है, लेकिन मतदाता सूची में नाम नहीं है। आगामी चुनाव के दौरान ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से बचने के लिए ही यह नाम जांचों अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने राज्य के आम मतदाताओं, राजनीतिक दलों, सोशल मीडिया इनफ्लुएंसर्स आदि सभी वर्गों से अपील की कि वे इस अभियान में अपनी सहभागिता निभाते हुए आम लोगों को मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के लिए प्रेरित करें।

न्यूज बॉक्स

जेएसएससी का सहायक आचार्य परीक्षा अब 28 को

रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से सहायक आचार्य की कक्षा छह से आठवीं के लिए अब 28 जुलाई को परीक्षा होगी। यह परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली थी, लेकिन इस दिन नक्सली बंदी के वजह से स्थगित कर दी गई है। इस परीक्षा के एडमिट कार्ड के लिए 24 जुलाई को लिंक जारी किया जाएगा।

हम स्वयं से सवाल करें, क्या लिख रहे हैं क्यों लिख रहे हैं : राकेश बिहारी

रांची। पिछले दिनों शहर में 'शब्दकार समूह' ने कविता पाठ और लोकार्पण से अलग कुछ ऐसे कार्यक्रम में सक्रियता दिखाई, जिससे संभावित रचनाकारों को मार्गदर्शन मिल सके। 'हम कैसे लिखें से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम स्वयं से सवाल करें कि हम क्या लिख रहे हैं! हम क्यों लिख रहे हैं!' ये कहना है सुप्रसिद्ध कथाकार और आलोचक राकेश बिहारी का। शब्दकार द्वारा आयोजित 'कथा- संवाद' कार्यक्रम में उन्होंने कथा लेखन पर बातचीत करते हुए यह बात कही। कहानी और उपन्यास में अंतर स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि कहानी एक घटना से शुरू होती है, वह जीवन को समग्रता में देखने का प्रयास नहीं करती।

सीईटी ने सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ मनाया 43वां स्थापना दिवस

रांची। रांची। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के सेंटर फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सीईटी) ने अपना 43वां स्थापना दिवस भव्य समारोहों और सामुदायिक कार्यक्रमों के साथ मनाया। सीईटी परिवार के बच्चों और महिलाओं ने अपने कलात्मक कौशल से 'स्वास्थ्य और पर्यावरण जागरूकता' पर बीते पखवाड़े में कई उत्कृष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया। सर्वप्रथम सदर अस्पताल, रांची के सहयोग रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बचाव संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने नगर आयुक्त से की मुलाकात

रांची। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम बचाव संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को खिलाड़ियों की सुविधाओं को लेकर रांची नगर निगम के नगर आयुक्त अमित कुमार से उनके कक्ष में मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने उन्हें एक मांग पत्र सौंपा, जिसमें समिति के सदस्यों ने कहा है कि रांची के ऐतिहासिक जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में जल जमाव के कारण खेल एवं खिलाड़ी दोनों त्रस्त हैं। इसे अविलंब ठीक करने की जरूरत है। मांग पत्र में कहा गया है कि पिछले दो महीनों से स्वच्छ पानी नहीं मिलने के कारण खिलाड़ी एवं आमजन बहुत परेशान हैं। यहां अविलंब प्याऊ बनाने की आवश्यकता है।

साइबर ठगी के पांच दोषियों को पांच-पांच साल की सजा

रांची। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने मंगलवार को बैंक अधिकारी बनकर करोड़ों की साइबर ठगी करने के पांच दोषियों को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही, कोर्ट ने सभी पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अदालत में पांचों को बीते शनिवार को दोषी करार दिया था। दोषियों में गणेश मंडल, प्रदीप मंडल, संतोष मंडल, पिंटू मंडल और अंकुश कुमार मंडल शामिल हैं।

मनरेगा कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल

रांची। राज्य के पांच हजार से अधिक मनरेगा कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। हड़ताल से राज्य में मनरेगा के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं का संचालन प्रभावित होगा। बता दें कि कर्मचारी लंबे समय से सेवा स्थायीकरण और सामाजिक सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन करते आ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार रोजगार सेवकों, कंप्यूटर ऑपरेटरों, इंजीनियरों, बीपीओ कर्मियों और अन्य लोगों की हड़ताल से बिरसा सिंचाई संवर्धन कुआं, बिरसा ग्रीन मैंगो गार्डन, अबुआ आवास और वीर पोटो हो खेल मैदान समेत कई योजनाओं के संचालन में व्यवधान पैदा होगा। इसके अलावा, लगभग 2,50,000 श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान प्रभावित हो सकता है।

सहायक पुलिसकर्मियों ने आंदोलन को आगे बढ़ाने का किया ऐलान

रांची। सहायक पुलिसकर्मियों ने सरकार के साथ सोमवार को बैठक में आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के बाद मंगलवार को एक बार फिर से आंदोलन को आगे जारी रखने का ऐलान किया है।झारखंड सहायक पुलिस प्रदेश संगठन के अध्यक्ष अविनाश द्विवेदी और सचिव विवेकानंद गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार के साथ हुई वार्ता में जिन बिंदुओं पर सहमति बनी है, यदि वह मांग 24 तारीख को होने वाली कैबिनेट में मान ली जाती है, तभी वे आंदोलन समाप्त करेंगे।

डीएवी हेहल में 'डीएवी स्पोर्ट्स-2024' क्लस्टर-5 का हुआ शुभारंभ

जो खेलेगा, वही खिलेगा : एसके मिश्रा

नवीन मेल संवाददाता। रांची

डीएवी पब्लिक स्कूल हेहल, रांची में चारदिवसीय 'डीएवी स्पोर्ट्स-2024' 'क्लस्टर-5' का शुभारंभ मंगलवार को एसके मिश्रा असिस्टेंट रीजनल अफसर डीएवी पब्लिक स्कूल्स झारखंड जोन-'जे'-सह क्लस्टर इंचार्ज ने डीएवी गान के साथ 'डीएवी खेल ध्वज' को फहरा कर किया।

डीएवी हेहल, रांची में डीएवी पब्लिक स्कूल्स झारखंड जोन-'जे' के सात विद्यालय, डीएवी हेहल, डीएवी बरियातू, डीएवी पुंदाग, डीएवी खूंटी, डीएवी टीसीआई गोविंदपुर, डीएवी सिल्ली, डीएवी खलारी के अंडर-14, 17 एवं 19 बालक-बालिका आयु वर्ग के लगभग 1085 खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, खो-खो, हैंडबॉल, कबड्डी, चेस, योग, एरोबिक्स एवं शूटिंग के खेलों को खेल भावना से खेलने की शपथ ली।

एसके मिश्रा ने खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि 'जो खेलेगा, वही खिलेगा।' खेल मानसिक, शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। यह हमें स्वस्थ रखने, दिमाग की क्षमता को विकसित करने, सामरिकता का अभ्यास करने और टीमवर्क करने का अवसर प्रदान करता है। यह हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमें सकारात्मक रूप से सोचने, संघर्ष करने और जीतने की क्षमता प्रदान करता है। एसके मिश्रा ने यह भी बताया कि जो क्लस्टर स्तर पर विजेता टीम होगी, वह स्टेट लेवल पर खेलेगी व जो टीम स्टेट में विजेता बनेगी, वह नेशनल लेवल पर खेलेगी। मौके पर सभी विजेता एवं उपविजेता टीम के खिलाड़ियों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर डीएवी विद्यालयों के प्राचार्य तापस घोष, संजीत कुमार मिश्र, कमलेश कुमार, रोशी बाधवानी, बुबुन शरण व शारीरिक शिक्षक संजय मंडल आदि मौजूद थे।

खेलों के परिणाम

वॉलीबॉल

बालक वर्ग अंडर-14

विजेता - डीएवी, खलारी

उपविजेता - डीएवी, टीसीआई, गोविंदपुर

बालक वर्ग अंडर-17

विजेता - डीएवी हेहल, रांची

उपविजेता - डीएवी, टीसीआई, गोविंदपुर

बालक वर्ग अंडर-19

विजेता - डीएवी, खलारी

उपविजेता - डीएवी, खूंटी

कबड्डी

बालक वर्ग अंडर-14

विजेता - डीएवी हेहल, रांची

उपविजेता - डीएवी, बरियातू

बालक वर्ग अंडर-17

विजेता - डीएवी हेहल, रांची

उपविजेता - डीएवी, खलारी

खो-खो

बालक वर्ग अंडर-14

विजेता - डीएवी हेहल, रांची

उपविजेता - डीएवी, टीसीआई, गोविंदपुर

डीएसपीएमयू में ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव 27 से

रांची। डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय (डीएसपीएमयू) और हेरिटेज सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में 27 एवं 28 जुलाई को ट्राइबल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है। इस आयोजन में देश की प्रतिष्ठित संस्थाओं और विश्वविद्यालयों के विद्वतजन अपने व्याख्यान द्वारा जनजातीय संस्कृति और विरासत पर प्रकाश डालेंगे। इस दो दिवसीय कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ तपन कुमार शांडिल्य करेंगे। मंगलवार को इससे संबंधित एक पोस्टर कुलपति डॉ तपन कुमार शांडिल्य ने जारी किया।

हेमंत वन, टू और थ्री ने झारखंड में तुष्टिकरण का खुला खेल खेला : प्रतुल

नवीन मेल संवाददाता। रांची

भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा भाजपा पर हिंदू, मुस्लिम करने के बयान पर कड़ी आपत्ति की है। प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा कि हेमंत 1, 2 और 3 में तुष्टिकरण का खुला खेल हुआ। सरकार ने पांच वर्ष जमकर मुस्लिम तुष्टिकरण का खेल खेला। बहुसंख्यकों की भावना को चोट पहुंचाया। प्रतुल ने कहा इसी सरकार ने सर्वप्रथम हिंदू फल दुकान लिखने पर जमशेदपुर में एक व्यक्ति को जेल भेज दिया था। इसी सरकार के कार्यकाल में एक आईएएस अधिकारी ने कांग्रेस के विधायक को नसीहत देते हुए कहा था कि मैं भी मुसलमान हूं और आप भी मुसलमान की वोट से जीतते हैं, इसलिए थोड़ा तमीज में रहें। प्रतुल ने कहा इसी सरकार ने तुष्टीकरण के तहत दुर्गा मां की प्रतिमाओं का साइज को सीमित कर दिया था और छठ पर्व को घाट में मनाने पर पाबंदी लगा दी थी।प्रतुल ने कहा हेमंत सोरेन कैसे भूल सकते हैं कि उनकी सरकार के कार्यकाल में ही सामान्य सरकारी विद्यालयों को जबरन उर्दू विद्यालय बना दिया गया।

हेमंत सोरेन के भाजपा पर हिंदू-मुस्लिम करने के बयान पर शाहदेव ने की कड़ी आपत्ति

चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ की बैठक

नवीन मेल संवाददाता। रांची

मतदाता सूची में नाम है या नहीं, इसको लेकर चुनाव आयोग ने मंगलवार को राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक की। बैठक में भाजपा की तरफ से मौजूद सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि चुनाव आयोग ने 25 जुलाई 24 को दिन के बारह बजे से एक बजे तक चुनाव आयोग एक अभियान चलाएगा, जिसका नाम होगा हैसटैग नामजांचो। यह अभियान चलाने का मकसद ये है कि हर मतदाता अपना नाम मतदाता सूची मे नाम खोज ले और अगर नहीं मिले तो नौ अगस्त तक अपना नाम जोड़वा ले। सुधीर श्रीवास्तव ने कहा कि यह अभियान इस कारण चुनाव आयोग ने शुरू किया है, क्योंकि लोक सभा चुनाव 24 मे बहुत से मतदाता का नाम मतदाता सूची से गायब हो गया था और इस संदर्भ कई बार चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी। 25 जुलाई को मतदाता सूची का प्रकाशन होना है और इसकी हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सभी राजनीतिक दलों को भेजा जाएगा। मतदाता सूची मे अपना नाम जांच लें। अगर नाम नहीं मिला, तो तत्काल अपना नाम ऑनलाइन जुड़वा लें या फिर ऑफ लाइन बूथ पर जाकर बीएलओ को फॉर्म 6 भरकर दें।

बजट 2024 : 'पूर्वोदय स्कीम' के जरिए चमकेगा झारखंड व पूर्वी भारत

नवीन मेल संवाददाता। रांची

केंद्रीय बजट में झारखंड और जनजातीय आबादी को लेकर महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में 'पूर्वोदय' नामक योजना शुरू करने का ऐलान किया है, जिसके अंतर्गत झारखंड के अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है। इस योजना का लक्ष्य इन पांचों राज्यों में चहुंमुखी विकास को गति देने के लिए मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन करना है, ताकि यह क्षेत्र विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रणी भूमिका निभाए।

बजट में आदिवासी समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू करने का ऐलान किया गया है। करीब 27 फीसदी जनजातीय आबादी वाले झारखंड के इस योजना से विशेष तौर पर लाभांवित होने की उम्मीद जताई जा रही है। यह योजना आदिवासी-बहुल गांवों और आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों को कवरेज देगा। इससे 63 हजार गांवों को कवर किया जाएगा, जिससे 5 करोड़ आदिवासियों को लाभ होगा। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समुदायों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाना होगा।

संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा यह बजट : संजय सेठ

रांची। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री सह सांसद संजय सेठ ने वर्ष 2024- 25 के बजट को सराहा है। उन्होंने कहा आज का बजट विकसित भारत की प्रतिबद्धता को पूर्ण करने की दिशा में ऐतिहासिक है। यह बजट मध्यवर्गीय, किसान, महिलाएं और युवाओं को सशक्त बनाते हुए संभावनाओं के नए द्वार खोलेगा। बजट में किसान, मध्य वर्ग ,और युवाओं को बजट में बड़ी सौगात दी गई है। कृषि क्षेत्र में 1.52 लाख करोड़ रुपए दिए गए हैं। युवाओं के लिए रोजगार व कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी पांच योजनाओं के लिए दो लाख करोड़ आवंटित किए गए हैं। 500 बड़ी कंपनियां में एक करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए जाएंगे। वहीं एक करोड़ छात्रों को 5000 रुपये मासिक भत्ता दिया जाएगा। हायर एजुकेशन के लिए 10 लाख तक लोन, कैंसर मरीजों को राहत देते हुए तीन दबाव पर सीमा शुल्क पूरी तरह हटाने का प्रस्ताव यह मध्य वर्ग के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वित्त मंत्री ने मध्यम वर्ग एवं गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सभी लोगों का पूरा ख्याल रखा है।

देश के चौमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 25000 ग्राम वासियों बस्तियों को मौसम के अनुकूल सड़क उपलब्ध कराना हो, आदिवासी समाज की समृद्धि मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत आदिवासियों के आर्थिक और सामाजिक तौर पर सशक्त किया जाएगा। रक्षा के क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनता है यह बजट नवभारत की मजबूत नींव साबित होगा। समाज के हर वर्ग को सशक्त करने वाले इस बजट के लिए देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एवं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई।

यह बजट युवा, गरीब, महिला व किसान सभी के लिए : अर्जुन मुंडा

रांची। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को कहा कि यह बजट विकसित भारत के चार स्तंभ युवा, गरीब, महिला और किसान सभी के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। यह बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बजट है। मुंडा ने कहा कि बजट में आदिवासियों की आर्थिक-सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करने की घोषणा की गयी है। इसमें 11 लाख करोड़ रुपये से अधिक का पूंजीगत व्यय आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के लिए घोषणाएं पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। कौशल और रोजगार सृजन की घोषणाएं ऐतिहासिक हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं।

विकासोन्मुख, युवा केंद्रित सर्व समावेशी बजट : बाबूलाल मरांडी

रांची। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने मोदी सरकार 3.0 के द्वारा सदन में प्रस्तुत पहले बजट की सराहना की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई व शुभकामनाएं दी। श्री मरांडी ने कहा कि यह बजट सर्व समावेशी, युवा केंद्रित और विकासोन्मुख बजट है। उन्होंने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्पों को साकार करने वाला बजट है। यह बजट 140 करोड़ देशवासियों की आशा एवं आकांक्षाओं के अनुरूप समाज के सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास को भी गतिशीलता प्रदान करेगा।

उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए यह बजट सुनहरा अवसर लेकर आया है। स्किल डेवलपमेंट के साथ-साथ 5 वर्षों में 4 करोड़ रोजगार की व्यवस्था देश के विकास में युवाओं की भूमिका को सुनिश्चित करेगा।

कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और महिला ये चार स्तंभों पर बजट आधारित है। साथ ही पूर्वोत्तर को विकास केंद्रित क्षेत्र जिसमे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, असम प्रदेश शामिल हैं। पूर्वोत्तर के विकास को सुनिश्चित कर भारत में नया सवेरा लाने की दिशा में मोदी सरकार कार्य कर रही है।कहा कि सरकार ने मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख की है, जिससे हमारे राज्य के गरीब आदिवासी भाइयों बहनों को बिना किसी गारंटर के सरलता से ऋण प्राप्त होगा।आदिवासी समाज की उन्नति एवं उन्हें विकास के मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ने विश्वसनीयता की गारंटी दी है। प्रधानमंत्री का यह अनमोल तोहफा झारखंड में आदिवासियों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा।

केंद्रीय बजट सभी वर्गों के लिए महत्वपूर्ण : सीपी सिंह

नवीन मेल संवाददाता। रांची

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश किया। इस बजट में भारत की अर्थव्यवस्था को आगे ले जाने का प्रयास शामिल है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के आर्थिक प्रकोष्ठ ने संसदीय बजट की व्याख्या के लिए एक एक्सपर्ट की टीम बनाई गई थी। उस टीम में अर्थशास्त्री, सीए, डाक्टर, प्रोफे सर आदि शामिल थे। उनलोगों ने कहा कि इस बजट का फायदा सभी वर्गों को होगा। रांची के विधायक सीपी सिंह ने कहा कि सालाना एक लाख से कम आय वालों को तीन हजार रूपए प्रतिमाह केंद्र की तरफ से सहायता राशि उपलब्ध होगी। छात्रों को पढाई करने के लिए मात्र तीन प्रतिशत पर लोन उपलब्ध होगा। एमएसमइ मुद्रा लोन को दस लाख से बढाकर बीस लाख कर दिया गया है। राष्ट्रीय नवीन मेल संवाददाता द्वारा यह पूछे जाने पर कि झारखंड को इस बजट में क्या मिला? विधायक सीपी सिंह ने कहा कि केंद्र की योजनाओं का लाभ सभी राज्यों को होगा। निःसंदेह झारखंड को भी सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। दरअसल वर्तमान हेमंत सोरन की सरकार विकास के मुद्दे पर काम ही नहीं करना चाहती। केंद्र सरकार सहायता देना चाहती है मगर राज्य सरकार लेना नहीं चाहती। नगर निकाय चुनाव केंद्र सरकार कराना चाहती है राज्य सरकार नहीं कराना चाहती। विकास के नियत की कमी है राज्य सरकार में।

पूर्वोदय योजना से झारखंड को सीधा लाभ : प्रतुल

भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने बजट को समावेशी और सभी वर्गों का खयाल रखने वाला बताया। उन्होंने कहा कि पूर्वोदय योजना के विकास के रोड मैप से झारखंड को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा।पूर्वी भारत भी देश के बाकी हिस्सों की तरह विकास की रफ्तार पकड़ेगी। इसके अतिरिक्त आकांक्षी जिला योजना की फंडिंग जारी रहने से झारखंड के 19 जिलों को सीधे तौर पर केंद्रीय राशि मिलती रहेगी।जनजातीय उन्नत ग्राम योजना के प्रारंभ होने से जनजातीय बहुल झारखंड की विकास में तेजी आएगी।इसके अतिरिक्त केंद्र की सभी योजनाओं का हिस्सा तो झारखंड को मिलेगा ही।मुद्रा लोन ने अब तक 30 करोड़ से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में सहायता की है। इसकी सीमा 20 लाख रुपया करने से छोटे व्यवसायियों और नया व्यवसाय शुरू करने वालों को बड़ा फायदा मिलेगा।

दलित और आदिवासियों को धोखा देने वाला बजट : भाकपा

रांची। भाकपा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक और जिला सचिव अजय कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से कहा कि वित्त मंत्री के जरिये पेश किया गया आम बजट देश के नौजवानों, महिलाओं, किसानों, दलित और आदिवासियों को धोखा देने वाला है। दोनों संयुक्त रूप से बजट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। दोनों नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में मिली शिकस्त के कारण और कई राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बजट में सिर्फ घोषणाएं की गई है। पूरे देश में सबसे ज्यादा टैक्स देने वाले झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ और किसानों के सम्मान से खिलवाड़ किया गया है। आवश्यक दिनचर्या और खाद्य पदार्थों पर टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई है। इसलिए यह आम बजट पूंजीवाद को फायदा और देश की 80 प्रतिशत जनता मजदूर छात्र नौजवान एवं विकास से वंचित लोगों पर बोझ डालने वाला बजट है। केंद्र सरकार ने पूंजीपतियों को ध्यान में रखकर बजट बनाया है, जो देश की 80 प्रतिशत जनता के हित में नहीं है।

बजट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास लोगों के लिए : झामुमो

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि वित्तमंत्री सीतारमण की ओर से पेश किया गया आम बजट आम लोगों के लिए नहीं, बल्कि खास लोगों के लिए बनाया गया है। उन्होंने कहा कि ये बजट प्रधानमंत्री की कुर्सी बचाओ या सत्ता बचाओ योजना के अंतर्गत आया है। ये बजट देश के लिए कतई नहीं है।

श्री भट्टाचार्य मंगलवार को संवाददाता सम्मेलन में बोल रहे थे। सुप्रियो ने कहा कि इस बजट से ये जाहिर हुआ कि केंद्र सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है। इस डर के कारण ही आंध्र प्रदेश पर खास ध्यान दिया गया है। साथ ही बिहार पर भी बजट को फोकस किया गया है। थोड़ा ध्यान ओडिशा पर भी ध्यान दिया गया है। इससे ऐसा लगता है कि बाकी 27 राज्य इस देश में है ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने हालिया चुनावों को मुद्दाविहीन हो कर लड़ा। केवल सांप्रदायिक बातें की। उन्होंने कहा कि बजट भी उसी की झलक जैसा

सुप्रियो ने कहा, इस बजट से ये जाहिर हुआ कि केंद्र सरकार अंदर से कितनी डरी हुई है।

है। सुप्रियो ने कहा कि बजट में सबसे ऊपर एग्रीकल्चर सेक्टर आता है। इससे पहले के बजट में एग्रीकल्चर के लिए कुल राशि का 6.5 प्रतिशत हिस्सा हुआ करता था। आज ये घटकर 3.9 प्रतिशत पर आ गया है। बजट में एमएसपी की कोई चर्चा नहीं है, जो अत्यंत अहम सेक्टर है और जिससे पेट भरा जाता है, उस पर कोई बात नहीं हुई। केवल फल और सब्जी पर बात हुई। उन्होंने कहा कि बजट में दूसरा अहम मुद्दा रोजगार का होता है। उन्होंने कहा केंद्र ने कल आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए देश में बेरोजगारी दर को 3.2 प्रतिशत बताया लेकिन सरकार की ही एक सहयोगी संस्था है सीएमआईई। ये एजेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी रिपोर्ट करती है। इस एजेंसी का आकलन है कि देश में बेरोजगारी दर 9.2 तक पहुंच गयी है। ये एक बड़ा घालमेल है।

सुप्रियो ने कहा कि किसी नई नौकरी या सरकारी नौकरी की घोषणा तक नहीं हुई। उन्होंने कहा कि शिक्षा पर कोई बात ही नहीं हुई। हेल्थ पर कोई बात नहीं हुई। बात हुई तो इस पर कि इलाज महंगा होगा और सोना सस्ता होगा। लोगों को कहा गया कि अधिक से अधिक मोबाइल खरीदिये। क्योंकि, इसकी कीमत कम कर दी गयी है। महंगाई जैसे विषय पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने कहा कि ये बजट, बिना सोच समझ के और बिना सही विचार के साथ बनाया गया एक दस्तावेज मात्र है। इससे देश में बेरोजगारी बढ़ेगी। किसानों के समक्ष मुश्किलें बढ़ेंगी।

ग्रेफाइट माइनिंग में भी उतर रही है कोल इंडिया

रांची। कोयले, सौर ऊर्जा और गैसीकरण के बाद अब कोल इंडिया ग्रेफाइट माइनिंग में भी उतर रही है। सीएमपीडीआई से मिली जानकारी के अनुसार खान मंत्रालय के आदेश के बाद कंपनी को अब ग्रेफाइट के प्रॉस्पेक्टिंग और माइनिंग के लिए कंपोजिट लाइसेंस मिला है। हालांकि, यह लाइसेंस मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में खट्टाली ग्रेफाइट ब्लॉक से संबंधित है। कोल इंडिया के बिजनेस डेवलपमेंट निदेशक देवाशीष नंदा ने बताया कि कोयले के अलावा यह हमारे लिए पहला मिनरल है। कोल इंडिया को राज्य सरकार को भेजे जाने वाले मिनरल की वैल्यू का 150.05 प्रतिशत माइनिंग प्रीमियम देना होता है। कोल इंडिया ने शेयर बाजार को बताया है कि कंपोजिट लाइसेंस की समय सीमा एक वर्ष और माइनिंग लीज तीन साल के लिए है। केंद्र सरकार के आत्मनिर्भरता विजन के अनुसार कोल इंडिया ने ग्लोबल और भारत के अंदर अहम खनिजों पर फोकस करने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई है। ग्रेफाइट का इस्तेमाल बैटरी के अलावा कई एप्लिकेशन में होता है। भारत में ईवी को बढ़ावा दिए जाने के बीच यह फोकस में है। देवाशीष नंदा ने बताया कि प्रोजेक्ट के लिए पूंजीगत व्यय का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी।

समग्र विकास के लिए परिवर्तनकारी पहल : अमर बाउरी

नवीन मेल संवाददाता। रांची

नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बाउरी ने बजट की सराहना करते हुए कहा कि झारखंड के हिस्से में कई योजनाओं की सौगात मिली है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए पूर्वोदय योजना ला रही है। इसके अंतर्गत इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए विशेष स्कीम। कहा कि इन क्षेत्रों में सरकार औद्योगिक गलियारे का भरपूर हर तरीके से समर्थन व सहयोग करेगी। कहा झारखंड के आदिवासी बहुल गांव होंगे लाभान्वित आदिवासियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए ₹प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान शुरू होगा। योजना आदिवासी-बहुल गांवों-आकांक्षी जिलों में आदिवासी परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज को अपनाएगी। इससे 63,000 गांवों को कवर किया जाएगा जिससे 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ होगा। कहा कि झारखंड के दूरदराज के गावों को जोड़ा जाएगा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण की शुरूआत की जाएगी, जिसके तहत देश भर के 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों के अनुकूल सड़कें उपलब्ध कराई जाएंगी।झारखंड में आवास की मांग करने वाले गरीबों व मध्यम वर्गीय परिवारों को मिलेगा बड़ा लाभ होगा।पीएम आवास योजना के तहत पूरे देश में तीन करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। बिजली बिल आपका शून्य हो इस तरफ आगे बढ़ी केंद्र सरकार बढ़ चुकी है। देश के 1 करोड़ घरों के लिए छतों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की गई। झारखंड समेत देश के युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसला मोदी सरकार 5 वर्षों में 500 शीर्ष कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करेगी।

ट्रेन में कांवरियों पर हुए हमले को लेकर बाबूलाल ने की पुलिस कार्रवाई की मांग

रांची। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कांवरियों पर हुए हमले की निंदा की है और पुलिस कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर कहा है कि रांची के पहाड़ी मंदिर जलाभिषेक करने आ रहे कांवरियों पर रांची-लोहरदगा ट्रेन में जानलेवा हमला और पथराव किए जाने की सूचना है। असामाजिक तत्वों द्वारा 2-3 स्टेशनों पर इस घटना को अंजाम दिया गया है।

कुल मिलाकर यह बजट आई वाश है : बन्ना

नवीन मेल संवाददाता। रांची

राज्य के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एक बार फिर मिडिल क्लास फैमिली को टैक्स के बोझ से दबा दिया है। चुनाव जीतने के बाद लगा था कि भाजपा टैक्स में राहत देगी लेकिन ये उल्टा हो गया। उन्होंने कहा कि बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए विकास फंड देना और झारखंड को उपेक्षित करना आदिवासी विरोधी मानसिकता का परिचायक है। उत्तर प्रदेश को भी उपेक्षित कर वहां की जनता से चुनावी बदला लिया गया है। कुल मिलाकर यह बजट आई वाश है। गुप्ता ने कहा कि मध्यम वर्ग के ऊपर लगता है चुनावी खर्च थोप दिया है। युवाओं को नौकरी के बदले इंटर्नशिप का झुनझुना वो भी ईएमआई में, किसानों और महिलाओं की फिर से उपेक्षा की गई है इस बजट में, कामगार और मजदूरों को फिर ठगा गया है। बजट को कांग्रेस के न्याय पत्र से चुराया गया है, जिसमें पहली नौकरी पक्की का वादा था। उन्होंने कहा कि झारखंड में केंद्रीय मंत्री चुनावी प्रभारी बने हैं लेकिन झारखंड की जनता को कुछ नहीं दिला सके। आश्चर्य है कि बजट में स्वास्थ्य सेवा का जिक्र नही है, उसके बजट को घटाया गया है।

केंद्र सरकार का बजट देश की जनता की आशाओं पर वज्रपात : राजेश ठाकुर

नवीन मेल संवाददाता। रांची

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट देश की जनता की आशाओं पर वज्रपात और झारखंड के लिए नील बट्टा सन्नाटा है। बजट का फोकस जनता नहीं, बल्कि सत्ता है और यह इस देश की विडंबना है। ठाकुर ने मंगलवार को बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश बजट उदाहरण बनकर रह गया है। झारखंड में लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला भाजपा ने केंद्रीय बजट में चुकाया है। उन्होंने कहा कि आश्चर्यजनक है कि कुल बजट का सिर्फ एक से दो प्रतिशत तक की राशि का प्रावधान पूरे देश में शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में किया गया है और

बातें उत्पादकता बढ़ाने की कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस बजट में राजनीतिक सहयोग की कीमत चुकाने की विवशता साफ दिखाई पड़ रही है। ठाकुर ने कहा कि अर्थव्यवस्था के विकास का इंजन निजी खपत के रिकॉर्ड सुस्ती पर बजट पूरी तरह मौन है। वर्ष 2016 से 2022 के बीच में 24 लाख उत्पादक कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इनके लिए सिर्फ क्रेडिट गारंटी की बात की गई है। ठोस कुछ भी नहीं किया गया है। बजट में जिस फिजिकल कंसोलिडेशन की बात की गई है उस लक्ष्य 4.5 फीसदी को यूपीए की सरकार ने 2014 में ही पा लिया था। किसानों को राहत पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर बजट में प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे किसानों के आय में वृद्धि हो सके। इसके विपरीत रिसर्च और कृषि संबंधित क्षेत्र के लिए प्रावधान किया जाना पिछले दरवाजे से कॉरपोरेट सेक्टर को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, जो इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ठाकुर ने कहा कि इस बजट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिले, बल्कि यूं कहें कि आम लोगों को इस बजट से कोई राहत नहीं है। उन्हें बजट के नाम पर झुनझुना भी नहीं दिया गया।

केंद्रीय बजट मजदूर व किसान विरोधी : भुनेश्वर

रांची। भाकपा (माले) के राज्य कमिटी सदस्य भुनेश्वर केवट ने कहा कि केंद्रीय बजट मजदूर व किसान विरोधी है। बजट में झारखंड के हिस्से कुछ भी नहीं मिला। झारखंड के बीमार उद्योगों के दुरुस्त करने की दिशा में बजट पूरी तरह से निराशा जनक है। एचईसी, कोयला उद्योग व छोटे उद्योगों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। गैर उत्पादक मदों के लिए राशि आवंटित किया गया है। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई विजन नहीं है। सिर्फ कॉरपोरेट कंपनियों के हितों का ख्याल किया गया है। युवाओं के लिए रोजगार सृजन और आम आदमी के आर्थिक हालात में सुधार की दिशा में कोई योजना नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के लिए भी बजट सिर्फ आईवाश है।

बड़े पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट : सुबोधकांत सहाय

नवीन मेल संवाददाता। रांची

पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय ने केन्द्र सरकार द्वारा मंगलवार को लोकसभा में पेश किए गए आम बजट पर तीखी प्रतिक्रिया की है। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट बड़े-बड़े पूंजीपतियों (कॉर्पोरेट घरानों) को लाभ पहुंचाने वाला बजट है। यह देश की जनता का नहीं, बल्कि विशेष तौर पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार का बजट है। उन्होंने कहा कि कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पर्यटन आदि के क्षेत्र में बजट में कोई नया प्रावधान नहीं किया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण भी महज आइवॉश है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार देने और बेरोजगारी दूर करने की दिशा में बजट में कुछ भी प्रावधान नहीं किया गया है। महंगाई पर नियंत्रण के लिए भी आम जनता को राहत नहीं दी गई। सरकारी कर्मचारियों व सेवानिवृतकर्मियों को भी इस बजट से घोर निराशा हुई है। आयकर की सीमा पांच लाख रुपए से घटाकर तीन लाख कर दिया जाना अनुचित है। उन्होंने कहा कि लगभग 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं। लेकिन उन पदों पर नियुक्ति के संबंध में बजट में कोई चर्चा नहीं की गई। युवाओं को रोजगार देने के नाम पर महज कागजी घोड़े दौड़ाए गए हैं। श्री सहाय ने कहा कि मध्यम वर्ग के लोग बड़ी मशक्कत से अपनी आमदनी में से कुछ राशि बचाकर रखा करते हैं, उस पर भी केंद्र सरकार की गिद्ध दृष्टि है। मध्यम वर्ग के जेब से कैसे उनकी मेहनत की कमाई निकाली जाए, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि झारखंड पूरे देश में खनिज संपदा से अधिक राजस्व देने वाला राज्य है। लेकिन झारखंड की जनता के लिए कोई राहत भरी बात बजट में नहीं की गई। उन्होंने कहा कि यह बजट आम लोगों के लिए नहीं बल्कि खास लोगों के लिए है।

आईसीआईसीआई बैंक में हुआ मारवाड़ी कॉलेज के 26 विद्यार्थियों का चयन

रांची। मारवाड़ी कॉलेज के प्लेसमेंट सेल द्वारा आयोजित कैंपस ड्राइव में बीकॉम, बीसए, आईटी, गणित और अंग्रेजी के 26 विद्यार्थियों का चयन आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर के पद पर 3.11 सीटीसी में हुआ। कैंपस ड्राइव मे अलग अलग विभागों के 200 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। उनका सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट और अलग अलग एचआर मैनेजेरियल और डिसीजन मेकिंग राउंड द्वारा किया गया। चयनित विद्यार्थियों में हर्षा अग्रवाल, हर्षिता कुमारी, सिमरन कुमारी, अभिजीत कुमार, नवदीप कुमार, विवेक कुमार, राहुल कुमार सिंह, अभिषेक सिंह, अंकिता कुमारी, सानिया फरहा, मोहित गुप्ता, खुशी कुमारी,अंकित कुमार गोपे शामिल हैं।

एसीसी के माइनिंग लीज नवीकरण आवेदन को निरस्त करने की मांग

खलारी। रांची जिले के खलारी, बुढ़मू में एसीसी को दिए गए माइनिंग लीज के नवीकरण का आवेदन निरस्त करने की मांग की गयी। इसे लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस लेबरसेल के महासचिव राजनसिंह राजा के अगुवाई में खलारी सीमेंट फैक्ट्री के सेवानिवृत्त कामगारों का एक प्रतिनिधिमंडल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोधकांत सहाय से मिला। सेवानिवृत सीमेंट कामगारों ने खलारी सीमेंट कारखाने की वर्तमान स्थिति और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। राजनसिंह राजा ने बताया कि एसीसी कंपनी के माइनिंग लीज के पहला नवीकरण 31 दिसंबर 1990 को समाप्त हो गया। इसके बाद से एसीसी कंपनी द्वारा दूसरे व तीसरे नवीकरण का आवेदन आज तक सरकार के पास लंबित है। खलारी में अब न तो कैप्टिव माइंस है न ही खलारी सीमेंट कारखाना में चूना पत्थर पकाने के लिए क्लिन बचा है। एसीसी को दिए गए लीज का प्रयोजन सीमेंट उत्पादन था।

मैथेमेटिक्स ओलंपियाड में संत माईकल के बच्चों का उम्दा प्रदर्शन

सिल्ली/मुरी। साइंस ओलिंपियाड फाउन्डेशन के द्वारा आयोजित मैथेमेटिक्स ओलिंपियाड परीक्षा में संत माईकल+2 स्कूल, मूरी के 60 बच्चो ने स्वर्ण पदक लाकर स्कूल का गौरव बढ़ाया। जिसमे कक्षा प्रथम से बारहवी तक के बच्चो ने भाग लिया था। विद्यालय प्रांगण में आज सभी विजेता बच्चों को स्वर्ण पदक एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। मौके पर स्कूल के निर्देशक राकेश कुमार ने सभी विजेता प्रतिभागियों को बधाई देते हुए कहा कि इस तरह के परीक्षा छात्र छात्राओ के स्वर्णिम विकास में सहायक होते हैं। उन्हें खुद को बेहतर साबित करने का मौका भी मिलता है। स्कूल के प्रधानाचार्य श्री सी. एल. प्रजापति ने कहे की जितना अधिक आप प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगे, उतनी ही अधिक आप अपने छिपी प्रतिभा को निखारेगे और आपको अधिक सफलता मिलेगी।

खेल से टीम भावना पैदा होती है : आशुतोष तिवारी

चान्हो। सिलागांई पंचायत के हुरहुरी गांव के होनहार खिलाड़ियों के बीच मंगलवार को जिला परिषद सदस्य आशुतोष तिवारी ने अपने आवास में फुटबॉल जर्सी का वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि खेल से न सिर्फ शारीरिक और मानसिक विकास होता है बल्कि टीम भावना भी जागृत होती है। जिससे हम अपने आसपास के लोगों से मिलकर रहते हैं। विकास के काम में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। साथ ही साथ एक दूसरे के सुख-दुख में भी शामिल होते है। आगे उन्होंने कहा कि हमारे क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। बस उन्हें उचित मौका मिले तो वह भी अपना नाम देश हो दुनिया में कर सकते हैं। ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने रोज देखने को मिल रहे हैं। उन्हें युवाओं में जोश भरते हुए कहा कि अपनी खेल प्रतिभा को आगे बढ़ते रहें मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूं जहां जरूरत पड़े मैं आप लोगों की मदद के लिए तैयार हूं। मौके पर अनिल साहु, मुन्ना पांडे, अनुज मिश्रा व हेमन्त दूबे समेत अन्य लोग भी शामिल थे।

मुखिया ने पीसीसी पथ का किया शिलान्यास

बेड़ो। बेड़ो प्रखंड के अंतर्गत हरिहरपुर जामटोली पंचायत के ग्राम भसनंदा में 15 वित्त मद की योजना के तहत पीसीसी सड़क का शिलान्यास किया गया। मुखिया लक्ष्मी कोया ने समाजसेवी सह मुखिया पति सुनील कच्छप से मिलकर 250 फीट पीसीसी पथ निर्माण का शिलान्यास किया गया । लंबे समय से गांव में पीसीसी पथ निर्माण के लिए ग्रामीणों के द्वारा मुखिया से मांग की जा रही थी। बाद में मुखिया लक्ष्मी कोया ने ग्रामीणों की समस्या के निदान के लिए पहल करते हुए अपने पति के साथ मिलकर योजना बनाई और 15 में वित्त मद से निर्माण कार्य की रूपरेखा तय की। लंबे समय के बाद सड़क का निर्माण की शिलान्यास कार्यक्रम से ग्रामीणों में खुशी की लहर है। इस मौके पर पूर्व मुखिया सुनील कच्छप , समाजसेवी लीला मुंडा ,धापा उराव, रसीद मीर,अजय गोप, विकास महतो अनिल पन्ना,वार्ड सदस्य प्रीति देवी शिवनारायण गोप, सैयद खान एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे।

न्यूज बॉक्स

मारवाड़ी युवा मंच रांची शाखा ने पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष की स्मृति में किया गौसेवा का आयोजन

रांची। मंगलवार रांची शाखा द्वारा सुबह 07:30 बजे पूर्व प्रांतीय अध्यक्ष स्वर्गीय विनय जालान के स्मृति में रांची गौशाला हरमू रोड में गौ सेवा का कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में गायों को गुड़, रोटी, हरि सब्जी एवं ताजी घांस खिलायी गयी साथ ही पक्षियों को दाना दिया गया। इस गौ सेवा कार्यक्रम के संयोजक स्व. विनय जालान के पुत्र श्रेय जालान एवं मंच के गौ सेवा प्रभारी कमलेश शर्मा एवं उज्ज्वल मुरारका मौजूद थे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शाखा अध्यक्ष आशीष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष स्पर्श चौधरी, पुर्व अध्यक्ष सुभाष पटवारी, स्वः विनय जालान जी की धर्मपत्नी सुमन जालान, दीपक जालान, विशाल महलका, अंकित टांटिया के साथ अन्य युवा सदस्य भी मौजूद थे।

प्रखंड स्तरीय बैठक में शामिल हुए डॉ परमेश्वर भगत

मांडर। प्रखंड के तिग्गा कॉम्प्लेक्स ब्रांबे में मांडर प्रखंड स्तरीय बैठक समाजसेवी शमीम अख़्तर आजाद की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई जिसमे मुख्य रूप पूर्व डीडीसी सह समाजसेवी डॉ परमेश्वर भगत शामिल हुए। बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए मांडर प्रखंड कमिटी का गठन किया गया। जिसमे सर्वसम्मति से जमाउद्दीन अंसारी को मांडर प्रखंड का प्रखंड प्रभारी बनाया गया। बैठक में विभिन्न पंचायत के पंचायत प्रभारी का गठन किया गया। जिसमे सुरसा पंचायत प्रभारी नेसार अख्तर, नसीम अंसारी, टिगोई अम्बा टोली पंचायत प्रभारी तहारत अंसारी, सकरा पंचायत प्रभारी मोद्दासिर हक, करगे पंचायत प्रभारी अंजर अंसारी, मलती पंचायत प्रभारी मो अली अंसारी, बरगड़ी पंचायत प्रभारी मंसूर आलम, कैंबो पंचायत प्रभारी नेजार अंसारी, नगड़ा पंचायत प्रभारी सईद अंसारी, ब्राम्बे पंचायत प्रभारी सुफियान अंसारी, मुरमा पंचायत प्रभारी अब्दुल मजीद एवं असलम अंसारी। बैठक के दौरान विभिन्न वक्ताओं ने बाहरी वक्ति को विधानसभा से भगाकर इस बार 2024 में स्थानीय माटी पुत्र डॉ परमेश्वर भगत के सिर ताज पहनाने का संकल्प लिया।

111वां श्री सुंदरकांड श्री हनुमान चालीसा पाठ संपन्न

रांची। कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ बज और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे के सुरताल से हरमू रोड का श्री श्याम मंदिर गूंज रहा था। अवसर था 111 वां श्री सुंदरकांड श्री हनुमान चालीसा के संगीतमय पाठ का हुआ आयोजन। श्री श्याम मित्र मंडल के द्वारा हरमू रोड के श्री श्याम मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को होने वाला 111 वां कार्यक्रम आज भक्तिमय माहौल में संपन्न हुआ। मुकेश बरनवाल राधा देवी बरनवाल ने परिवार के संग हनुमान जी महाराज की दिव्य अखंड पावन ज्योति प्रज्ज्वलित करके केसरिया पेड़ा गुड़ चना फल का प्रसाद अर्पित कर परिवार की खुशहाली की प्रार्थना की । मंडल के उपमंत्री अनिल नारनौली ने पूजन अनुष्ठान विधिवत संपन्न करवाया। श्रवण ढानढनियां ने चना प्रसाद की सेवा केसरिया पेड़ा सेवा पुष्पा देवी पोद्दार फल प्रसाद सेवा राजेश जयसवाल एवम गिरिगोला सेवा मुकेश मित्तल ने निवेदित की।

श्रमिक संगठनों को मजदूरों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा : ओमप्रकाश

खलारी। समय के साथ पदाधिकारियों को अपना कार्यशैली बदलना होगा और मजदूरों के प्रति जवाबदेह बनना पड़ेगा तभी हम लोग मिलकर श्रमिक संगठन के अस्तित्व को बचा पाएंगे। उक्त बातें जनता मजदूर संघ के सीसीएल सचिव ओमप्रकाश सिंह टीनू ने कही। वे मंगलवार को एनके एरिया वीआईपी क्लब में जनता मजदूर संघ द्वारा उद्योग के बदलते स्वरूप एवं श्रमजीवी वर्ग की आकांक्षा के बीच श्रमिक संघो की भूमिका विषय पर आयोजित कार्यशाला को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि समय के साथ अगर अपने-आप को नहीं बदलेंगे तो समय वैसे लोगों को श्रमिक संगठन की राजनीति से किनारा लगा देगी। वही संघ के सीसीएल अध्यक्ष कमलेशकुमार सिंह ने कहा कि आने वाला समय श्रमिक प्रतिनिधियों को राजनीतिक दल के नेताओं की तरह मजदूरों के प्रति उत्तरदायी बनना पड़ेगा। संगठन को भी जवाबदेह पदाधिकारी की आवश्यकता है जो मजदूर के भरोसे को जीतकर संगठन को आगे बढ़ाने की क्षमता रखता हो।

एलएडीसीएस अधिवक्ता राजेश सिन्हा ने सात वर्ष पुराना वैवाहिक वाद सुलझाया

नवीन मेल संवाददाता। रांची एलएडीसीएस के अधिवक्ता राजेश कुमार सिन्हा और आवेदक के अधिवक्ता सरिकन टोपनो के अथक प्रयास से प्री-लिटिगेशन वाद संख्या 185/2024 को समझौता कराकर सुलझा लिया गया। ज्ञात हो कि उक्त वाद में आवेदक ने एक आवेदन डालसा कार्यालय में अपनी पत्नी के विरूद्ध दायर किया था। आवेदन में उसने आरोप लगाया था कि पत्नी द्वारा गाली-गलौज, धक्का-मुक्की तथा कोई न कोई बहाना बनाकर आवेदक के परिवारवालों को अपमानित किया जाता है। बार-बार अपने मायके चली जाती थी और ससुराल में नहीं रहती थी। इस वाद को पांच बैठकों में सुलझा लिया गया। पत्नी राजी-खुशी से अपने पति के साथ ससुराल चली गई और अब किसी भी तरह का दोनों पक्षकारों के बीच मनमुटाव नहीं रहा। दोनों पक्षकार एक-दूसरे का मान-सम्मान तथा एक-दूसरे के परिवार का मान सम्मान रखने का पूरा दायित्व निभाएंगे। डालसा सचिव ने दोनों पक्षों को बधाई दी और आगे सुखमय वैवाहिक जीवन व्यतीत करने का आशीर्वाद दिया।

सिल्ली सीएचसी के एएनएम को मेडिकल किट दिया गया

सिल्ली/मुरी। हिंडालको इंडस्ट्रीज के सामुदायिक विकास प्रभाग की ओर से मंगलवार को सिल्ली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम (नर्सों) को एक मेडिकल किट का वितरण किया गया। कार्यक्रम में हिंडालको इकाई के हेड रोहित चौरसिया, सिल्ली प्रखंड विकास पदाधिकारी रेनू बाला, सिल्ली स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रियंका कुमारी, हिंडालको सीएसआर के हेड अनिल कुमार सिंह के द्वारा (नर्सों) को मेडिकल किट देकर सम्मानित किया गया। मेडिकल किट में बीपी मॉनिटर मशीन, मधुमेह टेस्टिंग मशीन, स्टेथोस्कोप, ऑक्सीमॉनिटर इत्यादि शामिल है। मौके पर बताया गया कि यह उपकरण अधिक योग्यताएं प्रदान करेंगे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोगी साबित होंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी और सामुदायिक अस्पताल के चिकित्सा प्रभारी ने बताया कि हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के द्वारा दिए गए उपहार के लिए हम बहुत ही आभारी हैं।

राम मनोहर लोहिया प्लस टू स्कूल में किया गया पौधरोपण

पिठोरिया। राम मनोहर लोहिया प्लस टू उच्च विद्यालय उमेडंडा परिसर में मंगलवार को पौधरोपण किया गया। पौधरोपण भाजपा के कार्यक्रम विभाग के प्रदेश संयोजक स्वामी देवेंद्र प्रकाश व अन्य अतिथियों ने किया। इस दौरान स्वामी देवेंद्र प्रकाश ने कहा कि समस्त विश्व को प्राकृतिक आपदा, ग्लोबल वार्मिंग व अन्य दुष्प्रभाव से बचाने का एकमात्र विकल्प पौधरोपण है। सभी से आग्रह करते हुए कहा कि सभी अपने घर के आसपास पौधरोपण करें, पौधे के बड़े होने तक देखभाल करें। इस मौके पर आम, कटहल और अमरूद का 102 पौधों को छात्रों व शिक्षकों के सहयोग से लगाया गया। पौधरोपण कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक डॉ अमरेंद्र कुमार, सुजीत कुमार केशरी, हीरा पासवान और बिंटु शाहदेव सहित विद्यालय परिवार के सदस्य मौजूद थे।

TATA
TATA STEEL

झारखण्ड सरकार
GOVERNMENT OF JHARKHAND

WORLD'S STRONGEST HOTEL BRAND 2024 2022 | 2021
TAJ
INDIA'S STRONGEST BRAND 2024 2023 | 2022 | 2020

भगवान बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क,
रांची में निर्मित
BILLION IMPRESSIONS
का उद्घाटन कार्यक्रम
24 जुलाई, 2024 | अपराह्न 12:30 बजे | भगवान बिरसा मुण्डा स्मृति पार्क, रांची

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार तथा
The Indian Hotels Company Ltd. (A TATA Enterprise) के बीच
ताज होटल के निर्माण हेतु
MoU हस्ताक्षर कार्यक्रम
24 जुलाई, 2024 | अपराह्न 01:30 बजे | प्रोजेक्ट भवन सभागार, धुर्वा, रांची

मुख्य अतिथि
श्री हेमन्त सोरेन
माननीय मुख्यमंत्री, झारखण्ड

विशिष्ट अतिथि
श्री हफीजुल हसन
माननीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, निबंधन विभाग, पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

श्री टी० वी० नरेन्द्रन
सी.ई.ओ. एण्ड एम.डी., टाटा स्टील

PR No. 330503 (Urban Development and Housing) 2024-25

नगर विकास एवं आवास विभाग, झारखण्ड सरकार

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का प्रथम बजट सीतारमण ने किया पेश

पवन कुमार सिंह
रामगढ़। 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्र सरकार का बजट पेश किया। उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में लगातार 7वीं बार बजट पेश किया। यह केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार का 13 वां बजट है। बजट में देश के गरीबों, महिलाओं, युवाओं किसानो पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में देश को वर्ष 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

एक ओर जहां सत्ता पक्ष की ओर से बजट को देश में विकास की रफ्तार बढ़ाने वाला करार दिया जा रहा है, वहीं, दूसरी ओर विपक्ष द्वारा बजट को किसान, मजदूर और युवा विरोधी और कॉरपोरेट घरानों के हित वाला बताया जा रहा है।

2047 तक भारत को विकसित बनाने पर जोर

पीएम गरीब कल्याण योजना को 5 वर्ष के लिए बढ़ाने की घोषणा

नौकरी और कौशल विकास पर 2 लाख करोड़ खर्च करने का एलान

महिलाओं और बालिकाओं के लिए 3 लाख करोड़ खर्च का प्रावधान

सत्ता पक्ष ने सराहा, तो विपक्ष ने बताया किसान मजदूर और युवा विरोधी

बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है : कुंटू बाबू

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य सह रामगढ़ विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रणंजय कुमार उर्फ कुंटू बाबू ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला और देश में विकास की गति को तेज करने वाला सिद्ध होगा। कहा कि बजट में देश के सभी वर्ग के हितों का पूरा ख्याल रखा गया है।

बजट कॉरपोरेट घरानों के हित वाला : सुधीर मंगलेश

दुलमी प्रखंड बीस सूत्री अध्यक्ष सुधीर मंगलेश ने बजट पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए इसे देश के कॉरपोरेट घरानो को लाभ पहुंचाने वाला और किसान, मजदूर, युवा और महिला विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा की बजट में देश के युवाओं पर बिलकुल भी फोकस नही किया गया है।

बजट से देश को विकसित बनाने में मिलेगी मदद : सूर्यवंश श्रीवास्तव

भाजपा कैंट मंडल अध्यक्ष सूर्यवंश श्रीवास्तव ने वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट की सराहना करते हुए इसे देश को विकसित बनाने की दिशा में एक बेहतर कदम बताया है। उन्होंने कहा की बजट में देश के किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरीपेशा सभी वर्गों का बेहतर तरीके से ख्याल रखा गया है। कहा की कुल मिलाकर बजट पूरी तरह से संतुलित है।

बजट किसान-मजदूर विरोधी : महेंद्र पाठक

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र पाठक ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे किसान, मजदूर, युवा और महिला विरोधी करार दिया है। उन्होंने कहा की बजट में सिर्फ देश के कॉरपोरेट घरानो का ख्याल रखा गया है। उन्होंने कहा कि बजट में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है और यहां के लोगों को ठगने का कार्य किया गया है। कहा कि किसानो को फसल बीमा का भुगतान नही हो रहा है।

देश को विकसित बनाने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा बजट : अमित साहू

फेडरेशन ऑफ झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्ट्रीज के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष अमित साहू ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश को विकसित बनाने की दिशा में मिल का पत्थर सिद्ध होगा। श्री साहू ने कहा कि बजट में देश कि किसानो, युवाओं और महिलाओं पर विशेष रूप से फोकस किया गया है। मुद्रा लोन को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रूपए करना युवाओं के रोजगार की दिशा में एक सार्थक पहल है। देश के कई राज्यों में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड जारी करने से किसनों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में मदद मिलेगी। महिलाओं के लिए बजट में 3 लाख करोड़ का प्रावधान है जो की सराहनीय है। यह देश में महिला सशक्तिकरण के लिए मिल का पत्थर सिद्ध होगा। सोलर एनर्जी के तहत देश के 1 करोड़ घरों में 300 यूनिट प्रति माह फ्री बिजली की घोषणा भी सराहनीय है। इस बजट महिलाओं को अधिक लाभ मिलने की संभावनाएं है, जो समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, महिलाएं विकसित होंगी तो देश विकसित होगा।

बजट देश को समृद्ध बनाने वाला: मनोज कुमार महतो

आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव मनोज कुमार महतो ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट की सराहना करते हुए इसे देश को समृद्ध बनाने वाला करार दिया है। उन्होंनं कहा की बजट में देश के किसान, मजदूर, युवाओं, महिलाओं सभी वर्ग का ख्याल रखा गया है। कहा कि बजट में युवाओं के लिए और भी प्रावधान होना चाहिए था। लेकिन जो हुआ वह बेहतर है। इसमें हर वर्ग का ध्यान रखते हुए बजट को पेश किया गया है। इस बजट से युवाओं को काफी सहुलियत होगी और देश समृद्ध की ओर बढ़ेगा। अगर बजट में किसी प्रकार की त्रुटियां या कमी होती है देश में अवरूद्ध पैदा होने लगेगी। इस बजट में मजदूरों का व किसानों का भी ख्याल अच्छी तरह से रखा गया है जो लाभ पहुंचने की संभावना है। अगर देश के किसानों को सहुलियत मिलेगी तो देश आगे की ओर बढ़ेगा और किसान भी स्वावलंबी बनेंगे। किसान ही देश के लिए सबसे बड़े अन्नदाता हैं और देश की उन्नति में उनका बहुत योगदान रहता है।

बजट से कर्मचारी खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं : डॉ सुनील

वित्त मंत्री द्वारा पेश बजट पर प्रतिक्रया व्यक्त करते हुए उत्क्रमित मध्य विद्यालय गोविंदपुर मांडू के प्रधापाध्यापक एवं पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश उप सचिव डॉ सुनील कुमार कश्यप ने कहा कि बजट में कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन लागू करने की दिशा में कोई भी घोषणा नहीं की गई है। जिससे कर्मचारी खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। बजट से लोगों में सुधार की संभावना ज्यादा होती है। जब बजट पेश होने के लिए होता है तो लोगों का ध्यान ज्यादा उसी ओर खिंचता है ताकि बजट में क्या आगे और क्या पेश किया जायेगा। लेकिन इसमें किसी तरह की कोई ऐसी चीज नहीं देखने को मिली रही है कि जो समाज के लिए ज्यादा फायदामंद हो। हालांकि लोगों को इससे काफी उम्मीद थी। लेकिन जब यह पेश किया गया तो लोगों में मायूसी देखी गयी, ताकि इसमें कुछ नहीं रखा गया है।

बजट किसान विरोधी : रमेश

झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी रमेश कुमार महतो ने कहा कि बजट पूरी तरह से किसान, मजदूर, युवा और महिला विरोधी है। उन्होंने कहा कि बजट में केवल कॉरपोरेट घरनों का ख्याल रखा गया है और किसान, मजदूर, युवा और महिलाओं के लिए इसमें बिलकुल भी फोकस नहीं किया गया है। केन्द्र सरकार बार-बार दावा करती है कि केन्द्र सरकार महिलाओं के लिए विशेष पैकेज दे रही है और किसानों को भी राहत दी जा रही है मगर यह सब कुछ बेकार की बातें हैं। इस बजट में कुछ नहीं मिला है इसी को लेकर किसानों में रोष देखा जा रहा है। किसानों का कहना है कि हमलोग रात दिन मेहनत करके अन्न उपजाते हैं और देश की तरक्की में हम किसानों का काफी योगदान होता है लेकिन केन्द्र ने सभी किसानों के उम्मीदों को चनाचूर कर दिया है जो किसानों के लिए चिंता का विषय है।

प्रमुख संघ झारखंड ने तीन सूत्री मांगों को लेकर राज्यपाल, मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

बरही । प्रमुख संघ झारखण्ड प्रदेश ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव को पंचायत समिति सदस्य, उप प्रमुख, प्रमुख की मांग पूरा करने के संबंध में मंत्री इरफान अंसारी को ज्ञापन सौपा है। बताया कि रांची राजभवन के सामने पंचायत समिति महासंघ झारखण्ड प्रदेश के बैनर तले प्रदेश अध्यक्ष सतेंद्र पांडेय उर्फ पिंकू पांडेय, प्रदेश महासचिव सन्तोष मंडल, कोषाध्यक्ष झारखण्ड प्रदेश कुमारी बिनीता, प्रदेश उपाध्यक्ष गीता मेहता के आह्वान पर पूरे झारखण्ड के सभी जिलों से प्रमुख, उप प्रमुख, पंचायत समिति सदस्यों की उपस्थिति में दिनांक 21 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया।झारखण्ड प्रदेश के सभी प्रखण्ड में सभी विभागों का कार्य प्रखण्ड की अध्यक्षता में निष्पादित किया जाए। प्रखण्ड स्तरीय स्थाई समिति को पूर्ण रूप से लागू किया जाए तथा पंचायत समिति सदस्यों को आय, जाति, आवासीय, जन्म, मृत्यु, वंशावली, आवास, सामाजिक पेंशन तथा अन्य सभी फॉर्म में पंचायत समिति सदस्य की हस्ताक्षर की मुख्य भूमिका दी जाए है। मौके पर बरही प्रखंड प्रमुख मनोज रजक भी मौजूद थे।

जेबीकेएसएस की बदलाव महासभा में उमड़ा जन सैलाब

बरकट्ठा। प्रखंड क्षेत्र के तुर्कबाद स्थित बाजार टांड में मंगलवार को जयराम महतो का भव्य स्वागत किया गया। वहीं जेबीकेएसएस के समर्थकों ने गाजेबाजे के साथ श्री महतो स्वागत किया। झारखंड में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनावी सरगर्मी तेज होती जा रही है। वहीं बरकट्ठा विधानसभा में चुनावी जंग में एक नई रंग भरने के लिए मंगलवार को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के सुप्रीमो जयराम महतो का आगमन बरकट्ठा में हुआ। इस निमित तुर्कबाद बाजार टांड में आयोजित विशाल बदलाव जनसभा को जयराम महतो संबोधित किया और झारखंड के माटी से जुड़े हुए झारखंडी जनमानस को अपने हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया। उन्होंने कहा कि झारखंड राज्य खनिज संपदा से भरी पड़ी है।

विधायक पर अश्लील टिप्पणी और बैनर पोस्टर पर साहू समाज ने जताया रोष

हजारीबाग। ओकनी साहू धर्मशाला में जिला अध्यक्ष के निर्देश पर जिला तैलिक समाज की एक बैठा के उपाध्यक्ष नारायण साहू (पंच मंदिर) के अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक का संचालन जिला महासचिव (ओरिया) नारायण साहू द्वारा किया गया। बैठक का मुख्य उदेश्य बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद पर अश्लील टिप्पणी और बैनर पोस्टर पर साहू समाज ने रोष जताया है। बड़कागांव के महुदी गांव में दो समुदायों के बीच उठे विवाद पर चर्चा की गई। साथ ही विधायक अंबा प्रसाद के विरुद्ध मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सामाजिक तत्वों और उन्मादी लोगों द्वारा अभद्र टिप्पणी कर व्यक्तिगत रूप से अपमानित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया। शरारती तत्वों द्वारा अश्लील बैनर पोस्टर के विरुद्ध साहू समाज ने कूकृतियों पर रोष जाताया और सर्वसम्मति से इस कुकृत्य के लिए घोर निंदा की है। बैठक में प्रशासन से या मांग की गई है कि विधायक द्वारा बड़कागांव थाने में दर्ज की के प्राथमिकता की गंभीरता एवं निष्पक्षता से जांच की जाए और दोषियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई किया जाए अन्यथा समाज वाद्य होकर चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करने की बात कही है। बैठक में बोधन साव, पोखन साव, रघुनंदन साव उर्फ बाबू जिला नगर अध्यक्ष ओमप्रकाश साहू विशेश्वर साव, मानकी साव, शीला देवी, कन्हाई साव, रामचंद्र साहू और सैकड़ो महिला पुरुष उपस्थित हुए।

अबुआ आवास मिल रहा है बबुआ को, गरीब परिवार को नहीं : दुलारी देवी

बरकट्ठा। प्रखंड क्षेत्र के पंचायत शिलाडीह में अबुआ आवास मिल रहा है बबुआ को, गरीब परिवार को नहीं। इस बाबत दुलारी देवी ,पति स्व0 बबलू टुडू ग्राम लगनवां, पंचायत शिलाडीह निवासी ने उपायुक्त को जनता दरबार में पत्र के माध्यम से अबुआ आवास को लेकर अपनी पीड़ा सुनाई है। जिसमें उन्होंने कहा है कि अबुआ आवास सूची में नाम जोड़ने के लिए जनता दरबार में आवेदन दी थी। जिसके बाद फाइनल सूची में नाम चढ़ गया। जिसका न0 70, एसीके न0 4578924 था। जिसके एक दिन बाद आवास जांच हेतु पंचायत सेवक गौरव सिंहा और एक बीएफटी मेरे घर पहुंचकर कहा कि अबुवा आवास के लिए तुम्हें 2लाख 50 हजार दिलवाएंगे इसके बदले 10 हजार की राशि देनी होगी। तभी फाइनल सूची में चढ़ा देंगे मैंने पैसे नहीं देने की आग्रह की। तत्पश्चात उन्होंने सूची से नाम गायब कर दिया। इस बाबत दुलारी देवी ने अपनी पीड़ा को पत्र के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड, मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग झारखंड सरकार, आयुक्त उत्तरी छोटा नागपुर को बताई है ।

मोदी सरकार के बजट का जदयू नेता ने किया स्वागत

हजारीबाग। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दिन मंगलवार को मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहला बजट पेश किया। जिसमें समाजसेवी सह जदयू नेता राकेश गुप्ता ने मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहला बजट पेश का प्रशंसा व्यक्त कर प्रतिक्रिया दिया एवं सहृदय स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट से हर वर्ग को लाभ मिलेगा। देश की अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी। तीसरे कार्यकाल की पहला बजट सकारात्मक एवं स्वागत योग्य है। देश का आर्थिक विकास और तीव्र गति से बढेगा। यह बजट सरकार की अपनी अब तक की उपलब्धियों और आगे के वर्षों के लिए अपने लक्ष्यों की एक झलक दिखाई है।

स्थायीकरण की मांग को लेकर मनरेगा कर्मियों का अनिश्चितकालीन धरना शुरू

कोडरमा। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मी संघ प्रदेश कमेटी के अहवाहन पर मनरेगा संघ जिला इकाई कोडरमा द्वारा सोमवार को जिला समाहरणालय परिसर में बेमियादी धरना शुरू हो गया। मनरेगा कर्मियों ने कहा कि झारखंड सरकार द्वारा मनरेगा कर्मियों के संविदा संवाद में किए गए आश्वासन के अंतर्गत स्थाईकरण करने का वादा हेमंत सरकार द्वारा किया गया था। लेकिन सरकार के कार्यकाल का साढ़े चार वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद भी स्थाईकरण के वायदे को अब तक पूर्ण नहीं किया गया है। राज्य में लगभग साढे पांच हजार मनरेगा कर्मी है, जिसमें बीपीओ एई, जेई, कंप्यूटर सहायक लेखा सहायक ग्राम रोजगार सेवक है।

भारत के समृद्ध भविष्य का सुनहरा बजट, सभी वर्गों का होगा उत्थान : मनीष जायसवाल

हजारीबाग। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नरेंद्र मोदी सरकार 3.0 का पहला आम बजट मंगलवार को पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल ने कहा की यह बजट 140 करोड़ भारतीयों की जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के साथ देश की अर्थव्यवस्था और आधारभूत ढांचा को मजबूती प्रदान करने वाला है। इसमें देश के गरीबों, किसानों, महिलाओं, युवाओं के साथ हर वर्ग के विकास और उत्थान का ध्यान रखा गया है। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि उन्नत बुनियादी ढांचे, नवाचार और अगली पीढ़ी के सुधारो के साथ एक समृद्ध भविष्य की ओर अग्रसर करते हुए समाज के हर वर्ग के विकास को इस बजट ने समाहित किया है।

उन्होंने कहा की यह गतिशीलता कृषि में उत्पादकता को बढ़ावा देने, रोजगार और कौशल को बढ़ाने और मानव संसाधन एवं सामाजिक न्याय को बढ़ाने का वादा करता है। यह शहरी विकास और ऊर्जा सुरक्षा में प्रगति को प्रेरित करता है।

अमीरों पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला है बजट : डॉ आरसी प्रसाद

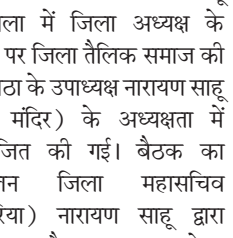

हजारीबाग। आटा और डाटा को महंगा किया गया है जिसे मैं भर्त्सना करता हूं यह बजट गरीबों किसानों बेरोजगारों छात्रों मध्यम व्यापारी वर्ग को हतोत्साहित करने वाला एवं अमीरों पूंजीपतियों को बढ़ावा देने वाला चुनावी जुमला नुमा बजट है यह बजट हतोत्साह का परिचायक है एवं 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने का कोशिश किया गया है ।

बजट में युवाओं को शिक्षा और रोजगार के लिए दिया विशेष उपहार : रंजन

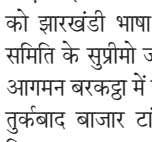

हजारीबाग। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से पेश किया। बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनीष जायसवाल से जुड़े रंजन चौधरी ने कहा की यह बजट गरीब, महिला, किसान और युवाओं को समर्पित है। बजट सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया है। रंजन चौधरी ने कहा की युवाओं को उनकी शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और रोजगार के लिए विशेष उपहार दिया गया है।

विकसित भारत के बजट में हर वर्ग का रखा विशेष ख्याल : शेफाली गुप्ता

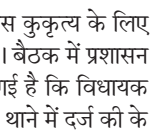

हजारीबाग। मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल की पहला बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में दिन मंगलवार को बजट पेश किया। संसद में पेश हुए आम बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा नेत्री शेफाली गुप्ता ने बताया कि मोदी सरकार की तीसरे कार्यकाल का पहला बजट 18वीं लोकसभा का बजट 2024-25 में विशेष रूप से अन्नदाताओं, महिलाओं की समृद्धि, युवाओं के रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान केंद्रित करने वाला बजट है।

पूर्व विधायक मनोज यादव के प्रयास से पंचमाधव में मिला ट्रांसफार्मर

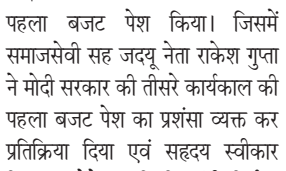

नवीन मेल संवाददाता। बरही प्रखंड के पंचमाधव पंचायत अंतर्गत ग्राम प्रजापति टोला में 24 घंटे के अंदर 63 केवीए का नया ट्रांसफार्मर पूर्व विधायक मनोज कुमार यादव के प्रयास से विभाग ने उपलब्ध कराया। मंगलवार को पूर्व विधायक मनोज यादव की उपस्थिति में मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र गोप के पंसस प्रतिनिधि कामेश्वर रविदास ने संयुक्त रूप से ट्रांसफार्मर का उद्घाटन किया। इस दौरान ग्रामीणों को सम्बोधित करते हुए पूर्व विधायक मनोज यादव ने कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान और उनके सुख-दुख में शामिल होकर हर वक्त उपलब्ध रहा हूं। जनसमस्याओं को लेकर मुखरता से हर वक्त उठाता रहा हूँ, ताकि लोगों को उनकी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करवा पाऊं। पूर्व विधायक ने कहा कि जनता के समस्याओं का समाधान और क्षेत्र का विकास उनकी पहली प्राथमिकता रही है। मौके पर मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र गोप, पंसस प्रतिनिधि कामेश्वर रविदास, पैकस अध्यक्ष सूर्यकांत राही, जानकी यादव, नागेश्वर गोप, चंद्र यादव, नीलम देवी, नीतु देवी, सिकंदर पंडित, अभिनंदन झा, जीतेन्द्र कुमार, मिथलेश यादव सहित सैकड़ो ग्रामीण उपस्थित थे।

मरकच्चो में कई ग्रामीण सड़कों की हालत जर्जर राहगीर परेशान

मरकच्चो। प्रखंड के जामू पंचायत अंतर्गत बिंडा से सिमरिया और पीडब्ल्यूडी रोड से हरलाडीह जाने वाली ग्रामीण सड़क की जर्जर हालत से ग्रामीण काफी परेशान हैं। सड़क की हालत खराब होने से स्कूल जाने वाले बच्चों को भी दिक्कतें होती हैं। साथ ही आये दिन दो पहिया वाहन दुर्घटनाग्रस्त होते रहते हैं। पंचायत की मुखिया नीता कुमारी ने उपायुक्त से मिल उन्हें ज्ञापन सौंप उक्त सड़क को बनवाने की मांग की है। ज्ञापन मे उन्होंने बताया है की मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के अंतर्गत बिंडा से सिमरिया भाया गोंडो अडवार तक सड़क का विशेष मरम्मत कार्य और पीडब्ल्यूडी रोड से हरलाडीह होते हुए नदी तक पथ का मरम्मत काम का टेंडर हो चुका है।

झारखंड में 12 दारोगा बनाए गए सिपाही

नवीन मेल संवाददाता। रांची

झारखंड सरकार ने 12 दारोगा को डिमोशन कर सिपाही बना दिया है। इसका आदेश गृह विभाग जारी कर दिया। प्रोन्नति पाए एक दारोगा अमरनाथ की मृत्यु पहले ही हो चुकी है। वे पलामू में पदस्थापित थे। आदेश के अनुसार 25 जनवरी, 2008 को 13 पुलिस कर्मियों को पारी से बाहर जाकर प्रोन्नति दी गई थी। तब सभी सिमडेगा जिला बल में पदस्थापित थे। सिमडेगा के बांसजोर ओपी पर 1/2 जनवरी, 2008 की रात में उग्रवादियों ने हमला किया था। इस हमले में इन

पुलिसकर्मियों ने साहस का परिचय देते हुए मुंहतोड़ जवाब दिया था। सिमडेगा एसपी ने इन पुलिसकर्मियों को पारी से बाहर जाकर प्रोन्नति देने की अनुशंसा की थी। प्रोन्नति आदेश जारी होने के बाद इसे झारखंड हाई कोर्ट में अरूण कुमार ने चुनौती दी थी। झारखंड हाई कोर्ट ने प्रोन्नति आदेश को रद्द कर दिया गया था।

सीएम के समक्ष होने वाले जन प्रदर्शन की तैयारी ग्राम स्तर पर तेज करें : विजय

नवीन मेल संवाददाता। सिमडेगा

झारखंड नवनिर्माण दल व ननबैंकिंग कंपनी पीड़ित मंच सिमडेगा के तत्वाधान में मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया।पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत दल के केंद्रीय नेता नील जस्टिन बेक व शिवचंद मांझी के संयुक्त नेतृत्व में सिमडेगा ब्लॉक से शहर में जुलूस निकालकर जमाकताओं ने सरकार को चेताते हुए कहा कि मेहनत का जमा पैसे की जल्द भुगतान नहीं हुई तो केंद्र व राज्य सरकार की खैर नहीं है ।जमाकताओं ने सहारा इंडिया, बेडो बैंक, साईं प्रकाश के अलावे दर्जनों विभिन्न ननबैंकिंग कंपनियों में जमा पैसे की सूद सहित भुगतान के लिए आंदोलन की शुरूआत कर दी है। इस मौके पर जुलूस व ब्लॉक मुख्यालय के समक्ष हुई सभा में शामिल झारखंड नवनिर्माण दल के केंद्रीय संयोजक विजय सिंह ने कहा कि जल्द भुगतान नहीं हुई तो 11 सितंबर 2024 को रांची में मुख्यमंत्री के समक्ष विशाल जन प्रदर्शन आयोजित की जाएगी । सहारा इंडिया सहित दर्जनों विभिन्न ननबैंकिंग कंपनियों में लोगों के मेहनत के पैसे की भुगतान की मांग को लेकर प्रखंडों में आंदोलन तेज करते हुए 11 सितंबर को रांची में होनेवाली मुख्यमंत्री के समक्ष जन प्रदर्शन में सिमडेगा से भी भारी संख्या में रांची चलने की तैयारी करने की बात कही है।

गावां उर्दू मध्य विद्यालय प्रबंधन समिति का चुनाव संपन्न

गिरिडीह। गावां उर्दू मध्य विद्यालय में ग्रामीणों के विरोध के बाद मंगलवार को पुनः प्रबंधन समिति का चुनाव कराया गया। चुनाव पर्यवेक्षक संतोष सिन्हा और धर्मजय कुमार के देखरेख में कराया गया। इस दौरान मो अलीमल्लाह को अध्यक्ष, मरियम खातून को संयोजिका के रूप में चुना गया। वहीं मो मुजफ्बर, मो शमशाद समेत 10 लोगों को सदस्य बनाया गया। गौरतलब है कि पूर्व में हुए प्रबंधन समिति के चुनाव में ग्रामीणों ने मनमानी और गोपनीय ढंग से चुनाव कराने का आरोप लगाया था। बाद में वार्ड सदस्य रेशमा परवीन के नेतृत्व में दर्जनों ग्रामीणों ने बीईईओ को लिखित आवेदन देकर पुनः चुनाव कराने की मांग की थी। इसपर अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी मामले को संज्ञान में लेते हुए बीईईओ से पुनः चुनाव कराने की मांग की। जिसपर बीईईओ ने पुनः चुनाव कराने का आदेश दिया था। जिसके तहत मंगलवार को स्थानीय ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों के मौजूदगी में चुनाव सम्पन्न कराया गया। मौके पर कांग्रेस नेता मरगूब आलम, वार्ड सदस्य रेशमा परवीन, शमशेर अली व बिलट्ठ खान समेत कई अभिभावक उपस्थित थे।

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय
भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल संख्या–2, राँची
अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या–16/2024–25

1.	विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता	:	कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, राँची।
2.	परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं समय	:	दिनांक 07.08.2024 को 1.00 बजे अपराह्न तक
3.	निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय	:	दिनांक 08.08.2024 का 3.00 बजे अपराह्न तक।
4.	निविदा खोलने की तिथि एवं समय	:	दिनांक 08.08.2024 को 3.30 बजे अपराह्न।
5.	परिमाण विपत्र बिकी का स्थान	:	1) अधीक्षण अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन अंचल सं0–2, राँची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा 2) कार्यपालक अभियन्ता,भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, राँची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा नगर नियंत्रण कक्ष राँची।
6.	निविदा प्राप्ति का स्थान	:	नगर नियंत्रण कक्ष राँची, कार्यपालक अभियन्ता, भवन निर्माण विभाग, भवन प्रमण्डल सं0–2, राँची के प्रतिनियुक्त पदाधिकारी द्वारा।
7.	निविदा खोलने का स्थान	:	अधोहस्ताक्षरी का कार्यालय
8.	कार्य की विवरणी	:	

क्र०	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रू०)	परिमाण विपत्र का मूल्य (रू०)	अग्रधन की राशि (रू०)	कार्य समाप्ति की अवधि।
1	Supplying and Installation of 50 Nos Additional Wi -Fi Routers at Ground to Second Floor of Advocate Blocks 1 & 2 at New High Court of Jharkhand at Dhurwa, Ranchi	4137800.00	5000.00	83000.00	1 Month
2	Renovation of CD type Qtr. No. -236 (Ground Floor) in Sector-3 at HEC, Dhurwa, Ranchi	597400.00	1250.00	12000.00	1 Month
3	Renovation of Room No.-123 (Department of Home, Jail & Disaster Management), 129 and 131 (Chief Secretary Office) at First Floor of Project Building at HEC, Dhurwa, Ranchi	1414100.00	2500.00	28500.00	1 Month

नोट :निविदा की शर्तें http://www.jharkhand.gov.in एवं कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखी जा सकती है।

कार्यपालक अभियन्ता
भवन निर्माण विभाग भवन प्रमण्डल संख्या–2, राँची

PR 330452 Building(24-25)D

आदिवासियों की अस्मिता और जीवन यापन के लिए जंगल का संरक्षण बेहद जरूरी

नवीन मेल संवाददाता। कोलेबिरा

कोलेबिरा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत शाहपुर पंचायत के कोंडेकेरा में कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोनगाड़ी ने आयोजित बैठक में भाग लिया।इस बैठक में विधायक ने उपस्थित सभी लोगों को जंगल की महत्ता को बताया और कहा कि जंगल एवं पर्यावरण की सुरक्षा और विकास के लिए माचा और शादी विवाह, पर्व त्योहारों में जंगलों से छोटे पेड़ या तोम्बा को ना काटे।इसके लिए विधायक ने जंगल किनारे के गांव वालों को टेंट और कनाथ का वितरण किया। उन्होंने कहा कि जंगल हमारे आदिवासी समाज के जीवन यापन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

मौके पर विधायक ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अभी भाजपा देश के लोगों को कह रही है कि सभी लोग पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक पेड़ अपनी मां के नाम पर लगाएं। वहीं दुसरी तरफ छत्तीसगढ़ के हसदेव जंगल को

अपने पूंजीपति मित्र अडानी को उजाड़ने के लिए दे रखी है। जिससे वहां के जमीन के नीचे रखे कोयला रूपी खजाने से लाभ कामवाया जा सके।ये बोलकर कि उस कोयला खदान के कोयले से बिजली रूपी ऊर्जा उत्पन्न हो।इसके अलावा विधायक ने अन्य मुद्दों के विषय पर भी लोगों को सम्बोधित किया।मौके पर जिला विधायक प्रतिनिधि सह अल्पसंख्यक जिलाध्यक्ष रावेल लकड़ा,प्रखंड अध्यक्ष सुलभ डुंगडुंग, मंडल अध्यक्ष राकेश कोनगाड़ी,कोलेबिरा बिधानसभा युवा अध्यक्ष अमृत डुंगडुंग,मंजू कुल्लु, उषा केरकेट्टा, अन्द्रियास कुल्लु, नीली ग्रेस सहित ग्रामवासी उपस्थित रहे।

समुची मानव जाति के चेहरे पर खुशी लाने का किया जा रहा है प्रयास : विधायक

भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जनता की एक ही मांग है, धर्म की राजनीति खत्म कर विकास की राजनीति हो और यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है

नवीन मेल संवाददाता। सिमडेगा

विधायक भूषण बाड़ा के कार्यशैली से प्रभावित होकर कुटमाकच्छार चारडीपा के कई भाजपा एवं अन्य पार्टी के कार्यकताओं ने मंगलवार को कांग्रेस पार्टी का सदस्यता ग्रहण किया। पार्टी में शामिल होने वाले सभी लोगों को विधायक भूषण बाड़ा, जिलाध्यक्ष डेविड तिर्की ने फुल माला पहना कर पार्टी में स्वागत किया। विधायक ने कहा कि भाजपा सिर्फ धर्म की राजनीति करती है। लेकिन जनता का एक ही मांग है, धर्म की राजनीति खत्म कर विकास की राजनीति हो और यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। इसी का नतीजा है कि

लोगों का मोह भाजपा से भंग हो रहा है। वहीं जिप सदस्य जोसिमा खाखा ने कहा कि कांग्रेस हर धर्म के लोगों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है।आज विधायक भूषण बाड़ा के कार्य से खुश होकर लोगों का रुझान कांग्रेस पार्टी की ओर बढ़ा है। वहीं जिलाध्यक्ष डेविड तिर्की ने कांग्रेस पार्टी के नीति सिद्धांतों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी सभी कार्यकताओं को पुरा सम्मान देने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता मंत्री, सांसद और विधायक है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के दोनों कांग्रेस के विधायक लगातार हर धर्म समुदाय के लोगों की सेवा करने में जुटे हैं। आज सिमडेगा जिला हर समुदाय कांग्रेस के दोनों विधायकों के कार्यकाल से काफी खुश हैं। मौके पर जिलाध्यक्ष डेविड तिर्की, जिप सदस्य समरोम पौल टोपनो, 20 सूत्री उपाध्यक्ष मनोज जायसवाल, प्रखंड अध्यक्ष अजीत लकड़ा, प्रखंड अध्यक्ष टेलेसफॉर टोप्पो,ज्योति लुगुन आदि उपस्थित थे।

रौतिया समाज ने तोरपा विधायक को सौंपा ज्ञापन

बानो। अखिल भारतीय रौतिया समाज विकास परिषद् के प्रदेश अध्यक्ष रोहित सिंह ने तोरपा विधायक कोचे मुण्डा से मुलाकात कर समाज के विभिन्न समस्याओं को लेकर मांग पत्र सौंपा।दिए ज्ञापन में रौतिया जाति को एस. टी में शामिल करने एवं रौतिया जाति का जमीन को को सी.एन.टी. एक्ट में शामिल करने को लेकर विधानसभा सत्र में पेश करने एवं सी.एन.टी. एक्ट में शामिल करने के लिए कहा है। मौके पर प्रदेश अध्यक्ष रोहित सिंह, जिला अध्यक्ष राजेश सिंह, प्रदेश मिडिया प्रभारी धरमबीर सिंह, प्रदेश सचिव सालिकगृम सिंह, कृष्णा सिंह, बसंत सिंह आदि लोग उपस्थित थे।

हंगामेदार रही तिसरी बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक

कस्तूरबा विद्यालय में नामांकन, मनरेगा में गड़बड़ी सहित कई मामलों को लेकर उठाया गया सवाल

नवीन मेल संवाददाता। गिरिडीह (तिसरी)

तिसरी प्रखंड सह अंचल कार्यालय में में मंगलवार को आयोजित बीस सूत्री क्रियान्वयन समिति की बैठक काफी हंगामेदार रही। बीस सूत्री अध्यक्ष मो। मुन्नीबुद्दीन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कस्तूरबा विद्यालय के नामांकन की जांच रिपोर्ट की मांग को लेकर सांसद व विधायक प्रतिनिधि, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनीष कुमार पर जमकर बिफरे।

बताया जाता है कि पिछले दिनों पंचायत समिति सदस्यों की बैठक में कस्तूरबा विद्यालय नामांकन में सरकारी मापदंडों को अनदेखा कर घालमेल करने का मामला प्रमुखता से उठाया गया था। जिसके बाद

प्रखंड स्तर से एक जांच टीम का गठन किया गया था। बैठक में सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव और विधायक प्रतिनिधि लक्ष्मण मोदी ने इसी जांच रिपोर्ट की मांग की लेकिन पदाधिकारियों द्वारा रिपोर्ट देने में आना - कानी की जाने लगी। जिसपर विधायक और सांसद प्रतिनिधि बीडीओ मनीष कुमार पर जमकर बिफरे और बैठक के दौरान ही बीडीओ पर सदन की गरिमा को समाप्त करने और गलत मानसिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।

काफी हंगामे के बाद बीडीओ मनीष कुमार ने बीईइओ रंजीत कुमार को जनप्रतिनिधियों के समक्ष जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की बात कही। बीस सूत्री अध्यक्ष ने कहा कि मनरेगा के एक भी वेंडर के पास मेटेरियल नहीं है जबकि वे कागजों पर ही मेटेरियल की पूर्ति करके 5 प्रतिशत कमीशन ले लेते हैं। सांसद प्रतिनिधि में कहा कि मनरेगा योजनाओं की आधे से ज्यादा राशि पदाधिकारीयों को चढ़ावा देने में चली जाती है। ऐसे में योजना धरातल पर कितना होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लिहाजा उन्होंने बीडीओ से इस पर ध्यान देने की बात कही।

दो बच्चियों को किया गया रेसक्यू

तिसरी। चाइल्डलाईन द्वारा मिले गुप्त सुचना के आधार पर सवेरा फाउंडेशन पर्यवेक्षक सह बाल अधिकार कार्यकर्ता इंकज कुमार के नेतृत्व व तिसरी पुलिस के सहयोग से ट्रैफिकिंग के लिए ले जाए जा रहे दोनों नाबालिग बच्चियों को तिसरी चौक से रेसक्यू कर लिया गया है। दोनों नाबालिग बच्चियां लोकाय थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली हैं। बताया जाता है कि सफेद रंग की एक कार में उक्त दोनों नाबालिग बच्चियों को ले जाया जा रहा था, जिसमें दो पुरुष और एक महिला थी। बाल अधिकार कार्यकर्ता इंकज कुमार ने लगभग 10 कि मी। तक बाईक से उनका पीछा किया। इस दौरान शक होने पर कार चालक ने कई बार रूट डाइवर्ट कर उन्हें चकमा देने की भी कोशिश की लेकिन इंकज ने अपनी सूझ - बुझ से लगातार उनका पीछा किया और इसकी सुचना तिसरी का थाना प्रभारी संजय नायक को दी।

ग्रामीण क्षेत्र के लोगों में बजट की समझ

गुलाम अहमद रजा

भारत आज भी कृषि प्रधान देश है। भारतवासी अब भी प्रत्यक्ष या आप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। फार्मिंग से लेकर फैक्टरियाँ तक कृषि पर आश्रित हैं। यहाँ की एकोनॉमी की निर्भरता ग्रामीण इलाकों में खट रहे मजदूरों एवं किसानों पर है। ऐसे में बजट ग्रामीण इलाकों के लिए और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है।

देश की संसद में बजट पेश हो चुका है। दिल्ली की राजनीति का असर कश्मीर से कन्याकुमारी तक नजर आ रहा है। अखबारों और न्यूज चैनलों पर इसे लेकर लेख और डिबेट प्रसारित किए जा रहे हैं। अलग-अलग विचार के लोग इसपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। वहीं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग भी अपनी पार्टी द्वारा दिए गए निदेर्शों का पालन करते हुए भी इसके फायदे और नुकसान गिना रहे हैं। इनलोगों के हिसाब से बजट से सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि हम भारत के लोगों को इससे क्या मिला? अकसरियत आबादी को इससे आम जिंदगी में फायदा मिला या नहीं? हालांकि मुख्य मुद्दा तो यह होना चाहिए कि भारत के लोगों को बजट की समझ है भी या नहीं! चूंकि भारत कृषि प्रधान देश है तो बजट का सबसे अधिक असर ग्रामीण इलाकों के लोगों पर पड़ना है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रामीण इलाकों में बजट की समझ कितनी है? भारत में शिक्षा व्यवस्था अभी भी निम्न स्तर पर है। सुदूर क्षेत्र के लोगों को अपना नाम तक लिखना नहीं आता। ऐसे में बजट की समझ मुमकिन ही नहीं। बस प्रेस के माध्यम से जो पढ़ने-सुनने को मिला उसी से खुश या दुखी हो जाते हैं। झारखंड में भी कमोबेश यही हाल है। यहां के विश्वविद्यालय महज डिग्रियाँ बांटने की मशीन बन कर रह गईं हैं। इस शिक्षा व्यवस्था से भले ही रोजगार मिल जाए परंतु आम जिंदगी में आने वाले काम का ज्ञान नहीं मिल पाता। बजट भी इसमे शामिल है। बड़े-बड़े कॉर्पोरेट और सरकारी कंपनियों में काम करने वाले पढे लिखे लोगों को भी बजट का समझ नहीं हो पाना इसका सीधा उधाहरण है। जब डॉक्टर, इंजीनियर, डायरेक्टर, कलाकार आदि जैसे लोगों को बजट के नाम पर सिर्फ सुनी सुनाई बातें ही पता हो तो यह कल्पना भी नहीं किया जा सकता कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसकी समझ हो। ग्रामीण लोगों में बजट की समझ नील बटे सन्नाटा है।

बजट का समझ से परे होने के कई कारण हो सकते हैं। इसमें बजट कि लेखन शैली का कानूनी भाषा में होना, अतिशुद्ध हिन्दी या अंग्रेजी में होना, आम भाषा का उपयोग नहीं होना मुख्य है। वहीं प्रचार प्रसार में कमी भी अहम भूमिका निभाता है। ऐसे में प्रेस की भूमिका भी काफी अहम हो जाती है। प्रजा और सरकार के बीच संचार में अहम भूमिका निभाने वाली प्रेस ही एकमात्र उपाय है बजट को लोगों तक पहुंचाने की। इसके लिए सरकार को भी कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है। महज सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बजट के क्लिप और गजट की प्रति को प्रसारित करने तक ही सरकार को सीमित नहीं रहना चाहिए।

देश के हर एक नागरिक तक बजट को पहुंचाना सरकार की जिम्मेदारी है। इस कार्य में आजतक सभी सरकारें विफल रही हैं। सरकार को शिक्षा व्यवस्था में ऐसे बदलाव लाने चाहिए जिससे हर एक नागरिक कानूनी भाषा को समझ पाने में समर्थ हो जाए। इससे न सिर्फ लोग बजट को ही समझ पाएंगे बल्कि संविधान और कानून को भी समझने में सक्षम हो जाएंगे। कानून की समझ होने से क्राइम रेट पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा, लोग जागरूक हो जाएंगे। शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ सरकार प्रेस के माध्यम से आसान भाषा का उपयोग करते हुए विज्ञापनों का सहारा लेकर बजट को लोगों तक पहुंचा सकती है। अपने कामों का बखान करने वाले विज्ञापनों के साथ सरकार को जनहित विज्ञापनों की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहिए।

Government of Jharkhand
JHARKHAND FLYING INSTITUTE
(A Society Registered under Dept. of Cabinet Secretariat and Vigilance (Civil Aviation Division), Jharkhand
STATE HANGAR, BIRSA MUNDA AIRPORT ROAD, HINOO, RANCHI-2
Email – jfi.govtfly@gmail.com Telefax:- 0651-2250319, 2251090

Notice for Expression of Interest
EoI Ref. No.- EoI Aircraft Spares-37/2024/JFI/171
Date:- 23.07.2024
Inviting Expression of Interest (EoI) for the empanelment of Agency/Firm For Supply of Aircraft Spares, Lubricants and Rotables for Jharkhand Flying Institute.

1.	EoI Ref. No.	EoI Aircraft Spares-37/2024/JFI/ 171 Dated-23/07/2024
2.	Name of Work	For the empanelment of Agencies/Firms for the supply of Aircraft Spares, Lubricants and Rotables for Jharkhand Flying Institute (JFI)
3.	Pre Bid Meeting	30/07/2024 at 11:30 AM
4.	Start of Submission of EoI	01/08/2024
5.	Last date for submission of EoI	16/08/2024 up to 05:00 PM
6.	Opening of EoI	20/08/2024 up to 11:30 AM
7.	Officer Inviting EoI	Managing Director, Jharkhand Flying Institute, Govt. of Jharkhand
8.	Officer Name/Mob. No. for further inquiry	Mr. Rathour Nitant K. Singh, Section Officer Mob. No. 9472749978, E-Mail- jfi.govtfly@gmail.com

For Details, the interested Agencies/Firms are requested to visit the IPRD Website http://www.prdjharkhand.in/iprd for proposal and details of EOI.

The Agencies/Firms fulfilling the eligibility criteria may send their proposal with relevant supporting documents through speed post/ courier/ by hand, latest by 16/08/2024 at 05:00 PM to the office of Managing Director, Jharkhand Flying Institute, Civil Aviation Division, State Hangar, Birsa Munda Airport Road, Hinoo, Ranchi-834002.

Jharkhand Flying Institute reserves the right to accept or reject any or all EoI without assigning any reason. JFI also reserves the right to call off the process of empanalment at any stage without assigning any reason.

Sd/-
Managing Director
Jharkhand Flying Institute

PR.NO.330496 Civil Aviation(24-25):D

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय,
ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग
ई–अति अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना
ई–निविदा सं0 :–03/RE/2024-25/RWD/EE/HAZARIBAG दिनांक :– 22.07.2024

कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है ।

1.कार्य की विवरणी :–

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	प्रखण्ड	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपया में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की अवधि	कॉल
1	RWD/HAZ/STPKG/01/2024-25	बड़कागॉव	सी0सी0एल0 उरीमारी चेक पोस्ट से तिलैया तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल0–2.300 कि0मी0)	12,85,12,200/-	बारह करोड़ पचासी लाख बारह हजार दो सौ रुपये मात्र	15 (पन्द्रह) माह	द्वितीय
		बड़कागॉव	डारी मोड़ से मंझली डारी तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल0–1.860 कि0मी0)				
		बड़कागॉव	पुन्दोल से मरदुसाती तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल0–2.020 कि0मी0)				
		बड़कागॉव	टी02 से सुकुल खपिया तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल0–2.800 कि0मी0)				
		केरेडारी	पतरा से कण्डाबेर तक पथ का सुदृढ़ीकरण कार्य (ल0–7.500 कि0मी0)				

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि :–29.07.2024
3. ई–निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय :–07.08.2024 अपराह्न 5.00 बजे तक ।
4. निविदा खोलने की, तिथि, एवं समय–08.08.2024 अपराह्न 5.30 बजे।
5. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का पदनाम एवं पता :–कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग ।
6. ई–निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0–06546–265286 ।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है ।

कार्यपालक अभियंता,
ग्रामीण कार्य विभाग,कार्य प्रमण्डल, हजारीबाग

PR 330485 Rural Work Department(24-25).D

कार्यालय: जिला मत्स्य कार्यालय, सिमडेगा।
आवेदन आमंत्रण सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि सिमडेगा जिला में वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्यादेश सं0–05 रा0(वि0), दिनांक– 13.06.2024 के आलोक में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत निम्नलिखित योजना ओंका लक्ष्य प्राप्त है एवं जिसके आलोक में निम्नांकित योजनाओं हेतु लाभुकों का चयन किया जाना है। अतः निम्न योजनाओं हेतु आवेदन आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	योजना का नाम	इकाई	लघु शीर्ष	भौतिक लक्ष्य	इकाई अनुमान्य अनुदान	लाभुक का अंशदान	चयन हेतु अर्हताएँ
1	केज मत्स्य पालकों हेतु लाईफ जैकेट	सं0में	796	50	अधिकतम 1815/– रू	25 प्रतिशत अथवा605/– रू0 (इकाई लागत का)	1. केजमत्स्य पालक होजिनके द्वारा वर्त्तमान मेंमछलीपालन किया जा रहा हो। 2. लाभुक द्वारा अपना अंष दान लगाने हेतु लिखित सहमति देनाहोगा। 3. विगत वर्षों का केज मेंमछली उत्पादन काआँकड़ा लिखित रूप मेंआवेदन के साथ संलग्न करनाहोगा। 4. सरकार का अंषदान 75प्रतिषत् (1815/–रू0 देय होगा एवं शेष अंषदान 25 प्रतिषत लामुक द्वारा वहनकिया जाएगा।)
2	निजी क्षेत्र में महाझींगा पालन	एकड़ में	796	6	अधिकतम 128000/– रू0 (प्रति एकड़)		1. आवेदक मत्स्य पालनसेजुड़ाहो। 2. अपनानिजी 1 एकड़ एकड़ जलक्षेत्र का सदाबहार तालाबहो। 3. ST/SC/एवं महिलावर्ग के लिए राज्य सरकार का अंषदान 128000/– रू0 प्रति एकड़ होगा शेष अंषदान लामुक द्वारा वहन किया जाएगा।
3	पुरस्कार/ सम्मान	सं0 में	796	2	अधिकतम 30000/– रू0		उत्कृष्ट मत्स्य पालकों, मत्स्य बीज उत्पादकों तथा हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार स्वरूप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राषि 30000/– रू0 प्रतिचयनित कृषक पुरस्कार के रूप में 12 Paddle Wheel Aerator (विभाग द्वारा अनुमोदित) अथवा मत्स्य बीज पैकेजिंग हेतु ऑक्सीजन सिलिन्डर (Accessories सहित) के क्रय हेतु प्रोत्साहनराषि उनके बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से दी जायेगी।
4	मत्स्य कृषकों की गोष्ठी	–	796 789	650 40	–	–	इच्छुक मत्स्य कृषक पंचायत/ प्रखण्ड स्तर परमत्स्य कृषक गोष्ठी हेतु स्थल एवं वांछित विवरणी के साथ कार्यालय में संपर्क करें।
5	जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए I. Card	सं0 में	796	20	–	–	जलाषयों में मत्स्य शिकार माही करने वाले मछुआरे वांछित कागजातों के साथ अपना निबंधन कराने हेतु आवेदन समर्पित कर सकते है।
6	मत्स्य बीजउत्पादकोंको 03 दिवसीय प्रषिक्षण	सं0 में	796 789	190 20	–	–	सभी इच्छुक मत्स्य कृषक प्रषिक्षण हेतु जिलामत्स्य कार्यालय, सिमडेगा में संपर्क करें।
7	मत्स्य बीजउत्पादकों/ मत्स्य कृषकोंआदिको 01 से 01 दिवसीय कार्यषाला/सेमिनार	सं0 में	796 789	50 15	–	–	
8	05 दिवसीय प्रषिक्षण/विषय आधारितप्रषिक्षण	सं0 में	796 789	190 35	–	–	
9	नयेरंगीनमछलीपालन	सं0 में	796	02	–	–	नये रंगीन मछली पालन हेतु पूरक सामग्री आपूर्ति की जाएगी इसहेतु कार्यालय में आवेदन समर्पित कर सकते हैं।

नोट:–एतद् द्वारा उक्त तालिका में दिए गए विवरणों के आलोक मेंसिमडेगा जिला के ऐसेमत्स्य पालकों से जो आवेदनकरने की अहर्ता रखतेहैं एंव आवेदित कार्यक्रम के क्रियान्वयन में अंशदान लगाने में सक्षमहै, उनसे आवेदन आमंत्रित किया जाताहै।
आवेदन जमा करनेकी अंतिम तिथि :–01.08.2024
आवेदन जमा करने का स्थान :–जिलामत्स्य कार्यालय, सिमडेगा।
आवेदन प्रपत्र जिलामत्स्य कार्यालय, सिमडेगा में निःशुल्क प्राप्त किया जा सकताहै।
संबंधित जानकारी एवं आवेदनप्रपत्र जिला के वेबसाईट www.simdega.nic.inij भी देखा जा सकताहै।

जिलामत्स्य पदाधिकारी,
सिमडेगा।

PR 330441 Fish(24-25)D

हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि ख़ुशी जीवन की यात्रा का एक तरीका है, न कि जीवन की मंजिल। - रॉय गुडमैन

आम बजट और भारत का आम आदमी

मोदी 3.0 सरकार का बजट आज संसद में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और पक्ष और विपक्ष ने भारत के आम नागरिकों के हितों की बात जोर शोर से उठाई पर क्या रोजी रोटी की दौड़ में लगा एक औसत भारतीय बजट का मतलब समझता है? सामान्य पढ़े-लिखे आदमी के लिए भी इसे समझना टेढ़ी खीर होता है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बोजेत से बना है। इसका अर्थ होता है छोटा बैग। फ्रेंच भाषा में यह शब्द लैटिन शब्द 'बुल्गा' से लिया गया है। इसका अर्थ है 'चमड़े का थैला'। प्राचीन समय में बड़े व्यापारी अपने सारे मौद्रिक दस्तावेज एक थैले में रखते थे। इसी तरह धीरे-धीरे इस शब्द का प्रयोग संसाधनों को जुटाने के लिए किए गए हिसाब-किताब से जुड़ गया। इस तरह सरकारों के साल भर के आर्थिक बही-खाते को नाम मिला 'बजट'। सरकार द्वारा देश का आय-व्यय लेखाजोखा पेश करने की शुरुआत ब्रिटेन से हुई थी। ब्रिटेन के वित्त मंत्री संसद में जब आय-व्यय का लेखाजोखा पेश करने आते तो संबद्ध दस्तावेज चमड़े के एक लाल बैग में रखकर लाते। उस बैग को फ्रेंच में 'बजेटी' कहा जाता था, जो अंग्रेजी में भाषांतर करते समय 'बजट' हो गया। सरकार की कुल आय और व्यय में अंतर को आर्थिक शब्दावली में 'राजकोषीय घाटा' कहा जाता है। इससे इस बात की जानकारी होती है कि सरकार को कामकाज चलाने के लिए कितने उधार की जरूरत होगी। कुल राजस्व का हिसाब-किताब लगाने में उधार को शामिल नहीं किया जाता है। यानी, सरकार के खर्च और आमदनी के अंतर को वित्तीय घाटा या बजटीय घाटा कहा जाता है। चालू खाता घाटा जब किसी देश की वस्तुओं, सेवाओं और ट्रांसफर का आयात इनके निर्यात से ज्यादा हो जाता है, तब चालू खाते घाटा की स्थिति पैदा होता है। यानी, जब भारत में बनी चीजों और सेवाओं का बाहर निर्यात होता है तो इससे भुगतान हासिल होता है। दूसरी ओर, जब कोई भी वस्तु या सर्विस आयात की जाती है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इस तरह, देश में प्राप्त भुगतान और बाहरी देशों को चुकाई गई कीमत में जो अंतर आता है वह चालू खाता घाटा कहलाता है। सरकारी राजस्व व व्यय सरकारी राजस्व सरकार को उसके सभी स्त्रोतों से होने वाली आमदनी होता है। इसके विपरीत सरकार जिन-जिन मदों में खर्च करती है उसे सरकारी व्यय कहते हैं। यह सरकार की वित्तीय नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। वित्तमंत्री संसद में बजट प्रस्ताव रखते हुए विभिन्न तरह के कर और शुल्क के माध्यम से होने वाली आमदनी और योजनाओं व अन्य तरह के खर्चों का लेखा पेश करती हैं, उसे आमतौर पर बजट आकलन कहा जाता है। वित्त विधेयक के माध्यम से ही आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री सरकारी आमदनी बढ़ाने के विचार से नए करों आदि का प्रस्ताव करते हैं। इसके साथ ही वित्त विधेयक में मौजूदा कर प्रणाली में किसी तरह का संशोधन आदि को प्रस्तावित किया जाता है। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही इसे लागू किया जाता है।

> बजट देश की आय एवं व्यय का लेखा-जोखा है, इसमें नए करों आदि का प्रस्ताव भी होता है, संसद से मंजूरी के बाद यह लागू होता है

इस बजट से देश के आर्थिक विकास को नई गति मिलेगी

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण में बहुत ही शानदार बजट प्रस्तुत किया है। बजट के प्रावधानों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि इससे हर वर्ग के लोग लाभान्वित होंगे। इस बजट से देश के आर्थिक विकास को एक गति मिलेगी। बजट में शहरी एवं ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के समुचित विकास पर ध्यान दिया है। देश की आजादी के बाद शहरों के विकास को गति मिलती रही। वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जिस गति से विकास होना चाहिए, नहीं हो पाया है। इसका प्रतिकुल असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ा। सर्वविदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश के रूप में जाना जाता रहा है। अगर आजादी के बाद से कृषि विकास आधारित बजट में प्रावधान होते तो आज भारत की स्थिति कुछ और होती। नरेंद्र मोदी सरकार का तीसरा टर्म है। तीसरे टर्म का यह पहला बजट अन्य बजटों की तुलना में काफी श्रेष्यकर और सूझबूझ के साथ बनाया गया है।

प्रस्तुत बजट शहरी आवास, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि के विकास पर फोकस है। बजट की खासियत यह है कि रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया गया है। बजट में रोजगार सृजन के लिए दो लाख करोड रुपए का प्रावधान किया गया है। शहरी आवास के लिए 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कृषि क्षेत्र के विकास के लिए 1. 52 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। देश में बेरोजगारी एक भीषण समस्या के रूप में हमारे सामने है। नरेंद्र मोदी सरकार बीते चुनाव में यह घोषणा की थी कि बेरोजगारों को नौकरी दी जाएगी। बजट में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर बेरोजगारों को एक तरह से तोहफा देने का काम किया गया है। रोजगार सृजन के क्षेत्र में 2 लाख करोड़ रुपए की राशि एक बड़ी राशि होती है। देश में जिस तरह बेरोजगारी बढ़ी हुई है, दो लाख करोड़ रुपए की राशि काम जरूर है, लेकिन देश में रोजगार सृजन के लिए सार्थक कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट के बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर कहा कि यह हर वर्ग को समृद्द करने वाला बजट है। इस बजट से आर्थिक विकास को नई गति मिलेगा। हम भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। यह बजट समाज के हर वर्ग को शक्ति देने वाला और उद्योगो को प्रगति के नए रास्ते प्रदान करेगा। यह अनगिनत नए अवसर वाला बजट है। इससे महिलाओं में भागीदारी सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट पर बहुत ही गंभीरता के साथ अपना वक्तव्य जारी किया है। उन्होंने कहा कि प्रस्तुत बजट से आर्थिक विकास को गति मिलेगी। वर्ष 2019-20 विश्व महामारी कोरोना के कारण विश्व भर में आर्थिक मंदी आई थी। इस आर्थिक मंदी का प्रभाव भारत पर भी पड़ा था। प्रस्तुत बजट से ऐसा प्रतीत होता है कि देश के आर्थिक विकास में गति मिलेगी। देश आर्थिक रूप से संपन्न होगा, तभी देश के हर क्षेत्र में विकास दिखेगा। यह इस बजट की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। राजकोषीय घाटा एक ऐसा घाटा है, इस घाटे को भरने में देश की बड़ी पूंजी चली जाती है। देश की आजादी के बाद लगातार राजकोषीय घाटा बढ़ता ही चला गया। फलस्वरुप विश्व बैंक सहित कई अन्य देशों का कर्ज भारत पर लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। देश की आजादी के बाद कई सरकारी आई और कई सरकारी गई। लेकिन राजकीय घाटा कम नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले टर्म से ही राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए बजट में कई उपाय किए। फलस्वरूप अब उसकी तस्वीर उनके तीसरे टर्म में देखने को मिल रही है। बजट के प्रावधानों से प्रतीत होता है कि राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए भारत सरकार कृत संकल्पित है। उम्मीद है 2040 से 45 के बीच देश का राजकोषीय घाटा न्यूनतम स्तर पर होगा। वहीं से भारत एक विकासशील देश की परिधि से बाहर निकल कर एक विकसित देश के रूप में तब्दील हो पाएगा। देश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन बसर कर रहे लोगों को इस बजट से काफी लाभ मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में विकास की गति को बढ़ाए जाने से मजदूरों को ज्यादा काम मिल पाएगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे गरीबी रेखा की परिधि से ऊपर उठ पाएंगे। भारत में बढ़ती महंगाई एक भीषण समस्या के रूप में हमारे सामने है। देश में कम होते रोजगार और ऊपर से बढ़ती महंगाई से लोग परेशान है। प्रस्तुत बजट से महंगाई पर अंकुश लगेगी। देश के लोगों का प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। रोजगार के सृजन से देश का हर परिवार आर्थिक रूप से संपन्न होगा। इसका भारतीय बाजार पर बहुत ही अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। विश्व में आई आर्थिक मंदी के बावजूद भारतीय बाजार ठीक चल रहा है। विश्व आर्थिक मंदी का कोई प्रभाव भारतीय बाजार में देखने को नहीं मिलता है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी हुई है। प्रस्तुत बजट से प्रति व्यक्ति आय में भी काफी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जो भारत के लिए शुभ संकेत है। प्रस्तुत बजट में महिलाओं के चतुर्दिक विकास पर भी ध्यान दिया गया है। नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे टर्म में महिलाओं को पुरुषों के समक्ष बराबरी का दर्जा देने के लिए महिला बिल पारित कर अपने धर्म का निर्वाह किया। दो से तीन वर्षों में महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने वाला बिल अस्तित्व में भी आ जाएगा। ऐसे में महिलाओं को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए बजट में जो राशि आवंटित की गई है, महिला उत्थान की दिशा में एक कारगर कदम सिद्ध होगा। देश में आधा से ज्यादा आबादी 35 वर्ष के उम्र के लोगों की है। यह देश के लिए एक अच्छी खबर है। युवाओं के चतुर्दिक के विकास के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। *(यह लेखक के निजी विचार हैं)*

आज की बात

विजय केसरी
(कथाकार/स्तंभकार)

आपकी बात

क्यों सरदार पटेल की सीख से पूजा खेडकर रहीं दूर

आर.के. सिन्हा

लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल ने 21 अप्रैल, 1947 को राजधानी के मेटकॉफ हाउस में आजाद होने जा रहे भारत के पहले बैच के आईसीएस जो 1948 से आईपीएस कहलाये ऐसे सभी अफसरों को संबोधित करते हुए कहा था कि "उन्हें स्वतंत्र भारत में जनता के सवालों को लेकर गंभीरता और सहानुभूति का भाव रखना होगा। उन्हें अपने दायित्वों का निर्वाह ईमानदारी से करना होगा।" सरदार पटेल ने उन्हें स्वराज और सुराज का अंतर भी समझाया था। जाहिर है, उनका ईमानदारी से आशय यही रहा होगा कि वे अपने जीवन के हर क्षेत्र में शुचिता और तटस्थता का पालन करेंगे। पर हाल में आईएएस प्रोबेशनर पूजा खेडकर मामले को गहराई से देखने से समझ आ रहा है कि कुछ शातिर तत्व आईएएस या अन्य सरकारी नौकरियों को पाने के लिए फर्जी प्रमाणपत्र भी सौंपते हैं। उनके लिए ईमानदारी का कोई मतलब नहीं है। उनका सरदार पटेल की सीख से भी कोई लेना-देना नहीं। पूजा खेडकर मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में प्रशिक्षण ले रही थीं। उन्हें महाराष्ट्र, शायद उनके अपने राज्य कैडर, में जिला प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। उन्हें एहसास नहीं था कि आईएएस अफसर बनने का मतलब जनसेवा होता है। इसके बजाय, उसने इस पद को हासिल करने के बाद अपनी झूठी शान दिखानी शुरू कर दी। उसने कार, सुसज्जित कार्यालय और कर्मचारियों जैसी कई सुविधाओं की मांग की। चूंकि प्रोबेशनर्स इन लाभों के हकदार नहीं होते हैं, इसलिए उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया गया। इसलिए, उसने अपनी दैनिक जरूरतों के लिए एक लग्जरी कार 'किराए पर' ली। इससे भी बुरा यह है कि उन्होंने कार की छत पर नीली बीकन लाइट भी लगाई। बीकन लाइट के इस्तेमाल को लेकर नियम हैं कि हर कोई ऐसी लाइट नहीं लगा सकता, जिसके कार्यात्मक उद्देश्य आवश्यक नहीं हैं। एम्बुलेंस वाहन पर ऐसी लाइट वाहन की तेज गति को सुविधाजनक बनाने के लिए होती है। पूजा का चयन दो विशेष श्रेणियों के तहत किया गया था। एक, वह ओबीसी के गैर-क्रीमी वर्ग से संबंधित हैं। यह स्वयं ही संदिग्ध है, यह देखते हुए कि उनके पिता एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी थे। फिर वह गैर-क्रीमी लेयर में कैसे चुनी गई। वह निश्चित रूप से गरीब व्यक्ति नहीं थी। उनके परिवार के पास पर्याप्त जमीन है जो निश्चित रूप से उन्हें एक अलग आर्थिक श्रेणी में रखेगी। पूजा ने यह भी दावा किया था कि उसकी एक अलग तरह की शारीरिक स्थिति है, जो उसे विकलांग कोटे के तहत आरक्षित सीट के लिए हकदार बनाती है। यूपीएससी और कार्मिक विभाग द्वारा विकलांगता के संबंध में कुछ तय दिशा-निदेशों का पालन करते हैं। एक व्यक्ति जिसे एक आंख में दृष्टि नहीं होती है, उसे 'विकलांग'' नहीं माना जाता है, यदि दूसरी आंख हर तरह से ठीक है।

देश की बात

मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की जननी है भारत

डॉ. राघवेन्द्र शर्मा

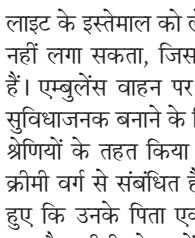

भारत के लिए यह गौरव का विषय है कि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। यह भी सर्वविदित है कि दुनिया में हमारे देश को मदर ऑफ डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र की जननी भी कहा जाता है। जाहिर है इसका श्रेय हमारी सामाजिक व्यवस्था और जागरूक अवस्था को जाता है। यही वजह है कि हमारे यहां अपवाद छोड़ दें तो बड़ी ही सहजता के साथ सत्ता परिवर्तन हो जाते हैं। मतदान के बाद सत्ताएं एक औपचारिकता की तरह हस्तांतरित हो जाती हैं। इस बीच किसी भी प्रकार की हाय तौबा देखने को नहीं मिलती। हाय तौबा से मेरा आशय उस हिंसा और उत्तेजना के अतिरेक से है जो हमें तथाकथित विकसित देशों में देखने को मिलती है। ऐसा अनेक जाने-माने देशों में देखने को मिला जब चुनाव पश्चात हारने वाली पार्टी को अपना आपा खोते देखा गया। यहां तक कि नई सत्ता के शपथ ग्रहण समारोह में भगदड़ मचीं, और तो और राष्ट्रपति भवनों तक को हिंसा का अतिरेक देखने को विवश होना पड़ गया। लेकिन बेहद गर्व की बात है कि भारत में ऐसे दृश्य कल्पनातीत ही हैं। सवाल उठता है कि जिन्हें हम आदर्श अथवा विकसित और संभ्रांत मानते रहे, वहां तो मतदान उपरांत सत्ता को लेकर हिंसक वातावरण देखने को मिले। फिर भारत में क्यों हालात सहज बने रहते हैं। इसका जवाब है देश के मतदाताओं का जागरूक होना। जब हम आजाद हुए तब हम पर राज करने वालों ने यही सवाल उठाया था कि इन्हें आजादी दे दी तो ये देश को चलाएंगे कैसे? लेकिन गर्व होता है यह याद करके कि हमने विश्व का सर्वोत्तम संविधान तो बनाया ही, विश्व की सबसे बड़े लोकतंत्र की स्थापना भी कर दिखाई। तो फिर दूसरा सवाल यह उठता है कि क्या हमारे यहां सत्ता की आपाधापी कभी मची ही नहीं? तो इसका जवाब इनकार में नहीं है। हां हम मानते हैं कि हमारे यहां भी इस तरह के प्रयास हुए, किंतु जनता की जागरूकता ने उन अति महत्वाकांक्षी हसरतों को नाकाम भी कर दिखाया। उदाहरण के लिए हम 1975 में बलात थोपे गए आपातकाल का उल्लेख कर सकते हैं।

बोधि वृक्ष

डर का माहौल यदि खतरे की सीढ़ी पार कर गया, तो पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है, और इसके लिए कोई दोषी है तो वह है, राजनेताओं में कुर्सी का मोह

...और अब नाम-पहचान पर धर्मयुद्ध

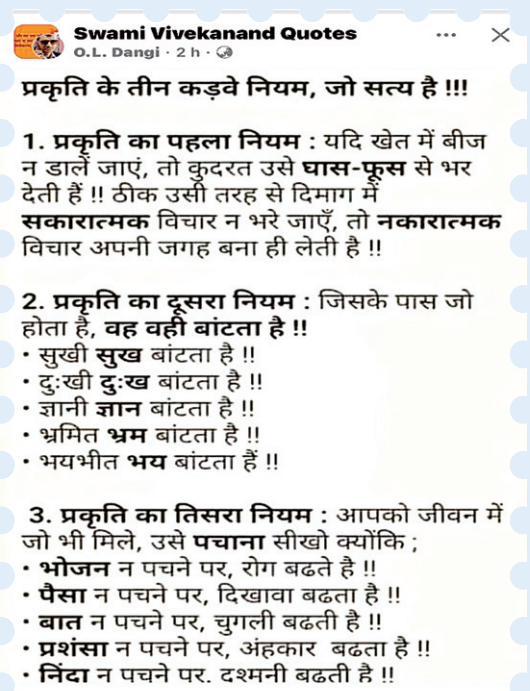

आज सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि समूचा विश्व एक दमघोटू माहौल में जीनें को मजबूर है, साम्प्रदायिकता का यह जहरीला धुंआ हर किसी के दिल-दिमाग में घुटन पैदा कर रहा है, भारत का 'हिन्दूराष्ट्र' का नारा अब विश्वमंच से लगाया जाने लगा है, इस कारण से एक सम्प्रदाय विशेष में डर तथा चिंता व्याप्त हो गई है, अब यह माहौल क्यों बनाया गया और इसके पीछे कौन सी शक्तियां है? इसका उत्तर तो बाद में खोज लिया जाएगा, किंतु प्राथमिकता इस माहौल को खत्म करने की है, क्योंकि यह माहौल यदि खतरे की सीढ़ी पार कर गया तो पूरे विश्व की शांति खतरे में पड़ सकती है। भारत में इस माहौल की शुरूआत देश को राजनीतिक नेतृत्व प्रदान करने वाले उत्तरप्रदेश से हुई है, जहां सबसे पहले धार्मिक रैलियों के मार्ग की दुकानों के बाहर उनके मालिकों के नाम की पट्टियां लगाने के आदेश प्रदान किए गए, जिसका सबसे पहले अनुसरण पड़ौसी राज्य उत्तराखण्ड ने किया जहां कांवड मार्ग की दुकानों पर इस विवादित नियम को लेकर सख्ती बरती गई। उत्तरप्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब छूत का यह रोग मध्यप्रदेश में भी प्रवेश कर गया है और मध्यप्रदेश स्थित देश की सबसे पुण्य व पवित्र नगरी अवंतिका (उज्जैन) में इस नियम को सख्ती के साथ लागू करने के निर्देश प्रदान कर दिए गए। वैसे इस स्थिति के लिए कोई दोषी नहीं है, न राजनेता और न उनके आराध्य। अगर कोई दोषी है तो वह है, कुर्सी का मोह।

–ओमप्रकाश मेहता

फेसबुक वॉल से

Swami Vivekanand Quotes
O.L. Dangi · 2 h ·

प्रकृति के तीन कड़वे नियम, जो सत्य है !!!

1. प्रकृति का पहला नियम : यदि खेत में बीज न डालें जाएं, तो कुदरत उसे **घास-फूस** से भर देती हैं !! ठीक उसी तरह से दिमाग में **सकारात्मक** विचार न भरे जाएँ, तो **नकारात्मक** विचार अपनी जगह बना ही लेती है !!

2. प्रकृति का दूसरा नियम : जिसके पास जो होता है, **वह वही बांटता है !!**
- सुखी **सुख** बांटता है !!
- दुःखी **दुःख** बांटता है !!
- ज्ञानी **ज्ञान** बांटता है !!
- भ्रमित **भ्रम** बांटता है !!
- भयभीत **भय** बांटता हैं !!

3. प्रकृति का तिसरा नियम : आपको जीवन में जो भी मिले, उसे **पचाना** सीखो क्योंकि ;
- **भोजन** न पचने पर, रोग बढते है !!
- **पैसा** न पचने पर, दिखावा बढता है !!
- **बात** न पचने पर, चुगली बढती है !!
- **प्रशंसा** न पचने पर, अंहकार बढता है !!
- **निंदा** न पचने पर, दश्मनी बढती है !!

290 · 8 comments 95 shares

Like · Comment · Send · Share

X से

Hardik Bhavsar @Bitt2DA · 18h
बारिश का इल्जाम भी मोदी जी पर...

और ये लाल टोपी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा है 🤣

752 · 2.8K · 9.6K · 602K

अलग बात

ट्रंप को हरा चुनाव जीत सकती हैं कमला

ललित मोहन बंसल
लेखक, भारतीय मूल के अमेरिकी पत्रकार हैं

भारतीय मूल की अश्वेत महिला कमला हैरिस राष्ट्रपति चुनाव-2024 जीत सकती हैं, बशर्ते डेमोक्रेट एकजुट हो जाएं और उनके एक वर्ग का महिलाओं के प्रति नजरिया बदल जाए। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद से एशियाई अमेरिकी, अफ्रीकी अमेरिकी और लैटिन अमेरिकी खेमों में खुशी की लहर है। कमला ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया में कहा है कि नामांकन लूंगी और चुनाव भी जीतूंगी। अमेरिका की दो बड़ी पार्टियों- रिपब्लिकन और डेमोक्रेट में परंपरावादियों का एक बड़ा समूह है, जो महिलाओं को बराबरी का दर्जा देने में संकोच करता है। डेमोक्रेटिक पुरुषों में एक-डेढ़ दशक से महिलाओं के प्रति नजरिए में तेजी से बदलाव आया है जबकि चर्च से निर्देशित परंपरावादी इवेंजिलिस्ट रिपब्लिकन अपने पुराने ढर्रे से बाहर नहीं आ पा रहे हैं।

अमेरिकी समाज में प्रगतिशील वाम और मध्यमार्गी डेमोक्रेट के पास 53-54 प्रतिशत मत हैं। इनमें अधिकतर निम्न और निम्न मध्यम आय वर्ग की एकल महिलाएं हैं, जो अपने सीमित संसाधनों के कारण मतदान में हिस्सा नहीं ले पातीं। कमला हैरिस ने पिछले चार वर्षों में अथक परिश्रम, एक महिला को छूने वाले मुद्दों में 'गर्भपात और इमिग्रेशन' पर काम किया है, उससे महिलाओं के एक बड़े वर्ग में कमला हैरिस के प्रति झुकाव बढ़ा है। चुनाव में अभी मात्र 105 दिन का समय शेष है। कमला हैरिस के सम्मुख पार्टी नियमों के अंतर्गत पहले नामांकन हासिल करना है और उसके बाद चुनाव प्रचार में एक बड़े फंड की जरूरत है। राष्ट्रपति जो बाइडेन के चुनावी फंड में मात्र 910 लाख डालर हैं, जो अमेरिकी चुनाव के लिए अत्यंत अल्प राशि है। हैरिस के दौड़ में आते ही बड़े और छोटे फंड देने वाले आगे आ रहे है। उन्होंने पहले पांच घंटों में खासी रकम जुटाई है। कमला के सम्मुख इस समय सबसे बड़ा मुद्दा राष्ट्रपति जो बाइडेन के अकस्मात राष्ट्रपति पद की दौड़ में हटने से पैदा हुई परिस्थिति में नामांकन हासिल करने की समस्या है। उनके नामांकन को लेकर पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं में बराक ओबामा, प्रतिनिधि सभा की स्पीकर के रूप में दायित्व निभाने वालीं नैन्सी पेलोसी तथा सीनेट और प्रतिनिधि सभा में पार्टी लीडर और नेता के रूप में दायित्व निभाने वाले चूक शुमर ने रविवार की देर रात तक कमला के प्रति समर्थन व्यक्त नहीं किया है। इसके बावजूद कमला एक दर्जन से अधिक डेमोक्रेट राज्यों और स्विंग स्टेट में समर्थन हासिल कर पद के उम्मीदवारों में सबसे आगे हैं।

टेक वर्ल्ड

बच्चों में अच्छी आदतों का विकास

हेमेन्द्र क्षीरसागर

बच्चे एक तरह से पौधे की तरह होते हैं। माता पिता माली की तरह, हम जिस तरह से उनकी देखभाल करेंगे हमें वैसा ही परिणाम देखने को मिलेगा। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास तभी संभव है जब वे शरारतें कर रहे हों या कई छोटी-छोटी गलतियां कर रहे हों। लेकिन आप उन्हें सही मार्गदर्शन करते हों। कुछ माता-पिता बच्चों की शरारतों, गलतियों को नजरअंदाज कर देते हैं यह सोचकर कि बच्चा अभी छोटा है। फिर यही छोटी-छोटी गलतियाँ उनकी आदतें बन जाती हैं। बचपन की गलतियां उसके भविष्य को प्रभावित करती हैं। बच्चा बड़ा होने पर अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाता। क्योंकि यह छोटी छोटी बातें उसकी आदत बन चुकी होती हैं और वह आदतों से मजबूर होता है। माता-पिता को बच्चों को बचपन से ही अच्छी तालीम देनी चाहिए। अगर छोटा बच्चा कोई गलती करता है तो उसे प्यार से समझाएं जैसे - अगर बच्चे ने कोई चीज खराब कर दी या तोड़ दी है तो उसे मारें नहीं। बच्चे में अच्छे संस्कार घर के माहौल से आते हैं। अगर आप बच्चों में शिक्षा, स्वास्थ्य, ईमानदारी, सादगी, विनम्रता, बड़ों का सम्मान आदि के लिए सुबह शाम एक घंटे का समय देते हैं, तो आपको अवश्य ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अतः बच्चे को खिलौना ना दिया जाए, तो वह कुछ समय तक रोएगा। लेकिन संस्कार ना दिए जाएं तो वह जीवन भर रोएगा। बच्चों के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें, क्योंकि बच्चे अपने माता-पिता पर निर्भर होते हैं। उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें संतुलित आहार देने की जरूरत होती है। बच्चों को आहार देते समय इसके फायदे भी बताएं। धीरे-धीरे बच्चे इसे अपने भोजन का हिस्सा बना लेंगे। यह उनकी आदत बन जाएगी जो भविष्य में अच्छे स्वास्थ्य में मददगार साबित होगी।

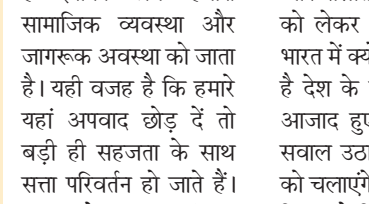

स्वामी, पारिजात माइनिंग इण्डस्ट्रीज (इण्डिया) प्रा.लि. के लिए प्रकाशक एंव मुद्रक हर्षवर्द्धन बजाज द्वारा 502, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान, हरमू रोड, रांची से प्रकाशित एवं एस एच प्रिंटर्स प्राइवेट लिमिटेड (पूर्व में शिवासाईं पब्लिकेशन प्राइवेट लिमिटेड), नियर टेंडर बागीचा पेट्रोल पम्प, रातू, रांची-835222, झारखंड द्वारा मुद्रित। रजिस्ट्रेशन नं: BIHHIN/1999/155, प्रधान संपादक : सुरेश बजाज, संपादक : हर्षवर्द्धन बजाज, कार्यकारी संपादक : सुनील सिंह 'बादल'*, समाचार संपादक : त्रिभुवन कुमार सिन्हा, प्रेस कार्यालय : रांची रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर (डालटनगंज) पलामू-822102, फोन नंबर : 06562-796018, रांची कार्यालय : 502बी, पांचवी मंजिल, मंगलमूर्ति हाईट्स, रानी बगान हरमू रोड, रांची-834001, फोन नंबर : 0651-3553943, ई-मेल : news.rnmail@gmail.com, article.rnmail@gmail.com (*पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेवार।)

आम बजट : बिहार में सड़कों का बिछेगा जाल, बाढ़ नियंत्रण पर भी होगा काम

एजेंसी

पटना। बिहार को भले ही विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, लेकिन, केंद्र सरकार ने बजट में कई तोहफे दिए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में आम बजट पेश किया। इस आम बजट में बिहार को सड़क, स्वास्थ्य के साथ बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई सौगात दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए कहा कि हम नेपाल की तरफ से बाढ़ नियंत्रण के लिए काम करेंगे। हमारी सिंचाई की परियोजनाएं हैं, उसे वित्तीय समर्थन देंगे। इसमें 11,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। पेश बजट में अमृतसर-कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात की गई है। इस कॉरिडोर के तहत गया में एक औद्योगिक केंद्र बनाया जाएगा, जिससे पूर्वोत्तर क्षेत्र के औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि गया का यह केंद्र प्राचीन सांस्कृतिक केंद्रों को आधुनिक अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ेगा। गया के विष्णुपद मंदिर और बोधगया के महाबोधि मंदिर में धार्मिक पर्यटन विकसित किया जाएगा। नालंदा को भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार सहायता देगी। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार में चार नए एक्सप्रेस वे बनाने के प्रस्ताव दिए हैं। आम बजट में बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की गई। इसके अलावा 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का भी ऐलान किया गया। केंद्र सरकार ने पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस वे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान किया है। इसके अलावा बक्सर से भागलपुर के बीच हाईवे बनाया जाएगा। साथ ही बोधगया से राजगीर, वैशाली होते हुए दरभंगा तक हाईवे बनेगा। बक्सर में गंगा नदी पर दो लेन का एक पुल भी बनाया जाएगा। केंद्र सरकार बिहार में कई एयरपोर्ट, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगी। पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। निर्मला सीतारमण ने बिहार को अतिरिक्त आर्थिक मदद देने को लेकर कहा, बिहार के पीरपैंती में 21,400 करोड़ रुपये की लागत से 2400 मेगावाट का नया बिजली संयंत्र स्थापित करने सहित बिजली परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बिहार में नए हवाई अड्डे, मेडिकल कॉलेज और खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

बहुपक्षीय विकास बैंकों से बाहरी सहायता के लिए बिहार सरकार के अनुरोध पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, अमृतसर-कोलकाता औद्योगिक गलियारे पर हम बिहार के गया में औद्योगिक विकास करेंगे। इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। हम पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर-भागलपुर राजमार्ग, बोधगया-राजगीर-वैशाली-दरभंगा सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास का भी समर्थन करेंगे और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपये की लागत से एक अतिरिक्त दो लेन का पुल बनाया जाएगा।

बिहार में सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा

- पीरपैंती में 2,400 मेगावाट के 21,000 करोड़ के पावर प्लांट का ऐलान
- बिहार में नए मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम की भी स्थापना होगी
- पटना से पूर्णिया के बीच एक्सप्रेस वे बनाने के लिए फंड देने का ऐलान

बिहार के विकास में मील का पत्थर साबित होगा बजट : गिरिराज सिंह

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री और बिहार से लोकसभा सांसद गिरिराज सिंह ने आम बजट की सराहना करते हुए कहा है कि यह बजट चार स्तंभ युवा, किसान, गरीब और महिला पर टिका हुआ है। एमएसएमई, कृषि और महिला के कल्याण सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को बजट में मिली सौगातों की विपक्षी दलों द्वारा आलोचना करने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस बताए कि आंध्र प्रदेश के विभाजन के समय उनकी सरकार ने जो वादा किया था, वो आंध्र प्रदेश को नहीं मिलना चाहिए, क्या आंध्र प्रदेश को उसकी राजधानी के विकास के लिए फंड नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जब आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस की सरकार थी, तब भी मोदी सरकार ने आंध्र प्रदेश को फंड दिया था और आज भी दिया है। बिहार को लेकर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए पहली बार 2015 में 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा की थी और 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किया।

बजट में बिहार को मिली कई सौगातें, जदयू ने जताई खुशी

पटना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को लोकसभा में मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश किया। बजट में मोदी सरकार ने बिहार के लिए कई बड़ी घोषणाएं की है। जिस पर जदयू नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने मोदी सरकार के बजट की प्रशंसा की और कहा कि भारत सरकार ने बजट में बिहार को विशेष पैकेज से ज्यादा दे दिया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 26,000 करोड़ के हाईवे बनाने की घोषणा की गई है। केंद्र ने गंगा नदी पर दो नए पुल बनाने की घोषणा की है। बिहार के जिन जगहों में मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहां केंद्र सरकार ने नए मेडिकल कॉलेज खोलने का प्रावधान किया है। जहां एयरपोर्ट नहीं है, वहां पर एयरपोर्ट बनाने के लिए बिहार सरकार से प्रस्ताव मांगा गया है। 2 लाख 66 हजार करोड़ ग्रामीण विकास विभाग को केंद्र सरकार ने दिया है, पीरपैंती में 2,400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने की घोषणा की गई है।

उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया

बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने केंद्रीय बजट को स्वागतयोग्य बताते हुए इसे ऐतिहासिक बजट बताया। उन्होंने कहा कि बिहार को सभी क्षेत्रों में कुछ न कुछ मिला है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केंद्रीय बजट का स्वागत किया। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट में एक तरह से भारत के खजाने को बिहार की तरफ खोलने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि यह बजट बिहार को विकसित बनाने की पटकथा लिखेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में बिहार को तीन प्रोजेक्ट्स में करीब 58 हजार 900 करोड़ रुपये मिले हैं। इसमें तीन एक्सप्रेस-वे, पावर प्लांट, एयरपोर्ट और मेडिकल कॉलेज भी खुलेंगे, गया-नालंदा में कॉरिडोर बनेगा। उन्होंने कहा कि इस बजट से बिहार के विकास की गति में तेजी आएगी और बिहार के सभी क्षेत्रों को विकसित बनाने में मदद मिलेगी। चौधरी ने जोर देकर कहा कि बिहार में बाढ़ की समस्या हो, एयरपोर्ट की समस्या हो, बिजली की बात हो, धार्मिक स्थलों के विकास की बात हो, पर्यटकों की संख्या बढ़ाने की बात हो, सभी क्षेत्र में कुछ न कुछ दिया गया है। इससे बिहार का सवार्गीण विकास होगा। बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने 2024-25 के केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए कहा कि इस बजट में गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के सर्वांगीण विकास के साथ विकसित भारत के संकल्प की दिशा में सार्थक कदम बढ़ाया गया है। विशेष रूप से यह बजट बिहार के विकास के लिए ऐतिहासिक है।

तेजस्वी ने केंद्रीय बजट को बताया निराशाजनक, रविशंकर ने कहा

'विकसित भारत की राह करेगा मजबूत'

पटना। बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने केंद्रीय बजट को निराशाजनक बजट कहा है। बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बजट ने बिहार के लोगों को फिर निराश किया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार को प्रगति पथ पर ले जाने के लिए एक रिवाइवल प्लान की जरूरत थी, और इसके लिए विशेष राज्य के दर्जे के साथ विशेष पैकेज की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि, रूटीन आवंटन तथा पूर्व स्वीकृत, निर्धारित और आवंटित योजनाओं को नई सौगात बताने वाले बिहार का अपमान न करें। उन्होंने कहा कि पलायन रोकने, प्रदेश का पिछड़ापन हटाने तथा उद्योग धंधों के साथ-साथ युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए, हम विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इंच भर भी पीछे नहीं हटेंगे।

इधर, पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि आज जो बजट पेश हुआ है, वह विकसित भारत बनने की गति को और तेज करेगा। इस बजट में रोजगार के करोड़ों अवसर बढ़ाने के बड़े रोडमैप हैं।

आज का राशिफल

मेष कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कर भला तो हो भला वाली कहावत याद रखें। किसी को हानी पंहुचाने की चेष्टा न करें अन्यथा हानि संभव है। धार्मिक कार्य में समय और धन व्यय होगा। कर्ज तथा रोगों से मुक्ति भी संभव है।

वृषभ यात्रा शुभ रहेगी। अपने काम पर पैनी नजर रखिए। विरोधी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। अपने काम को प्राथमिकता से करें। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा।

मिथुन शनै-शनै स्थिति पक्ष की बनने लगेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश लाभ देगी। यात्रा का दूरगामी परिणाम मिल जाएगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। सुखद समय की अनुभूतियां प्रबल होगी। लाभदायक कार्यों की चेष्टाएं प्रबल होंगी।

कर्क मध्याह्न से ही आशाएं बलवती होंगी। महत्त्वपूर्ण कार्यों को आज ही निपटा लें, उसके बाद समय व्ययकारी सिद्ध होगा। भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। इच्छित कार्य सफल होंगे। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी।

सिंह कामकाज में आ रही बाधा को दूर कर लेंगे। सुविधा और समन्वय बना रहने से कामकाज में प्रगति बन जाएगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी। यात्रा शुभ रहेगी। माता पक्ष से विशेष लाभ। कार्यक्षेत्र में संतोषजनक सफलता मिलेगी। यात्रा का परिणाम मिल जाएगा।

कन्या अपने काम पर पैनी नजर रखिए। स्वास्थ्य लाभ में समय और धन व्यय होगा। लेन-देन में अस्पष्टता ठीक नहीं। मध्याह्न पूर्व समय आपके पक्ष का बना रहेगा। समय पक्ष का बना रहेगा। कारोबारी काम में प्रगति बनती रहेगी। लेन-देन में आ रही बाधा दूर करने का प्रयास होंगे।

तुला कहीं रुका हुआ पैसा वसूलने में मदद मिल जाएगी। व्यर्थ प्रपंच में समय नहीं गंवाकर अपने काम पर ध्यान दीजिए। पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। व्यापार व व्यवसाय में स्थिति उत्तम रहेगी। आर्थिक हित के काम को साधने में मदद मिल जाएगी।

वृश्चिक अपने काम को प्राथमिकता से करें। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध होंगे। कुछ आर्थिक संकोच पैदा हो सकते है। कोई प्रिय वस्तु या नवीन वस्त्राभूषण प्राप्त होंगे। पुराने मित्र से मिलन होगा। अपने हित के काम सुबह-सवेरे निपटा लें।

धनु धार्मिक आस्थाएं फलीभूत होंगी। निर्मूल शंकाओं के कारण मनस्ताप भी पैदा हो सकते है। कामकाज की व्यस्तता से सुख-आराम प्रभावित होगा। धर्म-कर्म के प्रति रुचि जागृत होगी। मानसिक एवं शारीरिक शिथिलता पैदा होगी। श्रेष्ठजनों की सहानुभूतियां होगी। समय पक्ष का बना रहेगा।

मकर परिवारजन का सहयोग व समन्वय काम को बनाना आसान करेगा। समय नकारात्मक परिणाम देने वाला बन रहा है। आलस्य का त्याग करें। कारोबारी काम में नवीन तालमेल और समन्वय बन जाएगा। जीवन साथी अथवा यार दोस्तों के साथ साझे में किए जा रहे काम में लाभ मिल जाएगा।

कुम्भ पूर्व नियोजित कार्यक्रम सरलता से संपन्न हो जाएंगे। जोखिम से दूर रहना ही बुद्धिमानी होगी। ले देकर की जा रही काम की कोशिश ठीक नहीं। महत्वपूर्ण कार्य को समय पर बना लें तो अच्छा ही होगा। आशा और उत्साह के कारण सक्रियता बढ़ेगी। स्वास्थ्य मध्यम रहेगा। मित्र से मिलन होगा।

मीन भ्रातृपक्ष में विरोध होने की संभावना है। मान-सम्मान बढ़ेगा। आय-व्यय की स्थिति समान रहेगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। व्यापार व व्यवसाय में ध्यान देने से सफलता मिलेगी। मेल-मिलाप से काम बनाने की कोशिश सफल होगी। आगे बढ़ने के अवसर लाभकारी सिद्ध हो रहे हैं।

'विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है बजट : सीएम योगी

एजेंसी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के आम बजट को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि ये बजट भारत की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करेगा। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का आम बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, विकासोन्मुखी 140 करोड़ देशवासियों की आशाओं, आकांक्षाओं और अमृतकाल के सभी संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। आम बजट 2024-25 'विकसित भारत-आत्मनिर्भर भारत' के निर्माण का आर्थिक दस्तावेज है। इस आम बजट में अंत्योदय की पावन भावना, विकास की असीम संभावना और नवोन्मेष की नव-दृष्टि है। इस आम बजट में अन्नदाता किसानों की समृद्धि के लिए 1 लाख 52 हजार करोड़ रुपये कृषि और सहायक क्षेत्रों के लिए, महिला सशक्तीकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से आधी आबादी वाले देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की आधी आबादी इससे लाभांवित होने वाली है।

खास तौर पर तब जब यूपी 2020 से मिशन शक्ति को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतार रहा है, सर्वाधिक अन्नदाता किसान यूपी से आता है, उनकी समृद्धि में आज संसद में प्रस्तुत आम बजट बड़ी भूमिका निर्वहन करने वाला है। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को लाखों नौकरियों के साथ-साथ माध्यम वर्गी परिवार के लिए इनकम टैक्स में जो नई टैक्स सैल्ब की घोषणा हुई है, ये स्वागत योग्य है। यह बजट भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदलने के संकल्प साथ ही दुनिया के ग्रोथ इंजन के रूप में भारत की भूमिका और विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने का एक आर्थिक दस्तावेज के रूप में यह देश की संसद में प्रस्तुत किया गया है।

मोदी सरकार का बजट मायूस करने वाला ज्यादा : मायावती

मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट मंगलवार को लोकसभा में पेश किया गया। इस पर बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने प्रतिक्रिया दी है। मायावती ने कहा, संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ढर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्नासेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु 'अच्छे दिन' की उम्मीदों वाला कम, उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा है।" देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहां के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव है।

पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं : अखिलेश

केंद्रीय बजट को लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। उन्होंने कहा, अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की क्या स्थिति है? जो परियोजनाएं वे चला रहे हैं, वे कभी समय पर पूरी नहीं होतीं। यह अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के किसानों के लिए बजट में कुछ है जो प्रधानमंत्री देते हैं? वहीं, केंद्रीय बजट 2024 पर मैनपुरी से सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ होना चाहिए था, बजट में कुछ भी नहीं है, रसोई का ख्याल नहीं रखा गया है। सरकार महंगाई को लेकर कोई कदम नहीं उठाना चाहती।

4,300 से अधिक छात्र बांग्लादेश से लौटे

एजेंसी

कोलकाता। सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) ने मंगलवार को कहा कि पिछले चार दिन में एक कनाडाई और दो मालदीव के नागरिकों सहित 4,300 से अधिक छात्र बांग्लादेश से भारत आ चुके हैं। बीएसएफ की पूर्वी कमान के एक अधिकारी ने बताया, शुक्रवार से अब तक 4,315 छात्र भारत-बांग्लादेश सीमा पार कर आ चुके हैं और उन्हें बीएसएफ द्वारा सहायता दी गई। सीमा पार करने वाले इन छात्रों में से 3,087 भारतीय, 41 बांग्लादेशी, 1,118 नेपाली, 66 भूटानी, दो मालदीव का और एक कनाडाई छात्र है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों की चिकित्सा जांच के साथ उन्हें भोजन भी उपलब्ध कराया गया। अधिकारी ने बताया, जरूरत पड़ने पर दस्तावेजों के लिए विशेष काउंटर भी स्थापित किए गए हैं। वहीं, बीएसएफ छात्रों को उनके निकटतम गंतव्य तक पहुंचाने का भी इंतजाम कर रहा है।

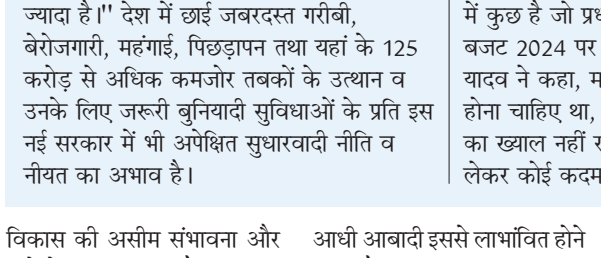

अवैध आव्रजन रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी की गई

बीएसएफ अधिकारी ने कहा, भारत-बांग्लादेश सीमा से किसी भी अवैध आव्रजन को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। भारत और अन्य देशों के छात्रों की सुरक्षित वापसी का भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बीएसएफ की पूर्वी कमान को पांच भारतीय राज्यों के 32 जिलों से होकर गुजरने वाली भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

न्यूज बॉक्स

तृणमूल के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है

कोलकता। केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण द्वारा बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को दिए गए विशेष पैकेज पर विपक्ष हमलावर हो गया है। केंद्रीय बजट पर तृणमूल कांग्रेस के सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह 'कुर्सी बचाओ' बजट है। उन्होंने कहा कि ये बजट एनडीए के नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को साथ रखने के लिए है, ये बजट देश के लिए नहीं है। इसमें बंगाल के लिए कुछ नहीं है, इनको बंगाल से कोई लेना देना नहीं है।

29 सांसदों के बावजूद बजट में मध्य प्रदेश के साथ हुआ छल : जीतू पटवारी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश देश के बजट पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 29 सीटें दी हैं, लेकिन राज्य के लिए बजट में कुछ नहीं है। उन्होने कहा कि, पूरे देश में नरेंद्र मोदी से विश्वास हटा था, बाद में जैसे-तैसे उनकी सरकार बनी थी। लेकिन, इस बजट में मध्य प्रदेश की भावना के साथ धोखा किया गया है। मध्य प्रदेश को 29 सांसदों के बावजूद कुछ नहीं मिला। उन्होंने कहा, गेहूं और धान के लिए 'मोदी गारंटी' की बात की गई थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने की बातें की, अब 100 औद्योगिक सिटी बनाने की बात हो रही है। पहले 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, अब 4 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं। सबसे ज्यादा महंगाई हमारे देश में है, बेरोजगारी भी हमारे यहां सबसे ज्यादा है। जिस तरह से बजट का प्रस्तुतीकरण हुआ, उसका संदेश स्पष्ट है कि अब सिंगल झूठ की जगह डबल झूठ से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के साथ छल हुआ है। यह शर्मनाक है कि यहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव, शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे केंद्रीय मंत्री भी मध्य प्रदेश की रक्षा नहीं कर पाए। इन सबको अपने लिए जीना है। जब मध्य प्रदेश के बच्चों का गला घोटा जाता है, तो ये चुप रहते हैं।

हाईकोर्ट का लोस अध्यक्ष की बेटी के खिलाफ अपमानजनक पोस्ट हटाने का आदेश

नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को रेलवे अधिकारी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला को बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट को हटाने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला की पीठ ने अंजलि बिरला के बारे में भ्रामक और गलत जानकारी फैलाने के लिए एक्स, गूगल और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के खिलाफ दायर मानहानि मुकदमे में अंतरिम निर्देश दिया है। अदालत ने यह दावा करने वाले पोस्ट को ब्लॉक करने का आदेश दिया कि अंजलि बिरला ने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा पास की। न्यायालय ने एक्स और गूगल को विवादित सोशल मीडिया सामग्री को 24 घंटे के भीतर हटाने का निर्देश दिया। यदि वादी को किसी अन्य समान पोस्ट के बारे में पता चलता है, तो वह इसके बारे में एक्स और गूगल को सूचित करेगी। न्यायमूर्ति चावला ने अज्ञात पक्षों के अंजलि के मानहानि मुकदमे में उल्लिखित कथित मानहानि वाले कंटेंट को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पोस्ट करने, प्रसारित करने, ट्वीट करने या रीट्वीट पर भी रोक लगा दी। उच्च न्यायालय ने इस मामले में एक्स, गूगल, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा अज्ञात पक्षों को भी नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।

पूर्णिया में अज्ञात बीमारी से तीन की मौत कई बीमार, डब्लूएचओ की टीम पहुंची

पूर्णिया। पूर्णिया पूर्व के एक गांव में अज्ञात बीमारी से तीन लोगों की मौत हो गई है एवं कई लोग बीमार हैं। तीन लोगों की मौत विगत 10 से 15 दिनों के अंदर हुई है। गांव के गरीब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे गांव में कई लोग बीमार हैं। बात धीरे-धीरे फैलती गई और तब जाकर डॉक्टर की टीम पहुंची। यह मामला पूर्णिया पूर्व प्रखंड के रामपुर पंचायत के मुसहरी टोला की है। यहां किसी अनजाने वायरस की वजह से एक ही परिवार के तीन लोगों की मृत्यु हो गई तथा गांव के कई अन्य लोग बीमार हैं। दहशत से पूरे गांव में एक अनजाने डर का माहौल बना हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद उपाध्यक्ष नीरज सिंह उर्फ छोटू सिंह एवं कई लोग पहुंचे । साथ ही पूर्णिया से मेडिकल की एक बड़ी टीम वहां पहुंची एवं जांच वगैरह करना प्रारंभ किया। मेडिकल टीम ने पूरे गांव में फैले संक्रमण को लेकर लोगों को बेहतर उपचार की बात कही एवं यथासंभव मदद करने का भरोसा भी दिया। इस भयावह स्थिति को देखते हुए पूर्णिया के सिविल सर्जन से बात की गई। उसके बाद संध्या में पूर्णिया चिकित्सा पदाधिकारी ,सिविल सर्जन एवं डब्लू एच ओ की टीम भी वहां पहुंच गई है। फिलहाल मेडिकल की टीम ने कहा है कि चापाकल का पानी नहीं पिए। अगर पीना ही है तो उस पानी को गर्म करने के बाद ठंडा होने पर ही पीएं एवं बरसाती चीजों को ना खाएं।

ममता बनर्जी ने दिए निर्देश: आलू संकट न हो, निर्यात पर रोक

कोलकाता। राज्य के आलू व्यवसायियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है, जिससे बाजार में आलू की कमी हो गई है और कीमतें बढ़ गई हैं। इस संकट से मध्यवर्गीय परिवारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आलू को लेकर कोई संकट नहीं होना चाहिए। मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ने पंचायत मंत्री और पूर्व कृषि सलाहकार प्रदीप मजूमदार को इस बारे में स्पष्ट रूप से निर्देश दिए। मंगलवार को राज्य विधानसभा में ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल की बैठक की। इस बैठक में आलू की मूल्यवृद्धि और आपूर्ति में कमी को लेकर उन्होंने गहरा असंतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि आलू को लेकर कोई संकट नहीं होना चाहिए और जब तक कीमतें नहीं घटतीं, तब तक अन्य राज्यों को आलू निर्यात नहीं किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि प्रगतिशील आलू व्यापारी संघ ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री ने अब इस संघ को हटाकर नए संगठन बनाने का निर्देश दिया है। पिछले कुछ हफ्तों से आलू की कीमतें सातवें आसमान पर हैं। राज्य सरकार द्वारा जारी कई निर्देशों और कड़े कदमों के बावजूद स्थिति में बहुत सुधार नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जब तक राज्य की मांग पूरी नहीं होती और कीमतें नियंत्रित नहीं होतीं, तब तक अन्य राज्यों को आलू निर्यात नहीं किया जाएगा। निर्यात पर रोक लगाने के लिए विभिन्न सीमाओं पर कड़ी निगरानी की जा रही है, जिसे लेकर आलू व्यापारियों में गहरा विरोध है। आलू व्यापारी संघ के अध्यक्ष विद्युतबरन प्रीतिहार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा निर्यात पर प्रतिबंध लगाने से व्यापार को नुकसान हो रहा है। इसके विरोध में आलू व्यापारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।

केंद्रीय बजट में खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपये आवंटित

880
करोड़ रुपए का आवंटित था पिछले वित्तीय वर्ष

596.39
करोड़ रुपए था 22-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन

2018
की शुरूआत के बाद से सरकार ने इसमें और खेल आयोजनों को जोड़ना जारी रखा है

नाडा के बजट को 21.73 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22.30 करोड़ रुपए कर दिया गया है

एनडीटीएल के बजट को 19.50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 22 करोड़ कर दिया गया है

एजेंसी। नई दिल्ली

जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रमुख परियोजना खेलो इंडिया को एक बार फिर खेल मंत्रालय के लिए केंद्रीय बजट में सबसे अधिक राशि आवंटित हुई है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा मंगलवार को पेश केंद्रीय बजट में खेल मंत्रालय के लिए 3,442.32 करोड़ रुपए में से खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह रकम पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान 880 करोड़ रुपए के संशोधित आवंटन से 20 करोड़ रुपए अधिक है। इस साल अगस्त में पेरिस ओलंपिक चक्र समाप्त होने वाला है और राष्ट्रमंडल खेलों और एशियाई खेलों अभी भी दो साल का समय है।

ऐसे में खेल मंत्रालय के बजट में पिछले चक्र की तुलना में केवल 45.36 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि की गई है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में खेलो इंडिया का वास्तविक आवंटन 596.39 करोड़ रुपए था। अगले साल (2023-24) के बजट में लगभग 400 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया था। इसे हालांकि संशोधित कर 880 करोड़ रुपए किया गया था। खेलो इंडिया युवा खेलों 2018 (केआईवाईजी) की शुरूआत के बाद से सरकार ने इसमें और खेल आयोजनों को जोड़ना जारी रखा है। मंत्रालय ने उसी वर्ष खेलो इंडिया शीतकालीन खेल और 2023 में खेलो इंडिया पैरा खेलों शुरू करने के साथ 2020 में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेलों की शुरूआत की। देश भर में सैकड़ों खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्टता केंद्र (केआईएससीई) स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य प्रतिभाशाली उदीयमान खिलाड़ियों को सुविधाएं प्रदान करना है। खेलो इंडिया के कई एथलीट वर्तमान में भारतीय ओलंपिक दल में शामिल हैं। राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) को सरकार की सहायता में भी 15 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। यह 2023-24 में 325 करोड़ रुपए से बढ़कर नवीनतम बजट में 340 करोड़ रुपए हो गई है।

पेरिस ओलंपिक में भारत कल शुरू करेगा यात्रा

पेरिस 2024 के दौरान भारत जिन 16 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा, जिनमें तीरंदाजी एथलेटिक्स, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, घुड़सवारी, गोल्फ, हॉकी, जूडो, रोइंग, नौकायन शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन, कुश्ती और टेनिस शामिल हैं।

एजेंसी। नई दिल्ली

भारतीय दल 25 जुलाई से पेरिस ओलंपिक में अपनी यात्रा शुरू करेगा, जिसमें 117 एथलीट 16 खेलों में 69 पदक स्पधाओं में भाग लेंगे। नीरज चोपड़ा की अगुआई में 29 सदस्यीय एथलेटिक्स टीम फ्रांस में ओलंपिक के लिए जाने वाले दल का एक बड़ा हिस्सा होगी। इसके अलावा 21 सदस्यीय निशानेबाजी दल भी होगा, जो पेरिस 2024 में किसी भी खेल के लिए भारत द्वारा भेजा गया दूसरा सबसे बड़ा दल होगा। यह भारत द्वारा ओलंपिक इतिहास में भेजा गया सबसे बड़ा निशानेबाजी दल है, इससे पहले टोक्यो 2020 ओलंपिक के दौरान 15 निशानेबाजों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था।

पेरिस में तिरंगा फहराने के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले तीरंदाजों में दीपिका कुमारी और तरुणदीप राय जैसे सितारे शामिल हैं। वे 25 जुलाई को व्यक्तिगत रैंकिंग राउंड में प्रतिस्पर्धा करेंगे और अगले दिन होने वाले उद्घाटन समारोह से पहले एक्शन में आने वाले पहले भारतीय होंगे।

भारत को 27 जुलाई को शैटॉरौक्स के राष्ट्रीय निशानेबाजी केंद्र में होने वाले मिश्रित टीम एयर राइफल पदक मैचों के दौरान पदक पर अपना पहला शॉट मिलेगा। इस स्पर्धा में दो भारतीय टीमें, संदीप सिंह/एलावेनिल वलारिवन और अर्जुन बाबूता/रमिता जिंदल प्रतिस्पर्धा करेंगी।

मनु भाकर दो व्यक्तिगत पिस्टल स्पधाओं और 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम प्रतियोगिता में भी प्रतिस्पर्धा करेंगी। हालांकि, शो के स्टार, मौजूदा ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा अगस्त के दौरान एक्शन में होंगे। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा के लिए क्वालीफायर 6 अगस्त को होंगे और फाइनल दो दिन बाद होगा।

पेरिस ओलंपिक के बाद टेनिस को अलविदा कहेंगे एंडी मरे

एजेंसी। नई दिल्ली

दो बार के ओलंपिक पुरुष एकल चैंपियन एंडी मरे ने मंगलवार को पुष्टि की कि वह पेरिस ओलंपिक खेलों के साथ ही अपने करियर का अंत करेंगे।

37 वर्षीय मरे ने मंगलवार को एक्स पर लिखा, अपने आखिरी टेनिस टूर्नामेंट के लिए पेरिस पहुंच गया हूं। ब्रिटेन के लिए प्रतिस्पर्धा करना मेरे करियर का अब तक का सबसे यादगार सप्ताह रहा है और मुझे इसे अंतिम बार करने पर बेहद गर्व है! पेरिस ओलंपिक में टेनिस शनिवार से रोलांड गैरोस के क्ले कोर्ट पर शुरू हो रहा है। मरे ने 2012 लंदन ओलंपिक में विंबलडन में ग्रास कोर्ट पर रोजर फेडरर को लगातार तीन सीटों हराकर अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था।

तादेज पोगाकर ने पेरिस ओलंपिक से नाम वापस लिया

एजेंसी। पेरिस

टूर डी फ्रांस विजेता तादेज पोगाकर पेरिस ओलंपिक में भाग नहीं लेंगे। स्लोवेनियाई राइडर ने थकान के कारण ओलंपिक से हटने का फैसला किया है। स्लोवेनियाई एजेंसी एसटीए ने सोमवार को इस खबर की पुष्टि की, जब पोगाकर ने एक दिन पहले ही डेनमार्क के दूसरे स्थान पर रहे जोनास विंगेगार्ड पर छह मिनट से अधिक की बढ़त के साथ अपना तीसरा टूर जीता था। पोगाकर ने छह चरणों में जीत हासिल की और रेस में अपना दबदबा बनाए रखा, मई में गिरो डे इटालिया जीतने के बाद उनकी जीत और भी प्रभावशाली हो गई। पोगाकर की जीत का तरीका और शुरूआती सीजन की एक दिवसीय दौड़ में दिखाया गया फॉर्म, जो 273 किलोमीटर की ओलंपिक रोड साइकिलिंग रेस के समान है, इसका मतलब है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता अपने पहले से ही शानदार सीजन में ओलंपिक स्वर्ण पदक के लिए पसंदीदा थे। हालांकि, उनके एजेंट एलेक्स कैरेरा ने बताया कि पिछले तीन महीनों में 25 वर्षीय खिलाड़ी ने जो थकान जमा की है, उसके कारण उन्हें पेरिस खेलों से हटने का फैसला लेना पड़ा है। पोगाकर और विंगगार्ड दोनों पेरिस में प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे हैं, इसलिए टूर डी फ्रांस में तीसरे स्थान पर रहने वाले रेम्को इवेनेपेल और वाउट वैन एर्ट की बेल्जियम की जोड़ी पेरिस में नई पसंदीदा होगी, दोनों इवेनेपेल रोड रेस और 32 किलोमीटर के टाइम-ट्रायल में स्वर्ण के लिए चुनौती पेश करेंगे।

राहुल द्रविड़ की बतौर मुख्य कोच आईपीएल में हो सकती है वापसी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व मुख्य कोच राहुल द्रविड़ का कार्यकाल टीम इंडिया के साथ टी20 विश्व कप के बाद खत्म हो गया है। अब वो एक बार फिर मुख्य कोच की भूमिका में आ सकते हैं, हालांकि इस बार वो आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स की कमान संभालने वाले हैं। भारतीय टीम को टी20 विश्व कप 2024 में मुख्य कोच के रूप में सफलतापूर्वक जीत दिलाने के बाद राहुल द्रविड़ कथित तौर पर इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में एक नए रोमांचक सफर की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में उनका कार्यकाल समाप्त होने के बाद द्रविड़ से टी20 लीग में कई फ्रेंचाइजियों ने संपर्क किया।

भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका पहुंची

टी20 श्रृंखला के लिए श्रीलंका टीम की घोषणा, असालांका को मिली कप्तानी

पाल्लेकल। चरित असालांका भारत के खिलाफ 27 जुलाई से शुरू हो रही तीन मैचों की टी20 श्रृंखला में श्रीलंका के कप्तान होंगे। वह टी20 विश्व कप में टीम के जल्दी बाहर होने के बाद इस्तीफा देने वाले स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा की जगह लेंगे। स्पिन हरफनमौला वानिंदु हसरंगा के बाद असालांका को कप्तानी सौंपी गई है। हसरंगा ने अमेरिका और वेस्टइंडीज में पिछले महीने हुए टी20 विश्व कप में श्रीलंका की कप्तानी की थी। असालांका ने इस साल की शुरूआत में बांग्लादेश दौरे पर भी दो टी20 मैचों में श्रीलंका की कप्तानी की थी जब हसरंगा आईसीसी आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबन झेल रहे थे।

02 दिन काउंट डाउन **पेरिस ओलंपिक**

समय-समय पर बदले ओलंपिक मैडलों के डिजाइन

नई दिल्ली। 1896 में जब ओलिम्पिक की शुरूआत हुई थी तो केवल प्रथम और द्वितीय रहे एथलीट्स को ही मैडल दिया जाता था। धीरे-धीरे नियमों में बदलाव हुआ तो मैडलों के डिजाइन भी बदलते गए। मैडलों पर गॉड जीउस, देवी नाइके, जैतून के पेड़ की टाहनियों की छवियां लंबे समय तक रही हैं। इसी बीच पेरिस प्रबंधन ने हालिया गेम्स के मैडलों में एफिल टावर की आकृति भी जोड़ दी है। आइए जानते हैं- कैसे समय-समय पर मैडलों के डिजाइन में बदलाव होते गए।

एथलैंस 1896 : ओलिम्पिक के पहले मैडल

1896 ओलिम्पिक में केवल पहले और दूसरे स्थान पर रहने वाले एथलीटों को मैडल दिए जाते थे। मैडल पर भगवान जीउस की आकृति को एक ग्लोब पकड़े देखा जा सकता है। दूसरी तरफ, एक्रोपोलिस की साइट थी। जिस पर लिखा था।

एम्स्टर्डम 1928 : 44 साल चला यह डिजाइन

1921 में ओलिम्पिक समिति ने मैडल का डिजाइन बदला जोकि करीब आधी सदी तक चला। इसपर विजय की पारंपरिक देवी को एक हाथ में मुकुट और दूसरे हाथ में ताड़ के पत्ते पकड़े दशार्या गया। मैडल के पीछे ओलिम्पिक चैम्पियन को प्रसन्न भीड़ हवा में लहराती दिखती है।

म्यूनिख 1972 : मैडल में बेटे भी किए शामिल

1928 से ओलिम्पिक पदकों के दोनों तरफ की छवियां एक जैसी ही थीं। हालांकि, 1972 में म्यूनिख खेलों के लिए मैडलों में कैस्टर और पोलक्स की छवि जोड़ दी गई। यह दोनों जीउस और लेडा के जुड़वां बेटे थे। 44 वर्षों में पदकों के डिजाइन में यह पहला बदलाव था।

सियोल 1988 : शांति और एकता का प्रतीक

ओलिम्पिक खेलों की भावना को ध्यान में रखते हुए सियोल 1988 के पदकों में महत्वपूर्ण बदलाव हुआ ताकि दुनिया को शांति का संदेश दिया जा सके। पदकों के पीछे की तरफ अपनी चोंच में लॉरेल पत्ती पकड़े हुए कबूतर की छवि धातु पर उकेरी गई।

एथैंस 2004 : देवी नाइके की छवि बदली

1896 के बाद एथैंस में साल 2004 में ओलिम्पिक हुए। इसके लिए मैडलों में बदलाव किए गए। मैडलों पर देवी नाइके को बैठे हुए चित्रित करने के बजाय, उन्हें सर्वश्रेष्ठ एथलीटों को जीत दिलाने के लिए स्टेडियम में उड़ते हुए दिखाया गया था।

बीजिंग 2008 : मैडलों पर बनाया ड्रैगन पैटर्न

बीजिंग ओलिम्पिक के दौरान मैडलों पर पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का एक स्थायी प्रतीकः जेड अंकित किया गया। प्रत्येक मैडल के पीछे एक ड्रैगन पैटर्न भी बनाया गया। पदकों का डिजाइन बड़प्पन, सदाचार, नैतिकता और सम्मान का प्रतीक चुना गया।

टोक्यो 2020 : इलैक्ट्रॉनिक उपकरण इस्तेमाल किए

टोक्यो 2020 मैडल प्रोजैक्ट में कुल 78,985 टन बेकार पड़े इलैक्ट्रॉनिक उपकरणों को इस्तेमाल किया गया। इससे निकले 30.3 किलोग्राम सोना, 4,100 किलोग्राम चांदी और 2,700 किलोग्राम कांस्य निकाला गया और पदकों के निर्माण में पुनः उपयोग किया गया।

पेरिस 2024 : एफिल टॉवर का टुकड़ा डाला

कोई एथलीट अगर पेरिस में स्वर्ण, रजत या कांस्य मैडल जीतता है तो वह अपने साथ पेरिस के प्रतिष्ठित एफिल टावर का टुकड़ा भी लेकर जाएगा। इन मैडलों में टावर के एक हिस्से का लोहा डाला गया है। प्रबंधन की इस पहल ने इस ओलिम्पिक को और भी यूनीक बना दिया है।

व्यापार/लाइफ व साइंस

बाजार को रास नहीं आया बजट

एजेंसी। नई दिल्ली

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया। बजट पेश किये जाने से पहले ही शेयर बाजार में उथल-पुथल देखने को मिल रही थी और जैसे ही टैक्स से जुड़े ऐलान किए गए, तो अचानक बेंचमार्के इंडेक्स सेंसेक्स और निफ्टी क्रैश हो गए। सेंसेक्स 1200 अंक तक फिसल गया। वही, निफ्टी में 400 अंकों की बड़ी गिरावट आई।

शेयर बाजार में भारी उथल-पुथल जारी

इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करना शुरू किया उधर 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स उछल गया। लेकिन, कुछ ही मिनटों में यह लाल निशान में फिसल गया और बाद में दोपहर के कारोबार के दौरान 1,266.17 अंक गिरकर 79,235.91 पर आ गया। हालांकि खबर लिखे जाते समय यह 134.58 यानी 0.17 फीसदी की गिरावट के साथ 80,367.50 पर कारोबार कर रहा था।

कुछ ऐसा ही रुख निफ्टी का भी रहा। जैसे ही वित्त मंत्री ने लोकसभा में अपना 7वां केंद्रीय बजट पेश करना शुरू किया,

सेंसेक्स 1200 अंक तक फिसल गया। वही, निफ्टी में 400 अंकों की बड़ी गिरावट आई

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, जल्द ही अस्थिर रुझान आने लगे और बेंचमार्क बाद में 435.05 अंक गिरकर 24,074.20 पर पहुंच गया। खबर लिखे जाते समय यह 17 अंक यानी 0.07 फीसदी की मामूली गिरावट के साथ 24,492.25 अंक पर कारोबार कर रहा था।

कैपिटल गेन टैक्स में इजाफे का ऐलान शेयर बाजार को रास नहीं आया

शेयर बाजार में गिरावट की सबसे बड़ी वजह कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा रहा। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में इजाफा करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि एक साल से कम के टेन्योर या होल्डिंग पीरियड के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया गया है और जिन निवेशकों की शेयरहोल्डिंग 1 साल यानी 12 महीने से ज्यादा है, उनके द्वारा शेयरों से हुई कमाई पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 12.5 फीसदी का लगेगा। जबकि पहले इस पर 10 फीसदी टैक्स लगता था।

हालांकि आम बजट में वित्त मंत्री ने निवेशकों को एक राहत भी दी है। सीतारमण ने कुछ निश्चित एसेट्स को लेकर कैपिटल गेन एग्जम्प्शन लिमिट यानी शेयर से हुई कमाई पर छूट की दर को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये सालाना कर दिया गया। पहले यह सीमा 1लाख रुपये सालाना थी।

शेयर बाजार में गिरावट की दूसरी वजह बढ़ाने का प्रस्ताव है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को वायदा और विकल्प कारोबार में प्रतिभूति लेनदेन कर की दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा।

लंबी अवधि में शेयर बाजार में होगा ज्यादा फायदा एलटीसीजी छूट बढ़ी

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया। वित्त मंत्री ने बजट में एक तरफ सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) में बढ़ोतरी की तो दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट में भी इजाफा किया। वित्त मंत्री की ओर से फ्यूचर और ऑप्शन पर लगने वाली सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स (एसटीटी) को बढ़ाकर 0.02 प्रतिशत और 0.1 प्रतिशत कर दिया गया है। डेरिवेटिव सेगमेंट में ऑप्शन को सेल पर विक्रेता की ओर से 0.0625 प्रतिशत एसटीटी अदा किया जाएगा। वहीं, इस पर 0.125 प्रतिशत एसटीटी ऑप्शन खरीदार की ओर से दिया जाएगा। फाइनेंस बिल के मुताबिक नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। वित्त मंत्री ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन (एसटीसीजी) टैक्स को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। वहीं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (एलटीसीजी) टैक्स को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है।

बिना इंटरनेट के वॉट्ससेप पर शेयर कर पाएंगे फाइल

एजेंसी। नई दिल्ली

ऐपल डिवाइस में एयरड्रॉप फीचर दिया जाता है, जिसकी मदद से दो ऐपल डिवाइस के बीच बिना इंटरनेट के बड़ी सी बड़ी फाइल को ट्रांसफर किया जा सकता है। यह बेहद फास्ट प्रोसेस है। वैसे तो मार्केट में कई अन्य फीचर जैसे ब्लूटूथ मौजूद हैं, लेकिन इनकी स्पीड कम होती है। ऐसे में वॉट्सऐप भी ऐपल एयर ड्रॉप की तर्ज पर एक नया फीचर ला रहा है, जिसकी मदद से दो वॉट्सऐप यूजर्स बिना इंटरनेट की मदद से फाइल ट्रांसफर कर पाएंगे। टेस्टिंग एंड्रॉइड यूजर्स के लिए शुरू हो गई है।

▸ बिना इंटरनेट ट्रांसफर होगी फाइल

यह फीचर एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होगी। इसमें बिना इंटरनेट कनेक्शन के फाइल एक डिवाइस से दूसरे में ट्रांसफर कर पाएंगे। हालांकि डिवाइस में लिमिटेशन होने की वजह से उन्हें फाइल ट्रांसफर के लिए एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा, जिसे एंड्रॉइड डिवाइस में दिया जाएगा। इस फीचर को लेटेस्ट वॉट्सऐप बीटा अपडेट में स्पॉट किया गया है। फिलहाल यह फीचर इंटरनल टेस्टिंग के लिए उपलब्ध है। यह फीचर आप पब्लिक के लिए कब उपलब्ध होगा, फिलहाल इस बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

▸ क्या होगा फायदा?

मौजूदा वक्त में फाइल वॉट्सऐप से ट्रांसफर करने के लिए इंटरनेट की जरूरत होती है। हालांकि बिना इंटरनेट फाइल ट्रांसफर से यूजर्स को काफी राहत हो सकती है। खासतौर पर उन यूजर्स के लिए जिनके एरिया में नेटवर्क कवरेज की दिक्कत होती है।

▸ आ रहे ये फीचर्स

वॉट्सऐप एक अन्य फीचर पर काम कर रहा है, जिसमें वॉट्सऐप अपने यूजर्स को प्रोफाइल के लिए यूजरनेम बनाने की छूट देगा। साधारण शब्दों में समझें, तो आपको चैटिंग, वॉइस कॉल और वीडियो कॉल के लिए मोबाइल नंबर साझा नहीं करना होगा।

हीरो सर्ज ईवी को मिला प्लैटिनम ए डिजाइन अवार्ड

एजेंसी। नई दिल्ली

मोटरसाइकल और स्कूटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प को हीरो सर्ज ईवी के लिए प्रतिष्ठित प्लैटिनम ए डिजाइन अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अब आप सोट रहे होंगे कि सर्ज ईवी क्या है और इसे अवॉर्ड किसने दिया है। इसका जवाब यह है कि इस साल जनवरी में हीरो मोटोकॉर्प ने जयपुर में एक इवेंट के दौरान सर्ज एस32 ईवी को अनवील किा था और बाद में फरवरी 2024 में मोबिलिटी एक्सपो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। हीरो सर्ज ईवी एक ऐसी गाड़ी है, जो महज 3 मिनट में स्कूटर से 3-व्हीलर बन जाता है। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी सर्ज ईवी को ऐसे डिजाइन किया है कि यह स्कूटर के रूप में इस्तेमाल में आ सकती है और जरूरत पड़ने पर इसे तिपहिया वाहन की शक्ल देकर इससे बिजनेस भी किया जा सकता है।

सिर्फ 3 बटन दबाकर बदल सकते हैं मोड्स

हीरो सर्ज ईवी को प्रतिष्ठित प्लैटिनम ए डिजाइन अवॉर्ड वीइकल, मोबिलिटी एंड ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन कैटिगरी में मिला है। सर्ज ईवी सिर्फ 3 मिनट में टू-व?हीलर से थ्री-व?हीलर में आसानी से बदल जाने की अनोखी क्षमता रखता है। वाहन के प्रकार को बदलने की पहल करने वाले सर्ज ईवी में एक इंटेलिजेंट यूजर इंटरफेस है, जो वाहन के टाइप के अनुसार ऑटोमैटिक तरीके से एडजस्ट हो जाता है। यूजर्स सिर्फ 3 बटनों का इस्तेमाल कर इसके मोड्स को आसानी से बदल सकते हैं।

हीरो मोटोकॉर्प की खास पहल

आपको बता दें कि हीरो मोटोकॉर्प ने सर्ज एस32 का विकास सिर्फ चार साल पहले शुरू हुआ था। यह काम हीरो मोटोकॉर्प के इन-हाउस इंक्युबेशन सेंटर हीरो हैच में हुआ था।

भारत के पास नवीकरणीय ऊर्जा, दूरसंचार में एफडीआई को आकर्षित करने की क्षमता : आर्थिक सर्वे

एजेंसी। नई दिल्ली

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-2024 में कहा गया कि नवीकरणीय ऊर्जा जैसी ग्रीनफील्ड परियोजनाओं, दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर जैसी डिजिटल सेवाओं और परामर्श सेवाओं जैसे क्षेत्रों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को आकर्षित करने के लिए भारत के पास एक बेहतर बुनियादी ढांचा है।

मध्यम अवधि में, भारत पश्चिम के साथ अपने वैल्यू चेन को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, खासकर नवीकरणीय ऊर्जा, एआई, सेमीकंडक्टर और अगली पीढ़ी के दूरसंचार सहित उन्नत प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में।

सर्वेक्षण में कहा गया है कि इस रणनीति को ऑस्ट्रेलिया-भारत मुक्त व्यापार समझौते और यूएस-भारत स्वच्छ ऊर्जा पहल जैसे समझौतों के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।

सर्वेक्षण के अनुसार, "इसी का नतीजा है, इन क्षेत्रों के भीतर ट्रेंडिंग पैटर्न विकसित होने लगे हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकी जैसे सौर वॉटर हीटर, अपशिष्ट रीसाइक्लिंग उपकरण और पवन टर्बाइन का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ वित्त वर्ष 2020 में 199.2 मिलियन डॉलर के मुकाबले बढ़कर वित्त वर्ष 2024 में 326.9 मिलियन डॉलर हो गया है।"

इसके अलावा, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में अग्रणी अमेरिकी और यूरोपीय कंपनियों, जैसे फर्स्ट सोलर, वेस्टा और स्कैटेक ने ग्रीन टेक्नोलॉजी की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए भारत में अपने संयंत्र स्थापित किए हैं।

एक नजर

शहीद हवलदार के परिजनों को किया गया सम्मानित

लातेहार । राजकीयकृत प्लस टू उच्च विद्यालय (अब मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय) ने सीआरपीएफ के 60वीं बटालियन के शहीद हवलदार विरेंद्र कुमार शर्मा के परिजनों को आज मंगलवार को सम्मानित किया। विरेंद्र शर्मा की स्मृति में कमांडेंट वीपी त्रिपाठी के निर्देश पर शहीद हवलदार की मां और अन्य परिजनों को सहायक कमांडेंट राजीव रंजन प्रताप ने शॉल व अन्य उपहार भेंट कर किया। मौके पर विद्यालय की प्राचार्य तृप्ति भारती, उप प्राचार्य नरेंद्र पांडेय, वरीय शिक्षक विद्युत ओझा, संतोष कुमार समेत कई शिक्षक व छात्र-छात्राएं मौजूद रहे। बता दें कि शहीद हवलदार शर्मा लातेहार निवासी थे और उन्होंने मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय में अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी।

स्तरोन्नत उच्च विद्यालय में हुआ बाल संसद का गठन

हरिहरगंज । पिपरा प्रखंड के स्तरोन्नत उच्च विद्यालय पिपरा में मंगलवार को विद्यालय के बच्चों के बीच वोटिंग के द्वारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बाल संसद का गठन किया गया। इस दौरान सूर्यकांत को प्रधानमंत्री, निरंजन को उप प्रधानमंत्री, नैंसी को अध्यक्ष, गरिमा को वित्त मंत्री, दिव्या को स्वास्थ्य मंत्री, खुशबू को स्वच्छता मंत्री, रितु को पर्यावरण मंत्री, हिमांशु को कौशल विकास मंत्री, अमित को खेलकूद एवं सांस्कृतिक मंत्री, अंकुश को सुरक्षा एवं न्याय मंत्री, नैंसी को शिक्षा मंत्री चुना गया। इस मौके पर प्रधानाध्यापिका अनुपमा ज्योति ने कहा कि बाल संसद विद्यालय के बच्चों का एक मंच है, जहां वे अपने विद्यालय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य शिक्षा और अपने अधिकारों की बात खुलकर करते हैं।

समाजसेवी के प्रयास से लगा नया ट्रांसफार्मर लोगों ने जताया आभार

हरिहरगंज । हरिहरगंज नगर पंचायत अंतर्गत पिपरा मोहल्ला में समाजसेवी राजीव रंजन के पहल पर नया ट्रांसफार्मर लगाया गया। बीते दो सप्ताह पहले ट्रांसफार्मर जल जाने के कारण बिजली आपूर्ति ठप हो गयी थी। इस वजह से मोहल्ले वासियों को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। मोहल्ले के लोगों ने समाजसेवी राजीव रंजन को उक्त समस्या से अवगत कराया था। वही संज्ञान लेते हुए श्री रंजन ने विद्युत विभाग के पदाधिकारी से उक्त विषय पर चर्चा कर 100 केवीए का नया ट्रांसफार्मर उपलब्ध कराया। ट्रांसफार्मर चालू हो जाने से मोहल्ले वासियों ने राजीव रंजन के प्रति आभार प्रकट किया। आभार प्रकट करने वालों में अनुज सिंह, दीपक सिंह, सोनू कुमार, अखिलेश पासवान, राघव पांडेय, धीरेंद्र पासवान, रोशन पांडेय, प्रदीप पासवान, सरोज सिंह, महेंद्र राम, जनेश्वर राम, उदय पासवान, मुन्ना पासवान, संजय पासवान, पवन पासवान, ललन पासवान आदि का नाम शामिल है।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना शिविर में 188 ग्रामीणों ने दिया आवेदन

नवीन मेल संवाददाता

हैदरनगर। उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश व निर्धारित समय अनुसार मंगलवार को मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से लोगों को आच्छादित करने को लेकर विशेष शिविर का आयोजन किया हैदरनगर प्रखंड कार्यालय के प्रांगण में किया गया। इस शिविर में विभिन्न पंचायत से आए सैकड़ों ग्रामीणों को बीडीओ विश्व प्रताप मालवा ने योजना के उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगार युवक व युवतियों को आत्म निर्भर बनाने के विभिन्न व्यवसायों को शुरू करने बेहतर अवसर दिया है। इसके प्रति उन्होंने जागरूकता के साथ प्रेरित किया कि इस योजना के स्वीकृत ऋण राशि का 40 फीसदी अनुदान राशि लाभुकों के खता में सीधे चली जायेगी। इस शिविर का निरीक्षण के बाद एसडीओ पियूष सिन्हा ने कहा कि राज्य में बेरोजगारी दर में कमी लाने के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। जिसमें युवाओं को इस योजना से अधिकाधिक लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत प्राप्त आवेदनों का समेकित रिपोर्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी, कल्याण पदाधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है। शिविर में प्रखंड कल्याण पदाधिकारी अमरेश कुमार समेत अन्य कई कर्मी के अलावा स्थानीय सीएसपी संचालकों को तत्काल प्राप्त आवेदनों को निष्पादन के लिए सभी उपकरण के साथ मुस्तैद किया गया है।जो आवेदनों को ऑन स्पॉट एंट्री करेंगे। प्रखंड कृषि पदाधिकारी अमरेश कुमार

ने बताया कि

इस योजना के तहत विभिन्न वर्ग के लोगों को व्यवसाय शुरू करने के लिए सरकार की ओर से ऋण 40 प्रतिशत अनुदान के साथ ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदकों को अपने साथ आधार व पैन कार्ड, जाति, आवासीय व आय प्रमाण पत्र की छायाप्रति, सरकारी नौकरी में नहीं होने का शपथ पत्र देना है। वाहन लेने वाले इच्छुक आवेदकों को वाहन का अद्यतन कोटेशन देना होगा। इच्छुक अहताधारी बेरोजगार युवक व युवतियों के पास आदि उपरोक्त जरूरी दस्तावेज वर्तमान में नहीं भी है तो आवेदन कर सकते हैं। किन्तु उक्त दस्तावेज को निर्गत कराने के बाद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा। इसके बाद ही उनके आवेदन के स्वीकृति के लिए ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। सुबह 10 बजे से शुरू इस शिविर में कुल 188 ग्रामीणों ने आवेदन सौंपा है। उन्होंने बत्शाया कि इसमें 12 ऑनलाइन में 50000 से कम तीन और नौ आवेदन इससे ऊपर के ऋण राशि स्वीकृति के लिए प्राप्त है। जबकि 176 आवेदन ऑफलाइन प्राप्त है। जिसकी जांच के बाद ऑनलाइन अपलोड किया जायेगा। शिविर में उनके अलावे 20 सूत्री अध्यक्ष बिमलेश सिंह, पूर्व मुखिया नावाजिश खान, नागेंद्र मेहता व सफिउल्ला खान, पंसस राजीव कुमार शर्मा सहित काफी संख्या में ग्रामीण उपस्थित थे।

जनता को सुविधाएं उपलब्ध कराना जनप्रतिनिधि का कर्तव्य : मंत्री मिथिलेश

गढ़वा । पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर ने सोमवार को गढ़वा विधानसभा क्षेत्र के डंडा प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न गांवों में जनता संवाद का आयोजन किया। इस दौरान मंत्री ठाकुर ने भिखही पंचायत के पपरवा टोला में रामा चौधरी के घर के समीप, भिखही गांव में दुर्गा मंडप के समीप, ग्राम छपरदागा के महुरान टोला में जनता संवाद का आयोजन किया। इस दौरान लोगों की समस्या सुनते हुए कई समस्याओं का ऑन द स्पॉट निदान किया। साथ ही शेष समस्याओं का यथाशीघ्र निदान करने की बात कही। कार्यकताओं एवं ग्रामीणों ने मंत्री का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ठाकुर ने कहा कि जब से आपने मुझे अपना आशीर्वाद देकर सेवक चुना है तब से मैं एक दिन भी चैन से नहीं बैठा हूं। लगातर आपके बीच रह कर आपकी सेवा में, आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयासरत हूं। बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, खेल सभी क्षेत्रों में काफी बेहतर कार्य किया हूं। यहां तक कि गढ़वा के लोगों ने मुझे दो बार हार का भी स्वाद चखाया फिर भी मैं जनसेवा में लगा रहा। आपने जो सेवा का आशीर्वाद दिया इसके लिए मैं आजीवन आभारी रहूंगा। कहा कि आज से साढ़े चार वर्ष पूर्व डंडा की क्या स्थिति थी और आज क्या है।

न्यूज बॉक्स

नाबालिग लड़की को हुसैनाबाद पुलिस ने किया बरामद

हुसैनाबाद। बीते सोमवार की देर शाम हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव से फरार हुई 16 वर्षीय नाबालिग लड़की को हुसैनाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया। इस मामले में लड़की की मां ने शादी की नीयत से बिहार के गया जिला के झंगट गांव निवासी अमन कुमार के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। दर्ज प्राथमिकी में बताया की बीते 17 जुलाई को कपड़ा और कुछ कागजात लेकर चुपके से घर से निकल गई थीं, देर शाम तक घर नहीं लौटने पर अपने स्तर से काफी खोजबीन की। लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। बाद में मुझे पता चला की वह किसी लड़के के साथ मोबाइल पर बात करती थी, तब पता चला की एक लड़का जिसका नाम अमन कुमार है मुझे पूर्ण विश्वास है की मेरी लड़की को उसने ही बहला फुसलाकर भगा ले गया है। लड़की के मां के लिखित आवेदन पर हुसैनाबाद थाना प्रभारी संजय यादव ने इस मामले को गंभीरता पूर्वक लेते हुये वरीय पुलिस पदाधिकरी के निर्देश पर एक टीम गठित कर मोबाइल लोकेशन के अधार पर लड़की को गया जिला के डुमरिया से बरामद कर थाना ले आई। पूछताछ के बाद उसे मंगलवार को मेडिकल जांच हेतु एमएचसीएच मेदिनीनगर भेज दिया।

हुसैनाबाद विधायक कमलेश सिंह ने आम बजट का किया स्वागत

हुसैनाबाद। आम बजट 2024 पर एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष सह विधायक कमलेश कुमार सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का वह स्वागत करते है। उन्होंने कहा कि यह विकसित भारत का बजट है।

इसमें युवा, गरीब, महिला, किसान के सशक्तिकरण के लिए समर्पित है। बजट विकसित भारत के भविष्य निर्माण का बेहतरीन बजट है।आदिवासियों की आर्थिक- सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरूआत करने की घोषणा की गई है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पूर्वोत्तर व पूर्वी भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देंगी। कौशल और रोजगार सृजन की दिशा में बजट प्रभावी है। बजट में सभी का खयाल रखा गया है। रोजगार सृजन से लेकर अर्थव्यवस्था की मजबूती को प्राथमिकता दी गई है।

मेगा कैंप से लाखों ग्रामीण मजदूर, युवा और युवतियों को स्वरोजगार पाने का मिला मौका

नौडीहा बाजार। प्रखंड के अंचल कार्यालय में मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत मेगा शिविर कैंप का आयोजन किया गया।इस मेगा कैंप में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, एवम कल्याण विभाग अधिकारी पूरी उपकरण के साथ मौजूदा उपस्थित रहे।इस मेगा कैंप में प्रखण्ड के सभी पंचायतों के यूवा युवती ग्रामीण बेवसायी मजदूर अधिक मात्रा में लाभान्वित हुए।बता दे की मेगा कैंप का आयोजन कर अवेदन प्राप्त किया गया। सभी प्राप्त आवेदनों को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी बीडीओ एवम कल्याण विभाग पदाधिकारी के द्वारा सत्यापन कर बारीकी से इंट्री करवाया गया।बता दे की इस योजना के तहत विभिन्न वर्गों के लोगों को व्यवसाई शुरू करने के लिए राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई योजना से ऋण उपलब्ध करवाने के लिए सभी आवेदनों को स्पष्टीकरण किया गया। बीडीओ शुभम बेला टोपनो ने बात चीत के दौरान यह बताया कि जिस तरह ग्रामीण मजदुर यूवा,युवतीयां अपनी जिस उम्मीद से अवेदन कर रहे है।और अवेदन प्राप्त किए जा रहे है। ठीक उसी प्रकार से कड़ी प्रबलता के साथ जिला मुख्यालय के द्वारा स्पष्टीकरण कर जल्द ही ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ताकि अपना स्वरोजगार करने में कायम होंगे। शिविर में उपस्थित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी शुभम बेला टोपनो, कल्याण विभाग पदाधिकारी प्रमोद कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ हीरा कुमार,जिला परिषद सुदामा पासवान, ब्लॉक प्रमुख रेशमी कुमारी मौजूदा उपस्थित रहे।

जनता दरबार के माध्यम से मिलने आए आमजनों की समस्याएं सुनी

नवीन मेल संवाददाता

चतरा। आज के जनता दरबार में चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र के चुड़िहार मुहल्ला के रहने वाले ने अपने आवेदन के माध्यम से बताया कि मै मुम्बई में मजदूरी का कार्य करता हूँ जो मै पिछले साल अपने घर आने के क्रम मे मुम्बई रेलवे स्टेशन पर मेरे दोनो पैर कट गया है। जो मै चलने फिरने में बिलकुल असहाय हुँ और मै चतरा सदर अस्पताल में दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गया तो वहां मुझसे राशि की मांग की जाती है । मेरे द्वारा राशि नहीं देने पर बोला जाता है कि प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। इस संदर्भ में अपर समाहर्ता ने मामले को संज्ञान में लेते हुए सिविल सर्जन चतरा को मामले की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने की बात कही। इसी प्रकार जन वितरण प्रणाली के संबंध

में ग्रामीण जनता ग्राम पंचायत कोलकोले कला, प्रखंड लावालौंग चतरा एवं अन्य से जनता दरबार में जनवितरण प्रणाली दुकानदार शबीहा खातून ग्राम पंचायत कोलकोले के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हुई। इस पर अपर समाहर्ता ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को कहा गरीबों के निवाले गटकने वालो के ऊपर जांच कर तत्काल प्रभाव से अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए उनके द्वारा गबन किए गए अनाज के समतुल्य राशि का वसूली करे। जनता दरबार का आयोजना समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में अपर समाहर्ता अरविंद कुमार की अध्यक्षता में की गई। उन्होंने एक एक कर जनता दरबार के माध्यम से समस्याओं को लेकर मिलने आए आमजनों की समस्याएं सुनी। उक्त के अलावे जनता दरबार में मुख्य रूप से अबुआ आवास, भूमि विवाद, राशन कार्ड, दिव्यांग पेंशन, सड़क, दिव्यांग उपकरण, अनुकंपा से संबंधित समेत अन्य मामला शामिल है।

एसीबी ने एएसआई को 20 हजार रुपये घूस लेते किया गिरफ्तार

नवीन मेल संवाददाता

लातेहार। पलामू की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने लातेहार के बारियातू थाना में पदस्थापित पुलिस अवर निरीक्षक (एएसआई) धीरेंद्र कुमार को रंगे हाथ 20 हजार घूस लेते गिरफ्तार किया है। एसीबी के प्रमंडलीय कार्यालय पलामू ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी। जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बारियातू थाना में अफीम रखने के मामले में एक मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में वादी के भतीजे को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। एएसआई धीरेंद्र कुमार ने कुछ दिनों बाद इसी कांड में वादी को फंसाने की धमकी देकर तीन लाख की मांग की थी। वादी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। लेकिन एएसआई ने वादी पर लगातार पैसे के लिए दवाब बनाया। इसके बाद वादी ने एसीबी से इसकी शिकायत

की। एसीबी के पुलिस उपाधीक्षक ने इस मामले का सत्यापन किया। मामला सत्य पाये जाने पर एसीबी की पलामू छापेमारी टीम ने दंडाधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों के सामने धीरेंद्र कुमार को 20 हजार घूस लेते गिरफ्तार किया। धीरेंद्र कुमार बिहार के कैमूर जिले के हरिनाथपुर स्थित अहिनौरा गांव के रहने वाले हैं। इस मामले में एसीबी ने 22 जुलाई को पलामू थाना कांड संख्या 06/2024 दर्ज किया है।

पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, सभी लोगों को लगाने की जरूरत है : कमलेश

नवीन मेल संवाददाता

सगालीम। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर विवेकानंद विद्या मन्दिर कुन्दरी में 111 पौधे का रोपण एवं चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। बता दें कि कुन्दरी में हो रहे संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल अपनी अनूठी पहचान बनाती जा रही है। जहां एक ओर आधुनिकता की धमक में युवा पीढ़ी खोती जा रही है, वहीं दूसरी ओर स्वामी विवेकानंद जी के प्रेरणा से संचालित विवेकानंद विद्या मंदिर कुन्दरी भारतीय संस्कृति और परंपरा को जीवंत करने का प्रयास कर रही है। विद्यालय में दिनांक 21 जुलाई 24 को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरुओं के पूजन के साथ सभी छात्रों को इसके महत्व और दृष्टिकोण से अवगत कराया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री शुभम कुमार ने उपस्थित छात्रों और अभिभावकों को बताया कि लगभग 3000 ई.पूर्व

पहले आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा के दिन महाभारत के रचयिता वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास जी के सम्मान में हर वर्ष आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का दिन माना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन वेद व्यास जी ने भागवत पुराण का ज्ञान भी दिया था। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा नाम से भी जाना जाता है। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरुजनों के सम्मान और उन्हें गुरु दक्षिणा देने का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस दिन अपने गुरु और गुरु तुल्य वरिष्ठजनों को मान-सम्मान देते हुए उनका आभार जरूर व्यक्त करना चाहिए। साथ ही जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए उन्हें गुरु दक्षिणा देने का भी महत्व है।

पंचायत कर्मियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

नवीन मेल संवाददाता

हुसैनाबाद। निकाय में कार्यरत दैनिक, मानदेय कर्मी का सेवा नियमित करने की मांग के समर्थन में हुसैनाबाद में कार्यरत कर्मियों ने हुसैनाबाद विधायक के नाम मांग पत्र सौंपा। विधायक कमलेश कुमार सिंह की अनुपस्थिति में मांगपत्र विधायक के आवासीय कार्यालय में मौजूद हंसराज सिंह को मांग पत्र समर्पित किया। हंसराज सिंह ने कर्मियों से विधायक की बात वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम कराया। विधायक ने उन्हें आश्वासन दिया की उनकी मांगें जायज हैं। वह इसके लिए विधानसभा में आवाज बुलंद करने का काम करेगें। कर्मचारियों की मांगों में निकाय कर्मी का वेतन भुगतान के लिए सरकार अपने स्तर से शत-प्रतिशत आवंटन निर्गत करें, निकाय में सेवा निवृत्त होने वाले कर्मियों का तमाम

तरह का सेवानिवृत्ति लाभ, सेवा निवृत्ति का भुगतान सरकार अपने कोष से करें, निकाय, निगम में उच्चतर पदों पर निकाय कर्मियों से ही पदोन्नित प्रदान किया जाए, आउटसोर्सिंग का मजदूरी का भुगतान सरकार अपने स्तर से कर भ्रष्टाचार समाप्त करें, जीवन बीमा का लाभ निकायकर्मियों को सरकार द्वारा किये जाने आदि मांगे शामिल है। उन्होंने आंदोलनात्मक कार्यकम की जानकारी देते हुए बताया कि 23 जुलाई 2024 से 27 जुलाई 2024 तक अपने-अपने निकाय मुख्यालयों में मशाल जुलुस निकाल कर विरोध किया जाएगा। उन्होंने बताया कि सता दल के विधायकों के आवास के समक्ष 06 अगस्त 2024 को मांगों के समर्थन में घरना दिया जायेगा।जबकि 12 अगस्त 2024 को मुख्यमंत्री आवास के समक्ष राज्यस्तरीय प्रदर्शन होगा, मांगें पूरी नहीं होने पर अनश्चितकालीन हड़ताल किया जायेगा। ज्ञापन सौंपने वालों में झारखंड लोकल बॉडी इंपलाई फेडरेशन के हुसैनाबाद अध्यक्ष उमेंद्र ठाकुर के अलावा प्रदीप कुमार पासवान, अवधेश कुमार, रवि कुमार व मंटू पटेल आदि लोग शामिल थे।

इंप्लाई फेडरेशन के आह्वान पर नगर पंचायत कर्मियों ने विधायक को सौंपा ज्ञापन

पेज एक का शेष

देश के हर वर्ग...

ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 वर्षों में लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इस गति को आगे बढ़ाते हुए, यह बजट हमारे नव-मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को और अधिक ऊर्जा देगा। हमारी युवा पीढ़ी को अभूतपूर्व अवसर मिलेंगे। शिक्षा और कौशल विकास एक नए स्तर पर पहुंचेंगे, जिससे हमारे देश की वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, यह बजट मध्यम वर्ग को पहले से कहीं अधिक सशक्त बनाएगा! पीएम ने कहा, हमें हर शहर, हर गांव, हर घर एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसी उद्देश्य से बिना गारंटी के मुद्रा लोन की लिमिट को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये किया गया है। इससे छोटे कारोबारियों, विशेष रूप से महिलाओं, दलित, पिछड़े और आदिवासी परिवारों में स्वरोजगार को बल मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार ने पिछले 10 साल में ये सुनिश्चित किया है कि गरीब और मध्यम वर्ग को टैक्स से राहत मिलती रहे। इस बजट में भी इनकम टैक्स में कटौती और स्टैंडर्ड डिडक्शन में वृद्धि का बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। टीडीएस के नियमों को भी सरल किया गया है। इन कदमों से हर टैक्सपेयर को अतिरिक्त बचत होने वाली है। पीएम ने कहा, इस बजट का एक बहुत बड़ा फोकस देश के किसान हैं। अन्न भंडारण के लिए दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम के बाद अब हम सब्जी उत्पादन क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इससे छोटे किसानों को सब्जियों-फल, अन्य उपज के लिए नए बाजार मिलेंगे और बेहतर दाम मिलेंगे। मोदी ने कहा, देश में गरीबी समाप्त हो, गरीब का सशक्तिकरण हो, इस दिशा में भी आज के बजट में प्रमुख घोषणाएं की गई हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ नए घर बनाना तय हुआ है। जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, सैचुरेशन अप्रोच के साथ 5 करोड़ आदिवासी परिवारों को मूलभूत सुविधाओं से जोड़ेगा। इसके अलावा ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 25 हजार नए ग्रामीण क्षेत्रों को ऑल वेदर रोड से जोड़ा जाएगा।

राज्य के विकास में...

जूनियर इंजीनियर (मैकेनिकल) मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर, माइनिंग इंस्पेक्टर, जूनियर इंजीनियर (इलेक्ट्रिकल), स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर, पाइपलाइन इंस्पेक्टर पद के 183 अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।कार्यक्षमता का बेहतर उदाहरण पेश करें नवनियुक्त अभ्यर्थीमुख्यमंत्री ने कहा कि आज टाउन प्लानर की नियुक्ति हुई है। उनका प्रयास होना चाहिए कि शहर का सर्वांगीण विकास कैसे हो। आपकी सूझबूझ और अनुभव के आधार पर राज्य के शहरों को एक नई दिशा मिलेगी। आप ईमानदारी से कम करें तथा बेहतर कार्य कर अपनी क्षमता का प्रदर्शन करें। आप राज्य के विकास में बेहतर कार्य करेंगे तो सरकार आपको सम्मानित करेगी। सिर्फ यूपीएससी से ही चयनित नहीं, बल्कि जेपीएससी और जेएसएससी से चयनित अभ्यर्थियों को भी अच्छे कार्य के लिए सम्मानित करने का कार्य राज्य सरकार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड में खनन की गतिविधि अन्य राज्यों से अलग है। राज्य में माइनिंग इंस्पेक्टर की भूमिका महत्वपूर्ण साबित होगी। राज्य के 24 जिलों में से आधे से अधिक जिलों में खनन की गतिविधियां होती हैं। खनन कार्य अव्यवस्थित नहीं, बल्कि सुव्यवस्थित तरीके से हो यह हम सभी की नैतिक जिम्मेवारी है। खनन कार्य के विषय को गंभीरता से लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोग आने वाले समय में खनन कार्य सिस्टमैटिक ढंग से करें, जिससे यहां के जान-माल को खतरा न हो तथा खनिज संपदाओं का लाभ राज्यवासियों को मिल सके।

एमएमसीएच का विवादों से नहीं छूट रहा नाता

नवीन मेल संवाददाता

मेदिनीनगर। अलग-अलग मामलों को लेकर मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल सुर्खियों में बना रहता है। कभी मूलभूत सुविधा के अभाव, कभी पेयजल की कमी कभी डॉक्टर एवं अन्य कर्मचारियों का अभाव तो कभी गंदगी का अंबार सहित कई मामले रोज उजागर होते हैं फिर भी यहां की व्यवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है। बताते चलें की 2019 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा पलामू में निर्मित किए गए मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। इसके अंतर्गत कॉलेज को नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय से संबद्धता दी गई थी और यह राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय भी है। इस कॉलेज का स्थापना होने के साथ ही पलामू जिला सदर अस्पताल को कॉलेज से जोड़ते हुए मेडिकल अस्पताल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। जिससे पलामू के लोगों में आशा की किरण जगी थी क्योंकि सदर अस्पताल से कई लापरवाही से जुड़े मामले पूर्व में उजागर हुआ करते थे,और चिकित्सीय सुविधाओं का खास अभाव था। लेकिन मरीज को लेकर लोगों में जागी अपेक्षा ढाक के तीन पात बनकर रह गई। अव्यवस्थित अस्पताल, यत्र तत्र

फैला हुआ कचरा, मरीज के द्वारा प्रयोग किए गए बिखरे हुए तकिए और बेडशीट, शौचालय में पानी के अभाव में प्रयोग करने हेतु बिखरे पड़े खरीद कर लाए गए बोतल, जीर्णझशीर्ण अवस्था में शौचालय तथा स्नानागार गंभीर रूप से घायल मरीज का इलाज की जगह रेफर यही इसकी पहचान बन चुकी है।विदित हो कि मेदिनीराय मेडिकल अस्पताल में पलामू समेत गढ़वा लातेहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्से तथा यूपी के रेणुकूट सोनभद्र के लोग भी यहां अपना इलाज करने पहुंचते हैं। समय-समय पर मरीजों की मरीजों तथा समाजसेवियों की शिकायत पर जिला प्रशासन अपने स्तर से व्यवस्था सुधारने का प्रयास तो करता है लेकिन कुछ दिनों तक हालत में सुधार आने के बाद पूर्ववत ही हो जाती है। पलामू उपायुक्त शशि रंजन ने मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का औचक निरीक्षण बीते 5 जुलाई को किया था। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों को उपलब्ध की जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने सिविल सर्जन को पुरानी खिड़कियों को बदलवाने तथा नया पर्दा लगवाने व बेडशीट चेंज करने के भी निर्देश दिए थे। उपायुक्त ने यह भी आदेश दिया था की जर्जर पड़े भवन को ध्वस्त कर वॉशिंग परिसर और शौचालय बनाने, अस्पताल में एमआरआई,नए सीटी स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीन लगाने के साथ पुराने ऑपरेशन थिएटर मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर में बदलने को भी निर्देशित किया था। उपयुक्त निर्देश पर नर्स के तथा इमरजेंसी मरीज हेतु केबिन का निर्माण किया जा रहा है लेकिन मूलभूत सुविधाओं में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। अस्पताल में आपातकालीन सेवाओं में इलाज कॉन्ट्रैक्ट पर रखे गए तीन-चार कर्मचारियों के द्वारा की जाती है जिन्हें काफी कम मानदेय मिलता है जिस कारण वे लगन से कार्य नहीं करते। पूर्व में सदर एसडीओ अनुराग तिवारी के निर्देश पर खराब पड़े आरओ मशीन को बदलकर ठीक करने तथा साफ सफाई का ध्यान रखने क्या आदेश को भी अनसुना कर दिया गया। अस्पताल परिसर में सोमवार के सुबह मिले नवजात शिशु के शव ने हड़कंप मचा दी साथ ही अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल भी खड़ा कर दिया।

कृषि गोष्ठी में किसानों को दी खरीफ फसल की नई तकनीक की जानकारी

नवीन मेल संवाददाता

हैदरनगर। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन योजना के तहत मोकहर कला ग्राम सह पंचायत मुख्यालय में किसानों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिसमें खरीफ फसल वर्ष 2024 - 2025 के लिए की जाने खेती के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। कृषि अनुसंधान केन्द्र चियांकी (मेदिनीनगर) के कृषि वैज्ञानिक अभिषेक पटेल ने कहा कि इस क्षेत्र के किसान अच्छी खेती और उपज के प्रति कम संसाधन के बावजूद के काफी मेहनती और सजग है। उन्हें वर्षापात का लगातार आघात भी झेलना पड़ रहा है।हालांकि इस प्रखंड का यह पंचायत पहाड़ी, जंगलों से सटे रहने के साथ ही ऊपरवार इलाका आता है। जहां सिंचाई की समुचित साधन नहीं रहने के बाद भी अपने बलबूते किसान कमर कसकर खेती करने

का प्रयास करते रहे हैं। उन्होंने किसानों को सुचारू रूप से खेती के लिए कई नई तकनीक की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को आत्म निर्भरता पर बल मिल सकेगा। गोष्ठी में मुखिया नाजमा खातून, पंचायत समिति सदस्य हुस्न आरा, समाजसेवी प्रेमतोष कुमार सिंह, प्रखंड कृषि पदाधिकारी ज्योति रंजन, सहायक तकनिकी प्रबंधक परवीन जहां, जनसेवक अमरेश कुमार ठाकुर व जयप्रकाश राम सहित सैकड़ों किसान शामिल थे।

KASHYAP'S DENTAL CLINIC

Dr. Vaibhav Kashyap

Oral & Dental Surgeon, C.c. Endodontist & Implantologist Certified Orthodontist, MIDA

" Smiles & More"

छात्र-छात्राओं के लिए 50% की छूट

Facilities

- आरसीटी
- पायरिया का ईलाज
- टेढ़े-मेढ़े दाँतों का ईलाज
- स्माईल डिजाइन
- इनविजिवल क्लिप
- दंत रोपण
- फिक्स दाँत लगाना
- अत्याधुनिक मशीन और तकनीक के द्वारा ईलाज

CHAMBER

SKYLINE - 4006, 4th Floor, Kadru, Opp. Dr. Lal's Hospital, Ranchi

Contact No. : 9199533383, 7903835453

Time : 9 am to 2 pm & 4 pm to 8 pm

Sunday : 9 am to 2 pm

E-mail : vaibhav.kashyap2011@gmail.com

ब्रिफ न्यूज

कनाडा के हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ लिखे भारत-विरोधी नारे

नई दिल्ली। कनाडा में अल्बर्ट राज्य की राजधानी एडमोंटन में एक हिंदू मंदिर को निशाना बनाया गया। मंदिर में तोड़फोड़ की गई और भारत विरोधी नारे भी लिखे गए। यह घटना कनाडा में हिंदू मंदिरों पर हाल ही में हुए हमलों की श्रृंखला में शामिल हो गई है। कनाडा के सांसद चंद्र आर्य ने बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में की गई तोड़फोड़ पर चिंता जताई। उन्होंने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपने पोस्ट में लिखा, "पिछले कुछ सालों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों पर हिंदू मंदिरों में भारत विरोधी नारे के साथ तोड़फोड़ की जा रही है।"

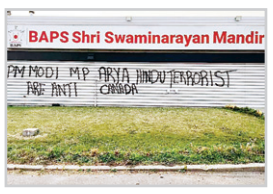

परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास से छह रूसी व 3 अन्य हिरासत में

चेन्नई। तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के पास घूम रहे छह रूसी नागरिकों और तीन भारतीयों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने आईएएनएस को बताया कि स्थानीय लोगों ने संयंत्र क्षेत्र के आसपास विदेशियों की मौजूदगी की सूचना दी। इसके बाद उन्हें सोमवार शाम को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने एक महिला समेत छह रूसियों के अलावा, तमिलनाडु के दो मूल निवासी और एक केरल के तिरुवनंतपुरम निवासी को भी हिरासत में लिया। तमिलनाडु पुलिस के सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों ने हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है।

इजरायली-अमेरिकी बंधकों के परिवारों से मिले नेतन्याहू

नई दिल्ली। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका की यात्रा पर हैं। वाशिंगटन में उन्होंने मंगलवार को उन परिवार वालों से मुलाकात की जिनके सदस्य हमास की हिरासत में गाजा में हैं। मुलाकात के बाद नेतन्याहू ने कहा, ₹मैं आवश्यक मानवीय उद्देश्य और बंधकों को वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं। मैं इजरायल के अस्तित्व को भी बचाए रखूंगा।" उन्होंने कहा, "हमास पर जीत जरूरी है। अगर हम इस लड़ाई में हार मान लेते हैं तो हम खतरे में पड़ जाएंगे, हमारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा।" इस मुलाकात में इजरायली प्रधानमंत्री के साथ वाशिंगटन जाने वाले बंधकों के परिवारों के कई सदस्य शामिल थे।

दोबारा नहीं होगी नीट यूजी परीक्षा : एससी

▶ साबित नहीं हुई बड़ी गड़बड़ी

एजेंसी

नई दिल्ली। नीट-यूजी पेपर लीक केस में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यह परीक्षा दोबारा नहीं कराई जा सकती क्योंकि बड़ी गड़बड़ी साबित नहीं हो सकी है। कोर्ट ने कहा कि फिर से परीक्षा कराना ठीक नहीं होगा और यह 24 लाख छात्रों के भविष्य का मामला है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत ने कहा कि इस मामले में व्यवस्थागत खामी की बात साबित नहीं होती है। इसलिए दोबारा से परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता।

अदालत ने कहा, 'फिर से एग्जाम कराने का आदेश देना 24 लाख बच्चों के लिए मुश्किल भरा होगा, जिन्होंने परीक्षा दी थी। इससे एडमिशन का शेड्यूल भी बाधित होगा। इसके अलावा मेडिकल एजुकेशन पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। यही नहीं इसका असर भविष्य में योग्य मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी के तौर पर भी दिख सकता है। इसके अलावा यह उन वंचित लोगों के लिए गंभीर चिंता का विषय होगा, जिन्हें सीटों पर आरक्षण मिला था।' इसके अलावा एक विवाद परीक्षा में आए एक प्रश्न पर भी था। इसके दो सही जवाब बताए जा रहे थे।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली को एक्सपर्ट कमेटी गठित करने को कहा था। उस कमेटी ने सवाल के दो जवाबों पर पैदा हुए भ्रम पर कहा था कि चौथा विकल्प ही सही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा कि एनटीए इस विकल्प के आधार पर रिजल्ट का फिर से मिलान कर लेगा। अदालत ने कहा कि एनटीए ने 1563 छात्रों की दोबारा परीक्षा भी कराई थी। उन लोगों को विकल्प मिला था कि ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे और यदि वे चाहें तो दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। यह भी विकल्प था कि जो बिना ग्रेस मार्क्स के ही मेरिट का हिस्सा बनना चाहते हैं, वे चाहें तो परीक्षा न भी दें।

कल से शुरू हो जाएगी नीट की काउंसिलिंग

कोर्ट के इस आदेश के बाद अब कल से नीट यूजी की काउंसिलिंग शुरू हो जाएगी। अदालत ने कहा कि पेपर लीक की बात हजारीबाग में ही साबित हो पाई है। इस मामले में व्यवस्थागत लीक की बात साबित नहीं हो सकी है। ऐसे में परीक्षा को रद्द करने की मांग सही नहीं है। बेंच ने कहा कि अब तक 155 छात्रों को ही लीक से फायदा होने की आशंका है। ऐसे में बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य को अधर में नहीं लटका सकते।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नीट पर जजमेंट देते हुए कहा-

- नीट यूजी पेपर लीक 2024 पर कोई विवाद नहीं है।
- जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद 10 जुलाई, 17 जुलाई और 21 जुलाई 2024 को सीबीआई ने 6 रिपोर्ट फाइल की।
- बताई गई जानकारी के अनुसार जांच चल रही है। सीबीआई का कहना है कि करीब 155 स्टूडेंट्स को हजारीबाग और पटना के एग्जाम सेंटर्स से पकड़ा गया जिन्हें इस फर्जीवाड़े का फायदा मिल रहा था।
- पूरा नीट एग्जाम कैंसिल करने से मना करते हुए कहा कि- ऐसा कोई सबूत नहीं है जो ये बताए कि पूरी परीक्षा की पवित्रता के साथ समझौता हुआ।
- इस समय ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो ये साबित करे कि नीट रिजल्ट में धांधली हुई या परीक्षा की शुचिता में कोई सिस्टमेटिक चूक हुई या व्यापक गड़बड़ी हुई।

आईएएस अकादमी के पास पूजा की कोई जानकारी नहीं

एजेंसी

मुंबई। महाराष्ट्र 2023 कैडर की ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) से जारी नोटिस के अंतिम दिन (मंगलवार को) मसूरी स्थित संस्थान के पास उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। एलबीएसएनएए ने 16 जुलाई को महाराष्ट्र सरकार को आदेश दिया था कि वह विवादास्पद ट्रेनी आईएएस को वाशिम कलेक्टरेट में 'सुपर न्यूमेरेरी असिस्टेंट कलेक्टर' के रूप में उनके क्षेत्रीय कार्यभार से तत्काल मुक्त करें और पूजा खेडकर को आगे की जरूरी कार्रवाई के लिए 23 जुलाई तक अकादमी में वापस रिपोर्ट करने का निर्देश दिया था। पूजा खेडकर (32) बीते शुक्रवार को वाशिम से पुणे पुलिस के पास अपना बयान दर्ज कराने के लिए निकली थीं, ताकि वह पुणे के कलेक्टर सुहास दिवसे के खिलाफ लगाए गए उत्पीड़न के आरोपों पर अपना बयान दर्ज करा सकें। कलेक्टर ने जुलाई के दूसरे सप्ताह में उनका पुणे कलेक्टरेट से वाशिम तबादला करने का आदेश दिया था। ट्रेनी आईएएस ने वाशिम कलेक्टरेट को रिपोर्ट किया था और 11 जुलाई को सहायक कलेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला था।

सीतारमण ने लगातार 7वीं बार पेश किया बजट, मोरारजी देसाई का तोड़ा रिकॉर्ड

एजेंसी

नई दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार सातवीं बार संसद में बजट पेश किया। ऐसा करने वाली वो देश की पहली वित्त मंत्री बन गईं है। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री मोरारजी देसाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मोरारजी देसाई ने साल 1959 से 1964 के बीच पांच पूर्ण बजट समेत एक अंतरिम बजट पेश किया था। पूर्व वित्त मंत्री ने कुल दस बजट भाषण दिए थे। मोरारजी देसाई के बाद पी. चिदंबरम ने 9 और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया था। निर्मला सीतारमण पहली वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने सात बार लगातार बजट पेश किया है। इससे पहले उन्होंने इसी साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया था। बजट पर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण के ही नाम पर है। उन्होंने 1 फरवरी, 2020 को अब तक सबसे लंबा बजट भाषण दिया था, जो दो घंटे और 40 मिनट तक चला था।

बजट पेश करने के लिए पहनी खास कलर की साड़ी

बजट भाषण के बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लुक को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। दरअसल हर बार की तरह वित्त मंत्री ने अपने सातवें बजट के लिए बेहद ही खास लुक चुना है। इस बार उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर की साड़ी पहनी है। साड़ी का बॉर्डर मैजेंटा और गोल्डन कलर से बना हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने ब्लाउज भी मैजेंटा कलर की पहनी है।

बजट से सहयोगियों को खुश करने की कोशिश : कांग्रेस

कांग्रेस के न्याय को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट

एजेंसी

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आम बजट को लेकर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। उन्होंने केंद्र के आम बजट को 'कुर्सी बचाओ बजट' बताया। इसके साथ ही उन्होंने सरकार के बजट को 'कॉपी पेस्ट' भी कहा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "कुर्सी बचाओ बजट। सहयोगियों को खुश करने की कोशिश की गई है। अन्य राज्यों की कीमत पर उनसे खोखले वादे किए गए। इसमें आम भारतीय को कोई राहत नहीं दी गई।" उन्होंने बजट को कांग्रेस के घोषणापत्र और पिछले बजट का कॉपी पेस्ट भी बताया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सकार के बजट पर निशाना साधते हुए लिखा, "कांग्रेस के न्याय के एजेंडे को ठीक तरह से कॉपी भी नहीं कर पाया मोदी सरकार का नकलची बजट। मोदी सरकार का बजट अपने गठबंधन के साथियों को ठगने के लिए आधी-अधूरी रेवड़ियां बांट रहा है, ताकि एनडीए बची रहे। ये 'देश की तरक्की' का बजट नहीं, मोदी सरकार बचाओ बजट है। 10 साल बाद उन युवाओं के लिए सीमित घोषणाएं हुईं हैं, जो सालाना दो करोड़ नौकरियों के जुमले को झेल रहे हैं। किसानों के लिए केवल सतही बातें हुईं हैं, डेढ़ गुना एमएसपी और आय दोगुना करना - सब चुनावी धोखेबाजी निकली।"

उन्होंने लिखा, "ग्रामीण वेतन को बढ़ाने का इस सरकार का कोई इरादा नहीं है। दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, माध्यम वर्ग और गांव-गरीब लोगों के लिए कोई भी क्रांतिकारी योजना नहीं है, जैसी कांग्रेस-यूपीए ने लागू की थी। 'गरीब' शब्द केवल स्वयं की ब्रांडिंग करने का जरिया बन गया है, ठोस कुछ भी नहीं है। महिलाओं के लिए इस बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जिससे उनकी आर्थिक क्षमता बढ़े और वो वर्कफोर्स में अधिक से अधिक शामिल हों। उल्टा महंगाई पर सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर वो पूंजीपति मित्रों में बांट रही है।"

चिदंबरम ने कहा, खुशी है कि वित्त मंत्री ने कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ा

पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि वित्त मंत्री ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए जारी कांग्रेस का घोषणापत्र पढ़ा है। पूर्व वित्त मंत्री ने एक्स पर लिखा, मुझे यह जानकर खुशी हुई कि माननीय वित्त मंत्री ने चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस का घोषणापत्र 2024 पढ़ा। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की भी खुशी है कि वित्त मंत्री ने रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन (ईएलआई) को अपना लिया है, जो कांग्रेस के घोषणापत्र के पेज नंबर 30 पर है।

बजट में मिले तोहफे से गदगद चंद्रबाबू नायडू, पीएम को दिया धन्यवाद

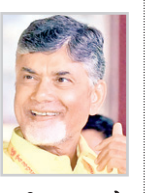

अप्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई घोषणाओं के लिए पीएम और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को धन्यवाद दिया। सीएम का कहना है कि इससे आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में काफी मदद मिलेगी। चंद्रबाबू ने एक्स पर लिखा, केंद्र से यह सहायता आंध्र प्रदेश के पुनर्निर्माण में बहुत मददगार साबित होगी। मैं इस प्रगतिशील और आत्मविश्वास बढ़ाने वाले बजट की प्रस्तुति के लिए आपको बधाई देता हूं।

सीएम धामी ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा बजट

केंद्रीय वित्त मंत्री मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट को लेकर लोकसभा स्पीकर और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की प्रतिक्रिया आई है। धामी ने कहा कि यह बजट विकसित भारत के संकल्प को पूरा करेगा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने एक्स पर लिखा, वित्त मंत्री मंगलवार की सुबह 11 बजे लोकसभा में बजट पेश करेंगी। बजट का सीधा प्रसारण संसद टीवी पर देखा जा सकता है।

एजुकेशन/करियर

एमबीए रूरल मैनेजमेंट में बना सकते हैं अपना करियर

रजनीश। एमबीए रूरल मैनेजमेंट में पढ़ाई आपको एग्रीकल्चर की फीडल के साथ साथ रूरल सेक्टर के प्रिंसिपल्स, प्लानिंग और उससे जुड़े आस्पेक्ट्स से रूबरू कराती है। यह दो साल का पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है जो स्टूडेंट्स को मुख्य रूप से रूरल और एग्रीकल्चर सेक्टर में आने वाली चीजों को प्लान, ऑर्गनाइज करना सिखाता है। इस कोर्स में आप एंट्रेंस एग्जाम के थरु एडमिशन ले सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम की बात करें तो उनमें सीएटी, मेट, जीएमएटी, जेट, जैसे टेस्ट्स शामिल होंगे। इन टेस्ट्स में आपको कम से कम 50% मार्क्स लाने आवश्यक होंगे।

एमबीए रूरल मैनेजमेंट

एमबीए रूरल मैनेजमेंट कोर्स आपको रूरल डेवलपमेंट और इस फील्ड में मिलने वाली कई बेहतरीन नौकरियों के विकल्पों के लिए तैयार करता है। मास्टर्स डिग्री होने के कारण आपके लिए इस फील्ड के दरवाजे और मिलने वाले ऑप्शंस की संख्या बढ़ जाती है।

एमबीए रूरल मैनेजमेंट का सिलेबस आपको फर्म और कंपनी में आने वाली मुश्किलों के लिए ज्ञान देता है जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए रेडी करता है। इस सिलेबस में रूरल इंडस्ट्री के एकाउंट्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, लीडरशिप स्किल्स और मार्केटिंग नॉलेज शामिल हैं।

यह आपको आपकी फील्ड में करियर ट्रांसफॉर्मेशन का मौका देता है। एक प्रोफेशनल कोर्स होने के साथ साथ एडवांस्ड नॉलेज की मौजूदगी इस कोर्स को आपका करियर बूस्टर बना सकती है।

इस कोर्स में प्रोजेक्ट्स, असाइनमेंट और केस स्टडीज आपको असली दुनिया में सही तरीका अपनाने और प्रैक्टिकल तरीके से सिचुएशन को हैंडल करने के लिए तैयार करती है।

करियर स्कोप

एमबीए रूरल मैनेजमेंट के बाद अगर आप आगे पढ़ाई का प्लान कर रहे हैं और बेहतर एजुकेशन चाहते हैं तो आप पीएचडी कोर्सेज की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। पीएचडी में आप अपनी पसंद की स्पेशलाइजेशन को चुन सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। पीएचडी के लिए आपके पास कम से कम 2 साल की पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है इसके आलावा अगर अब्रॉड से अपनी पीएचडी करने का प्लान कर रहे हैं तो इन टेस्ट्स में आपको कुछ बदलाव देखने को मिल सकते हैं। यह बदलाव आप अपनी चुनी गई यूनिवर्सिटी के हिसाब से भी देख पाएंगे।

विदेशों में भी होती है इसकी पढ़ाई

भारत में एमबीए रूरल मैनेजमेंट के लिए संस्थान

यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट एंड रिसर्च

जमनालाल बजाज इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

क्राइस्ट यूनिवर्सिटी

डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

आईआईटी दिल्ली

सिम्बायोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट

डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

सिम्बायोसिस इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज

भारतीदासन इंस्टिट्यूट ऑफ मैनेजमेंट

डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट

इंटरनेशनल स्कूल ऑफ बिजनेस एंड रिसर्च

मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी

कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी

डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट साइंस, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी

अमृता स्कूल ऑफ बिजनेस

फ्लेम यूनिवर्सिटी